राजस्थान विधान सभा

चौथी बैठक, बुधवार, १० मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में प्रातः ८ बज कर ३२ मिनट पर प्रारम्भ हुई.

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७०

झालावाड़ जिले में 'मान बड़ोद' योजना।

श्री जुझारसिंह—Will the Minister Incharge of Irrigation be pleased to state:—

(i) Whether the Government of Rajasthan propose to take up the work of "MAN BORDA" Scheme in Jhalawar District ?

(ii) If so, when ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)— (i) Yes.

(ii) Estimates are under preparation and it may take two months before work is started.

श्री राज हिम्मतसिंह—मान बड़ोद क्या कोई जगह है क्या ?

("मऊ बड़ोदा होगा" ऐसी सदन में आवाज़)

श्री राज हिम्मतसिंह—प्रश्न का उत्तर यह मिला है कि "मान बड़ौद" स्कीम को हाथ में लेने का विचार है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७१

पंचवर्षीय योजना में टौंक से उनियारा-अलीगढ़ होती हुई सड़क।

श्री सरदारसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.2

[श्री सरदारसिंह]

१. टोंक से उनियारा-अलीगढ़ होती हुई सड़क बनाने का कार्य क्या पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ?

२. अगर किया गया है तो इसका कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा की जावे ?

३. राष्ट्रीय सप्ताह में जो धांस से ककोड़ होती हुई उनियारा तक सड़क बनाने की योजना रखी गई थी उसमें किस कदर सफलता प्राप्त हुई है और वह सड़क कितने मील बन चुकी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—१. हां।

२. यदि आगामी वर्ष द्रव्य मिल गया तो कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

३. यह कार्य हाथ ही में नहीं लिया गया बताया और इसलिए सफलता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदारसिंह—क्या गजट के अन्दर टेन्डर नोटिफिकेशन हो चुका है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आप किसके लिए कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—सड़क के बारे में टेन्डर नोटिफिकेशन हो चुका है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने नोटिफिकेशन देखा है क्या ?

श्री सरदारसिंह—मैंने लोकवाणी में नोटिफिकेशन देखा है।

श्री टीकाराम पालीवाल—तो फिर पूछने की क्या बात है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२

कोटा औषधालय में यक्ष्मा के रोगियों के लिए व्यवस्था।

श्री जुझारसिंह— Will the Minister Incharge of Medical and Public Health Deptt. be pleased to state :—

(a) How many patients of 'Tuberculosis' were reported in the Hospital at Kotah last year and how were they provided.

(b) How has the Government utilised the amount of Rs. 25000/— sanctioned for T. B. patients in this area ?

Page No.3

[श्री जुझारसिंह]

(c) In view of the large number of cases of Tuberculosis in this area, does the Government intend to start a T. B. Sanatorium in near future ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री)—(अ) सन् १९५३ में क्षय रोग के ३०४ रोगियों की चिकित्सा कोटा अस्पताल में की गई।

(ब) इस वर्ष केवल १००००) रुपये की राशि व्यय के लिये निश्चित की गई जिसमें से ६५१६) रुपये जनवरी सन् १९५४ के अन्त तक खर्च किये जा चुके थे।

(स) निकट भविष्य में कोटा में टी. बी. क्लिनिक स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री जुझारसिंह—पूरी रकम कितने कामों में लाई जा चुकी है ?

श्री रामकरण जोशी—जितने मरीज आये उनका इलाज हो रहा है। जनवरी के अन्त का हिसाब हो चुका है। फरवरी और मार्च का बाकी है जो हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७३

डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में सरकारी एम्बुलेन्स गाड़ियों की व्यवस्था।

श्री सरदारसिंह—क्या चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

१. किन-किन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर सरकारी एम्बुलेन्स गाड़ियाँ सख्त बीमार तथा अर्जेन्ट केसेज़ को देहातों से अस्पताल में लाने के लिए रखी हुई हैं और किन-किन जगहों पर नहीं हैं ?

२, जहाँ पर नहीं है उन जगहों पर क्या सरकार का ऐसी गाड़ियाँ रखने का खयाल है ?

३. किस आधार से ये गाड़ियाँ रखी गई हैं और भविष्य में भी रखी जावेंगी ?

४. उन देहातों से जहाँ कि वर्षा ऋतु में अर्जेन्ट केसेज़ को हास्पिटल में लाना आवश्यक हो उनके लिए सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है ?

५. अगर व्यवस्था नहीं की गई है तो अब क्या विचार है ?

Page No.4

श्री रामकरणजोशी (स्वास्थ्यमन्त्री)—

१. निम्नलिखित हैडक्वार्टर्ज पर सरकारी एम्बुलेन्स गाड़ियाँ हैं :

१. अलवर २. सिरोही ३. भरतपुर ४. बूँदी ५. जयपुर

६. जोधपुर ७. बीकानेर ८. उदयपुर ९. कोटा १०. बाँसवाड़ा

२. इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

३. वितरणका अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है। इन स्थानों पर गाड़ियाँ राजस्थान-निर्माण के पूर्व से ही है।

४. जिन स्थानों पर एम्बुलेन्स हैं उनके आस-पास गाँवों के लिए भेज दी जाती हैं। इन स्थानों के लिए अलग से व्यवस्था करने का विचार करेगी ?

५. सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर में भी सरकार एम्बुलेन्स रखने का विचार करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—नई गाड़ियाँ जिले में रखने की ज़रूरत पर सरकार विचार करेगी।

श्री सरदारसिंह--सरकार कब तक सोच लेगी ?

श्री रामकरण जोशी--यह सब फाइनेन्सेज पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७४।

नाथद्वारा में मक्की की कुछ बोरियों का नीलाम किया जाना।

महाराज श्री शिवदान सिंह— क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या नाथद्वारा में हाल ही में ४७५ बोरियाँ मक्की की केवल ३७६ रुपये में नीलाम की गई थीं ?

(ख) यदि इतनी कम कीमत में नीलाम की गई तो उसका क्या कारण था ?

(ग) यदि सरकारी अफसरान की लापरवाही से इतनी कम कीमत में नीलाम करनी पड़ी तो उन पर क्या एक्शन लिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)— इस विषय में जाँच की जा रही है। बाद जाँच उचित कार्यवाही की जायगी। ऐसी दशा में दूसरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७५।

देवस्थान विभाग की स्थिति।

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Devasthan Department be pleased to state:--

Is it the intention of the Government to continue the Devasthan Dharampura Department as it is ?

श्री खेतसिंह— माननीय अध्यक्ष, यह तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, श्री जुझार सिंह।

प्रश्न संख्या ७६

पूर्व राजस्थान एकक में "भैंस बराड" लाग का होना तथा एकीकरण के पश्चात् उसका उठा दिया जाना

श्री जुझारसिंह—Will the Minister Incharge of Forest be pleased to state:--

(a) Whether a tax called "भैंस बराड" was levied in the whole of former Rajasthan unit at the time of its integration with greater Rajasthan and has it subsequently been stopped at certain places ?

(b) If so, why has it not been stopped as yet in certain Tehsils of former Kotah State having no better grazing facilities than in Bundi and Jhalawar Districts ?

(c) What is the income to the Government from this Tax ?

(d) What steps do the Government intend to take with regard to this tax in future ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)— (अ) ऐसा कोई टेक्स नहीं लिया जाता था। टेरिफ के अनुसार चराई ली जाती थी।

(ब), (स) और (ड) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

श्री जुझारसिंह— तो क्या कोई भैंसों की ग्रेजिंग का टेक्स नहीं लिया जाता था ?

श्री अमृतलाल यादव— जी हाँ, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया है।

श्री जुझारसिंह— कोटा और बूँदी में तो इस प्रकार का टेक्स नहीं लिया जाता है, फिर झालावाड़ में क्यों लिया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव— बूँदी और कोटा में भी चराई का टेक्स लिया जाता था।

श्री जुझारसिंह—बूँदी क्षेत्र से वसूली क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—इस सम्बन्ध में स्टे ऑर्डर्स हो गये थे और उसका फाइनल डिसिज़न होने तक वसूली स्थगित रखी गई है।

श्री जुझारसिंह—स्टे ऑर्डर्स को कितना अर्सा हो गया है और अब कितने अर्से तक रहेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि फोरेस्ट रूल बन गया है, रूल्स बन जावेंगे।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७।

मेजा के बन्ध का निर्माण-कार्य।

श्री अमरसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. मेजा के बन्ध के मुतअल्लिक कार्य कब प्रारम्भ हुआ ?

२. कितने वर्षों में उसके सम्पूर्ण होने का अनुमान है ?

३. कितने हज़ार बीघा ज़मीन की सिंचाई उससे होने का अनुमान है ?

४. कितने लाख रुपये लगने का अनुमान है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री) १. मेजा बन्ध का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

२. इस कार्य की मार्च सन् १९५६ तक समाप्त होने की आशा की जाती है।

३. इस बन्ध से करीब ३७,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होने का अनुमान किया जाता है।

५. अनुमानित लागत ५६,००,०००) रुपया होगी।

Page No.7

श्री तेजमल बापना— इसका काम कब से चालू होगया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी थोड़े दिनों से ही हुआ है।

श्री तेजमल बापना--क्या इसकी स्कीम पूरी हो चुकी है या अन्डर इन्वेस्टिगेशन है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—स्कीम सारी पूरी होने पर ही काम शुरू कराया जाता है।

श्री तेजमल बापना—क्या लाइन अभी अभी नहीं बदली गई है, जिसको करीब पाँच-सात दिन हुये होंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बन्ध की लाइन बदलने का तो सवाल ही नहीं होता।

श्री तेजमल बापना—पाल जो बन रही है वह मेजा गाँव में से होकर दो पहाड़ियों को मिलाने की दृष्टि से निकलती है। उसको एक माइल और बढ़ा दिया गया, क्या यह बात आपके ध्यान में लाई गई थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल--अगर पाल बदली गई है तो मैं उसकी जाँच कराऊँगा। शायद उसमें कोई टेक्निकल बात होगी या और कोई रुकावट पानी या लागत में होती होगी।

श्री तेजमल बापना—मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि पचास हज़ार रुपयों का मुनाफा होने की दृष्टि से दो पहाड़ियों को मिलाया गया। चूँकि बीच में ठाकुर साहब का मकान आजाता है, इस वजह से उसको बचाने के लिए आपके डिपार्टमेंट ने दूर लाइन निकाल दी।

श्री टीकाराम पालीवाल—इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं मालूम करूंगा।

श्री जवानसिंह—क्या इस प्रश्न के आने के बाद वहाँ कार्य शुरू किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी बात नहीं पहले से ही वहाँ काम शुरू है।

प्रश्न संख्या ७८

नसीराबाद से नीमच जानेवाली सड़क के राजस्थान से सम्बन्धित भाग का जीर्णोद्धार

(प्रश्न-कर्ता की अनुपस्थिति में श्री अध्यक्ष ने श्री जवानसिंह को प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की)

श्री अमरसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. नसीराबाद से नीमच जाने वाली सड़क के राजस्थान से सम्बन्धित भाग के जीर्णोद्धार करने की क्या कोई आज्ञा हुई है ?

[श्री अमरसिंह]

२. यदि हुई है, तो जून तक कितने रुपये व्यय हुए हैं और कितनी रकम मन्जूर हुई है ?

३. यह सड़क पक्की बनाई जायगी या फेयरवेदर ?

४. यदि फेयरवेदर है तो पुलों का जीर्णोद्धार भी किया जायगा या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) १. हाँ, इस कार्य को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

२. इसकी स्वीकृति जून के बाद आने के कारण जून तक कोई खर्चा नहीं हुआ। इस वर्ष में इस कार्य पर ५०,०००) रु. खर्च होने की आशा है।

३. यह सड़क पक्की बनेगी और पुलों का जीर्णोद्धार भी किया जायगा।

४. उपर्युक्त उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ७६

पादू बड़ी, मेडता तहसील में औषधालय खोलना

श्री भोपालसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पादू बड़ी, मेड़ता तहसील, में दूसरे नम्बर का कस्बा है ?

(ख) क्या यहाँ पर कोई औषधालय है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या यहाँ कोई औषधालय खोलने का सरकार विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)— (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) आवेदन-पत्र आने पर सरकार विचार करेगी।

प्रश्न संख्या ८०

डेगाना स्टेशन के समीप औषधालय का प्रबन्ध

श्री भोपालसिंह— क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.9

[श्री भोपालसिंह]

(क) क्या डेगाना स्टेशन के आस-पास ३०–३० मील में कोई शफाखाना नहीं है ?

(ख) क्या सरकार का विचार वहाँ शफाखाना खोलने का है ?

श्री रामकरण जोशी— (क) जी नहीं।

(ख) इस विषय में स्थानीय अधिकारियों से जाँच करवाई जा रही है।

प्रश्न संख्या ८१

धान व्यापार योजना के लिए नागरिक रसद विभाग के नाम ३१–३–५३ को ओवर ड्राफ्ट तथा गोदामों में धान का संग्रह

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Civil Supplies be pleased to answer:—

(a) What was the amount of overdraft outstanding against the Department for grain trading scheme etc. as on 31-1-1953 ?

(b) What was the value of stocks of grain in the godowns of the Department as on 31-3-53 ?

(c) What was the position in respect of the above two items as on 31-12-1953 ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)— (अ) सन् १९५२–५३ में इस विभाग को जितने रुपये की आवश्यकता होती थी वह खज़ाने से उपलब्ध किया जाता था। Overdraft के सम्बन्ध में यह कार्यालय अनभिज्ञ है।

(ब) सप्लाई विभाग में दिनांक ३१–३–५३ को अन्न संग्रहालयों में जो अन्न व उसका मूल्य १,५७,४२,६५४) रुपये आँका गया है।

(स) इसी प्रकार जो अन्न दिनांक ३१–१२–५३ को अन्न संग्रहालयों में था उसका मूल्य १,१४,२८,६५६ रुपये आँका गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जो रुपया विभाग द्वारा समय-समय पर लिया जाता है उसका टोटल मैं माँग रहा हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या— आपका प्रश्न ओवर ड्राफ्ट का था उसका मैंने जवाब दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने पूछा था "ओवरड्राफ्ट आउट स्टेन्डिंग अगेन्स्ट दी डिपार्टमेन्ट" बाकी ओवरड्राफ्ट का प्रश्न मैंने नहीं किया था। आपके डिपार्टमेन्ट में कितना रुपया आउट स्टेन्डिंग है, आपने कितनी रकम ली है, इन दोनों में अन्तर कितना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— इस विभाग के अकाउन्ट्स में जनरल अकाउन्ट्स भी शामिल थे। अगर आपका मतलब ओवरड्राफ्ट एडवान्सेज़ से है तो इसका सप्लाई विभाग में हिसाब पूरा नहीं हो पाया है यानी ३१-३-५३ तक हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हिसाब के तैयार होते ही आपको सूचना दे दी जायगी।

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या महकमे में इतना हिसाब नहीं रहता है कि कितना रुपया देना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— बहुत से हिसाब रखे जाते हैं। केवल धान खरीदने का ही हिसाब नहीं, वहाँ पर कई तरह से खर्च होते हैं। पूरा हिसाब आता है तभी मुकम्मिल समझा जाता है।

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह— माननीय मन्त्री का जवाब सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता। जो रकम आप ड्रॉ करते हैं उसकी टोटल तो मालूम होनी चाहिये। इसका अकाउन्ट डिपार्टमेंट में अवश्य होना चाहिये।

श्री पंड्या— इस तरह का प्रश्न पूछिये, अवश्य जवाब दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास— इसी तरह का प्रश्न था। जितना रुपया डिपार्टमेन्ट द्वारा ड्रॉ किया गया है उस साल के दौरान में और जितना वापिस जमा कराया गया है ट्रेजरी में इन दोनों की टोटल मिलाकर कितना अन्तर रहता है, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री भोगीलाल पंड्या— आप इस तरह का प्रश्न पूछिये, अवश्य जवाब दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास— प्रश्न तो इसी तरह का था कि "ओवर ड्राफ्ट आउट स्टेन्डिंग अगेन्स्ट दी डिपार्टमेंट" आप इसका अर्थ नहीं समझ सके इसमें मेरी गलती नहीं है।

श्री पंड्या— इसके अर्थ कई लगाये जा सकते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह तो अँग्रेजी ज़बान का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष।

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)—इसको तो आप भी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८२

वनस्थली विद्यापीठ में विभिन्न वर्गों की हरिजन लड़कियाँ

श्री लालूराम—क्या दलित वर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

वनस्थली विद्यापीठ में इस वर्ष हरिजनों की किन-किन वर्ग की कितनी-कितनी लड़कियाँ किस-किस दर्जे में हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री—उनकी संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—वे संख्या जानना चाहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—२५ है, वे जानते हैं। किन किन कक्षाओं में हैं, यदि आप आज्ञा दें तो पढ़कर सुना सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८३

उदयपुर निवासी नूर मोहम्मद रंगरेज को इवेक्यूई घोषित करना

श्री शिवदानसिंह—क्या निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

१. क्या यह सच है कि श्री नूर मोहम्मद, रंगरेज, निवासी उदयपुर को इवेक्यू करार दे दिया गया है ?

यदि यह सच है तो उसकी सम्पत्ति सरकार ने अपने अधिकार में अभी तक क्यों नहीं ली है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मंत्री)—श्री नूर मोहम्मद रंगरेज को एक आक्रांत सम्पत्ति के वास्ते निष्कासित घोषित किया गया था। उसके अपील करने पर एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ कस्टोडियन जनरल ने उसकी अपील को रद्द कर दिया है। उसके लिए रिमाण्ड मांगा गया है।

दूसरा प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न संख्या ८४

तहसील मेड़ता का हरसौर बांध एक उपजाऊ बांध

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हरसौर तहसील मेड़ता का बांध एक अच्छा उपजाऊ बांध हो गया है ?

(ख) इस बांध से कितना अनाज पैदा होने का सरकार अन्दाज लगाती है ?

(ग) सरकार की लागत रकम कितने सालों में वसूल हो जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—१. हां।

२. इस बांध से ३६० टन अनाज पैदा होने का अन्दाज है।

३. लागत रकम करीब १५ साल में वसूल हो जावेगी।

श्री भोपालसिंह—क्या इसकी नहरें पूरी नहीं कराई गई हैं ?

श्री पालीवाल—इसकी निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह विभाग नया है ?

श्री पालीवाल—विभाग तो नया नहीं, कार्य नया है।

श्री भोपालसिंह—क्या इस बांध को बड़ा बनाया जायगा ?

श्री पालीवाल—"और बड़े से" आपका क्या मतलब है यह मैं नहीं समझ पाया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८५

भैरून्दा गोल, तहसील मेड़ता के बालों को बांधना

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भैरून्दा गोल, तहसील मेड़ता के बालों को बांधने की सरकार जल्दी कृपा करेगी ?

(ख) क्या यह सच है, कि इस बाँध से दस-दस मील में नहर से पानी की पिलाई हो सकती है और इससे पड़ौस के कुओं में भी पानी खूब बढेगा ?

(ग) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि हरसौर के बांध की तरह यह बंधा भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) इन बालों को बांधने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह शंकास्पद है।

(ग) बांध बांधने की सूरत में यह सम्भव है।

(घ) यह बाले मेवड़ा, नथावड़ी, भथावडा वगैरह गांवों में ही फैलकर सेवज innunation पैदा करते हैं। बंध जाने से इसके विरुद्ध प्रभाव पड़ सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने बालों को बांधने का काम कब से शुरू किया है ?

Page No.13

श्री पालीवाल—जब से सरकार बनी, उससे पहले से।

श्री भूपालसिंह—क्या बांध के बांधने से काफी सिंचाई हो सकती है ?

श्री पालीवाल—फायदे के तो बहुत से काम हैं किन्तु सरकार इनको एक साथ नहीं कर सकती।

प्रश्न संख्या ८६

किसी पंचायत क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की शर्तें

श्री खेतसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) यदि कोई ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक औषधालय सरकार की ओर से खुलवाना चाहे तो किन शर्तों पर हमारी सरकार ऐसे औषधालय खोलने को तैयार है ?

(ख) कितनी जनसंख्या पर एक आयुर्वेदिक शाखा खोली जा सकती है ?

(ग) सन् १६५४-५५ में हमारी सरकार कितने और कहाँ-कहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालयों की शाखा खोलने की योजना अपने सम्मुख रख रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी—यदि कोई पंचायत अपने क्षेत्र में औषधालय सरकार की ओर से खुलवाना चाहती है तो उसे कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। उसे औषधालय के लिए उपयुक्त पक्के मकान की व्यवस्था करनी चाहिये तथा राज्यकर्मचारियों के रहने के लिए स्थान की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

यह निश्चित है कि जिस स्थान पर औषधालय खोला जावे उसकी स्थानीय जनसंख्या १५०० हो तथा आस पास के तीन-चार मील के ग्रामों की जनसंख्या कम से कम ५००० अवश्य होनी चाहिये।

सरकार द्वारा १६५३-५४ में ३५ नवीन औषधालय, ३२ आयुर्वेदिक व ३ यूनानी औषधालय खोले गये हैं तथा करीब ४० औषधालय आगामी वर्ष में भी, यानी सन् १६५४-५५ में खोले जाने की संभावना है। आगामी वर्ष में नवीन औषधालय खोले जाने वाले स्थानों पर अभी विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बजट की मन्जूरी होने के बाद ही ऐसा करना वान्छनीय है।

प्रश्न संख्या ८७

खाद्य-विभाग में कर्मचारियों को बर्खास्त तथा सस्पेन्ड करने सम्बन्धी

श्री धर्मपाल—क्या खाद्य मन्त्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) महकमा खाद्य में अब तक कितने कर्मचारी बर्खास्त किये गए और कितने सस्पेन्ड ? जो सस्पेन्ड किये गये उनमें से कितने बहाल किये गये ?

(ख) जो बहाल नहीं किए गए उनके प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नागरिक रसद विभाग में अब तक २१ कर्मचारी पदच्युत किये गये और १०३ मुअत्तिल किये गये।

४० की पुनः नियुक्ति की जा चुकी है। जिनकी पुनः नियुक्ति नहीं की गई उनके कागज़ातों पर अलग-अलग कार्यवाही चल रही है कुछ के कागज़ात न्यायालयों में भी चल रहे हैं।

श्री धर्मपाल—क्या यह सत्य है कि कई कर्मचारियों की तारीखें भी नहीं मिलीं।

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनके लिए आपने बताया था उन्हें तारीख दी गई है।

श्री धर्मपाल—क्या उन पर जल्दी फैसला होने की संभावना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—निकट भविष्य में फैसला हो जायगा।

श्री धर्मपाल—इन कर्मचारियों को सस्पेन्ड क्यों किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी लम्बी सूची है जो मैंने मेज पर रख दी है। उनमें से कई तो रिश्वतों के मामले में सस्पेन्ड किये गये, कई अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहे थे, इसलिये सस्पेन्ड किए गए।

श्री धर्मपाल—कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको चार्ज शीट नहीं दी गई और निकाल दिया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर कर्मचारियों को चार्ज शीट नहीं दी जाकर उन्हें निकाल दिया जाता तो वे खुद ही एतराज कर देते।

श्री जसवन्तसिंह—कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको बर्खास्त करने के बजाय इनाम दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर आपके ध्यान में ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो आप बताइये, उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री तेजमल बाफना—इनमें अफसर कितने और दूसरे कितने कर्मचारी हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसकी सूची टेबल पर रख दूंगा उसको पढ़कर आप देख सकते हैं।

प्रश्न संख्या ८८

कमिश्नरियों के हरिजन छात्रावासों में विद्यार्थियों की संख्या

श्री धर्मपाल—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) कमिश्नरियों के हरिजन छात्रावासों में कितने-कितने छात्रों को रखने की स्वीकृति है और जितनी स्वीकृति है क्या उसके मुताबिक सब में पूरी भर्ती हो गई है ?

[श्री धर्मपाल]

(ख) क्या यह सच है कि बीकानेर के हरिजन छात्रावास में केवल ३० छात्र ही भर्ती किए गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) बेकवर्ड क्लासेज़ वेलफेयर विभाग के अन्तर्गत डिविज़न हैड क्वार्टरों के प्रत्येक छात्रावास में ४० छात्र रखने की स्वीकृति है। अवशेष भाग का उत्तर नकारात्मक है।

(ख) नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को ज्वार की रोटी दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सब को गेहूँ की रोटी दी जाती है। जो सब का स्टेबल फूड है वह भी दिया जाता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—सरकार प्रत्येक छात्र पर कितना रुपया खर्च करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इन छात्रावासों में रहने के लिए जगह पर्याप्त है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एकाध जगह को छोड़ कर सब जगह पर्याप्त है। खासतौर से कोटा में जगह की कमी है, उसके लिए दूसरे मकान की तलाश की जा रही है।

श्री कंवरलाल जेलिया—इसकी कब तक उम्मीद की जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जुलाई तक इसका प्रबन्ध होने की आशा है नया सेशन शुरू होगा तब तक यह व्यवस्था हो जावेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—छात्रों को समय पर पुस्तकें नहीं दी जातीं, क्या यह भी सरकार के ध्यान में है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है। कहीं देर हुई हो। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि अगर ऐसी बातें सरकार के ध्यान में लाई जावें तो सरकार उन पर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—देरी जो करते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह

प्रश्न संख्या ८६

मरु-भू-भाग में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने की शासकीय योजना

श्री खेतसिंह—क्या मन्त्री वन-विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री खेतसिं

(क) राजस्थान के मरु-भू-भाग में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(ख) क्या सरकार मरु-भू-भाग के काश्तकारों को मुफ्त में पेड़ों के, गमले व बीज बोने को देने की योजना रखती है ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) सरकार रेगिस्तान को रोकने के लिए कितना रुपया व्यय कर चुकी है और इस वर्ष कितना व्यय करने के विषय में सोच रही है ?

(घ) सरकारी मन्त्रियों ने वायुयान द्वारा राजस्थान की सीमा पर जो बीज डाले थे उसका क्या नतीजा निकला ?

(ङ) क्या सरकार रेगिस्तान को रोकने के लिये कोई कमेटी मुकर्रर करने का भी सोच रही है जो सारे मामले की जाँच कर सरकार को रिपोर्ट पेश करे ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—(वन मन्त्री) (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित जोधपुर में डेजर्ट एफोरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन यह कार्य कर रहा है।

(ख), (ग) उत्तर (क) में आ गया है।

(घ) इनमें से कुछ बीज उगे और कुछ नष्ट हो गये।

(ङ) रिसर्च इन्स्टीट्यूट के कायम होने के बाद इस प्रकार की कमेटी को कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात भी सही है कि सरकार ऐसा ख्याल कर रही है कि रेगिस्तान को रोकने के लिए दरख्तों को काटना जरूरी है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री जसवन्तसिंह—तो क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर में जहाँ दरख्त पहिले से ही बहुत कम हैं, इतनी तादाद में दरख्तों के काटे जाने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले साल जरूर ऐसी एक बात आई थी और इसकी जाँच करने पर पता लगा कि कुछ इन्टरेस्टेड लोग, जिनमें कुछ शहरों के थे और कुछ व्यापारी लोग थे, इस कार्य में लगे हुए हैं और उन द्वारा इस प्रकार की कुछ घटनायें हुईं और हमने तुरन्त वहाँ पर स्पेशल स्टॉफ लगा कर इसको रोकने का प्रबन्ध कर दिया था और तब से ऐसी कोई शिकायत आज तक नहीं आई।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात सही है कि बीकानेर शहर में खुले आम कांग्रेस के एक नेता ने दरख्त काटने की दुकान लगा रखी है और वहाँ बहुमूल्य दरख्त बेचे जा रहे हैं और इसके लिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

Page No.17

श्री अमृतलाल यादव—दरख्त काटने की दुकान ?

श्री जसवन्तसिंह—जी नहीं, दरख्त बेचने की दुकान ! काटे हुए दरख्तों को बेचने की दुकान।

श्री अमृतलाल यादव—जो बात माननीय सदस्य ने बतायी है, वह बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कँवरलाल जेलिया—हवाई जहाज से बीज बोने की क्यों आवश्यकता हुई ?

श्री अमृतलाल यादव—अगर सरकार के ध्यान से और भी कोई दूसरा बड़ा वैज्ञानिक तरीका और वैज्ञानिक यन्त्र उपलब्ध होता और जनहित के लिए रेगिस्तान में बीज बोने की आवश्यकता होती, तो सरकार उसको भी करती और आगे भी कर सकती है।

श्री कँवरलाल जेलिया—तो क्या मैं यह समझूँ कि जब आप बीज डालते हैं तो हवाई जहाज से सफर भी करते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—उसमें हल के बजाय ऊपर से बीज बोया गया था इसलिये हमें भी साथ रहना पड़ा और उन बीज डालने वालों में मैं भी एक था।

(सदन में हँसी)

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सरकार यह आवश्यक समझती है ?

श्री तनसिंह—क्या असर हुआ उसका फिर ?

श्री अमृतलाल यादव—अभी इन्तजार करियेगा।

एक सदस्य—किस इलाके में बीज बोया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—बाड़मेर के बालोतरा इलाके में ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ये बीज उगे थे ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, कुछ उगे थे कुछ नष्ट हो गये।

श्री रामकिशोर व्यास—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बीज डाले कितने महिने हुए ?

श्री अमृतलाल यादव—करीब पाँच छः महिने हुए।

श्री तनसिंह—क्या वह बीज घुना हुआ था ?

श्री अमृतलाल यादव—और घुना हुआ था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितना बीज रेगिस्तान में डाला गया उसका कितना पर्सेन्टेज उगा और कितना नष्ट होगया और आज कितना सुरक्षित है ? पर्सेन्टेज के हिसाब से बताने की कृपा करें ।

श्री अमृतलाल यादव—उसका पर्सेन्टेज करीब करीब एक तिहाई लगभग आँका गया है और पूरा कुल मिलाकर इसलिए नहीं हो सका कि इसमें कुछ चूहे खा गये और कुछ पर जागीरदार साहबानों की कृपा हो गई और इसके अलावा और भी कुछ दूसरे कारण हो गये जिनकी वजह से पर्सेंटेज ठीक नहीं निकाल सकते ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दरख्त लगाये गए उन दरख्तों पर कितना खर्चा हुआ और प्रोपेगन्डा और मन्त्रियों आदि की तस्वीरें खींचने में कितना खर्चा हुआ ।

श्री अमृतलाल यादव—इसका नोटिस देंगे तो बता सकूँगा, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि ठीक ठीक आँकड़े बता सकूँ । पर, इतना डेफीनिटली बता सकता हूँ कि तस्वीरों और प्रोपेगन्डा पर इतना खर्च नहीं हुआ कि जितना बीज उगाने और दरख्त लगाने पर हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि एक तिहाई पर्सेन्टेज दरख्तों के सुरक्षित रहने का रहा, तो क्या सरकार ने इस बात की जाँच करवा ली है कि जो बीज डाला गया उसका एक तिहाई सुरक्षित रह गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं अन्दाज से अर्ज कर रहा हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जाँच के बाद का कोई उत्तर हो तो वह चाहता हूँ । अन्दाज तो हम भी लगा सकते हैं, कोई भी सदस्य लगा सकते हैं ।

श्री अमृतलाल यादव—जाँच के बाद इसका उत्तर दे सकूँगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Hon'ble Member has said that he has been successful. We want to know what is the percentage of the success. That is a very logical corrolary, otherwise how can one know if it has been successful ?

श्री अध्यक्ष—The reply is there.

श्री तनसिंह—क्या सरकार उन लोगों को जिनके खेतों में और जिनके यहाँ बीज डाले गये हैं, बेदखल करने का विचार कर रही है और क्या वे किसान जिनके खेतों में यह बीज गिरा है वे अपनी काश्त करने से महरूम रक्खे जावेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार किसी को बेदखल करने का इरादा नहीं रखती है । यह बात जरूर है कि जिनकी जमीन इसमें आ गई है उनको कम्पेन्सेशन देकर और दूसरी जमीन एवज में देकर राजी से यह काम किया जा रहा है ।

श्री तनसिंह—माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया अभी कि कुछ पर जागीरदार साहबानों की कृपा हो गई, तो वह क्या कृपा थी ?

श्री अमृतलाल यादव—वह कृपा यह थी कि जो दरख्त उनकी जमीनों में उगे उन्होंने समझा कि हमारा खेत सरकार ले लेगी, इसलिए उन्होंने उन दरख्तों को उखड़वा दिया, नष्ट कर दिया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सवा तीन करोड़ रुपया सरकार अपनी जिस पुलिस पर खर्च करती है, क्या वह पुलिस जागीरदारों के खिलाफ फिर इसके लिए कुछ नहीं कर सकी ?

श्री अमृतलाल यादव—खिलाफ का सवाल नहीं उठता है । उनकी जमीनों का सवाल था और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री खेतसिंह—मैंने एक भी सप्लीमेन्टरी प्रश्न नहीं पूछा है, इसलिये अब पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आपने क्यों नहीं पूछा ?

श्री खेतसिंह—मैं कोई २० दफा खड़ा हुआ, लेकिन मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—All right, do'nt waste time.

श्री खेतसिंह—तो क्या मैं यह समझूँ कि राजस्थान सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया और वह कोई दिलचस्पी नहीं लेती ?

श्री अमृतलाल यादव—नहीं, ऐसा नहीं है । राजस्थान सरकार इसमें विशेष दिलचस्पी लेती है ।

श्री खेतसिंह—तो क्या आप बतायेंगे कि राजस्थान सरकार ने रेगिस्तान को रोकने के लिये क्या योजना बनाई ?

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग सवाल है । इसका जवाब अलग रूप से दिया जा सकता है ।

श्री खेतसिंह—यह अलग सवाल नहीं है, यही तो मेरा सवाल था । आपने जो उत्तर अब तक दिया है, वह भारत सरकार की ओर से दिया है ।

श्री अमृतलाल यादव—भारत सरकार जो काम कर रही है वह अलग नहीं है । भारत सरकार करे या राजस्थान सरकार करे, फर्क नहीं है । जब काम भारत सरकार की ओर से हो रहा है और राजस्थान सरकार उसमें सहयोग दे रही है, तो राजस्थान सरकार को नई आवश्यकता डबल खर्चा करने की नहीं है ।

श्री खेतसिंह—राजस्थान सरकार ने कितना खर्चा अब तक किया है? कितना पैसा और खर्च करेगी, यह मेरा सवाल है?

श्री अमृतलाल यादव—राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ही मिल कर काम कर रही हैं। जो स्कीम है उसके अनुसार यदि भारत सरकार काम नहीं करती तो वही काम राजस्थान सरकार करती, लेकिन राजस्थान सरकार ने यह तै किया कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसे लिया जाय और भारत सरकार ने यह काम हाथ में ले लिया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—श्री खेतसिंह जी का सवाल सीधा-सा है। वे पूछते हैं कि कोई खर्चा इस कार्य के लिये राजस्थान सरकार ने किया या नहीं? अगर नहीं किया है, तो इसमें शर्म की बात नहीं है, साफ उत्तर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर चाहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव—राजस्थान सरकार ने थोड़ा बहुत खर्च किया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—पोजीशन यह है कि हमारे बहुत से काम ऐसे चल रहे हैं जिनमें भारत सरकार से सहायता हमको लेनी पड़ती है और हम ले रहे हैं। एक यही काम नहीं, बल्कि और भी कई काम हैं जिनमें हमें बहुत बड़ी सहायता भारत सरकार से मिल रही है। यदि भारत सरकार सहायता नहीं देती तो हमको खर्च करना पड़ता। लेकिन भारत सरकार ने पर्याप्त पैसा दिया है और इसलिये दिया है कि डेज़र्ट को रोकना खाली राजस्थान के हित में ही नहीं है, भारत के अन्य हिस्सों के हित में भी है। भारत सरकार ने इस काम के लिये रुपये एलोट किये हैं और हम इस काम में सहयोग दे रहे हैं। हम केवल नाम के लिये ही रुपये एलोट करें यह व्यवहारिक बात नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—श्री पालीवाल जी को एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सवाल सीधा था। यही पूछा था कि राजस्थान सरकार ने खर्च किया या नहीं?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह समझें कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें और आपके जवाब में फर्क है।

श्री टीकाराम पालीवाल—इसमें कोई अन्तर नहीं है। काम बराबर चल रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भारत सरकार राज्य सरकारकी सहायता कर रही है। क्या इसी प्रकार मन्त्री जी अपने साथी की सहायता कर रहे हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसमें कोई बेजा बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.21

प्रश्न संख्या ६०

बिजाथल के बाले को बाँधने की व्यवस्था

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या बिजाथल के बाले को बँधाने की सरकार कृपा करेगी ?

(ख) क्या यह सच है कि इस बाँध से बेरों में पानी काफी हो जावेगा ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इसकी लागत रकम को वहाँ के काश्तकार १० किश्तों में देने को तैयार हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस बाले को बँधाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है ?

(ख) हां, आसपास के कुओं में पानी बढ़ सकता है।

(ग) इसकी छानबीन की जा रही है।

श्री भोपालसिंह—तो क्या मैं यह समझूँ कि पंचवर्षीय योजना में इस पर पैसा खर्च नहीं किया जायगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे उत्तरों से ऐसा अनुमान लगाने की गुंजायश नहीं है।

प्रश्न संख्या ६१

पंचवर्षीय योजना में बिलाड़ा तहसील की पक्की सड़कें

श्री सन्तोषसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचवर्षीय योजना में बिलाड़ा तहसील की कौन-कौन-सी पक्की सड़कें मय कोलतार के कब तक बनकर तैयार हो जाँयगी ?

(ख) और इनके बनने का कार्य जल्दी से जल्दी कौन सी तारीख तक प्रारम्भ हो जायगा ?

(ग) जोधपुर से बिलाड़ा पक्की सड़क से पीपाड़ सिटी को मिलाने वाली एपरोच रोड़ पक्की (कोलतार की) कौन से माइल स्टोन से कटेगी ? क्या यह एपरोच रोड़ इसी वर्ष में बनकर तैयार हो जायगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) कोई मय कोलतार के सड़क बनाने की योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

(ग) कोलतार की ऐसी कोई सड़क नहीं बनेगी।

Page No.22

प्रश्न संख्या ६२

सन १९५३ में जन-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिये शासकीय व्यय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to answer :

(a) What was the total amount spent on pay of officers and for establishment including travelling and other allowances for the Public Health Department during 1952-53 ?

(b) What was the total amount spent for medicines including vaccines for the Public Health Department during 1952-53.

श्री रामकरण जोशी—(अ) कुल ७,१८३००) रुपये व्यय हुए।

(ब) औषधि एवं वैक्सीन (टीके) पर १९५२-५३ में कुल २,०४,५५५ रुपये व्यय हुये। इसके अतिरिक्त इस भाँति की औषधियाँ जैसे कि मैपाक्रीन, पैलुड्रीन इत्यादि का खर्च मेडिकल बजट से चार्ज होता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या आप इसको ठीक मानते हैं कि वेतन आदि में ७ लाख रुपये खर्च किये जाँय ?

श्री रामकरण जोशी—मेरे ख्याल से पब्लिक हैल्थ आदि को देख कर सवाल किया जाय तो यह वाजिब है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बात है कि भारत सरकार द्वारा ग्रान्ट, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिये १५ लाख रुपयों की दी गई।

श्री अध्यक्ष—It is not the question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The question is : "The total establishment expenditure is seven lacs and the actual expenditure on medicines is only 2 lacs."

श्री अध्यक्ष—It is, what it is.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He says that looking to public health it is all right.

श्री अध्यक्ष—It was only a question of opinion. He needs not say whether it is right or wrong.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All right. Is the Government aware that in the antimalaria work of the Public Health Department conducted by the Government of India the percentage of expenditure on establishment is only 15 ?

श्री रामकरण जोशी—बड़े स्केल पर करने पर......

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—मैं निवेदन करता हूँ कि बड़ी स्केल पर करने से पर्सेन्टेज कम हो सकती है। यह पर्सेन्टेज बेजा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान सरकार का पर्सेन्टेज कितना है ?

श्री रामकरण जोशी—यह पर्सेन्टेज आप निकाल लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह पर्सेन्टेज ३७५ नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ १५ पर्सेन्ट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या १५ पर्सेन्ट और ३७५ पर्सेन्ट में कोई अन्तर नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—यह अन्तर आप निकाल लीजिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३

शासकीय औषधालयों में रोगियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to answer :—

(a) What is the calorific value of the average diet given to patients in the State Hospitals ?

(b) What is the calorific value of the diet given to prisoners as per the specifications of the Jail Manual ?

(c) Is the Government aware that according to nutrition experts the diet given to the patients in the State Hospital is much below the required number of calories for a standard diet ?

(d) Will the Government take steps to remedy such an unseemly position ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) साधारणतया सरकारी अस्पतालों में दो प्रकार का भोजन दिया जाता है : साधारण भोजन (दाल, रोटी इत्यादि) और हल्का भोजन (खिचड़ी, चांवल, दूध इत्यादि) साधारण भोजन की कैलोरिफिक वैल्यु लगभग २३०० है। हल्के भोजन की कैलोरिफिक की

[श्री रामकरण जोशी]

संख्या उसके अनुपात पर निर्भर है और १००० से १६०० तक होती है। हल्के भोजन की मात्रा रोगी की पाचन-शक्ति के अनुसार दी जाती है।

(ब) कारावास में दिये जाने वाले भोजन की कैलोरिफिक वैल्यु इस प्रकार है : श्रमकार अपराधी (Labour Convict) २६२४ कैलोरिफिक और अश्रमकार अपराधी २५४५ कैलोरिफिक।

(स) जी नहीं। आहार विशेषज्ञों के अनुसार प्रामाणिक खुराक की कैलोरीज़ की संख्या एक साधारण स्वस्थ भारतीय के लिये २२०० होनी चाहिए।

(द) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि डॉक्टरों ने २५०० कैलोरिफिक डाइट हिन्दुस्तान के लिये वाजिब समझी है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने प्रश्न के (अ) भाग में जो २३०० कैलोरिफिक बताया उसे २२०० समझिये। इसे ठीक कर लीजिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं, उन डाक्टरों, ने जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें जो कैलोरिफिक डाइट की आवश्यकता बतलाई है, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या सरकार को इसके बारे में ज्ञान है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं लीग ऑफ नेशन्स की बात आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने सभी देशों के लिये २४०० कैलोरिफिक वैल्यु आवश्यक बताई है और अपने यहाँ २२०० है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माफ कीजियेगा, मैंने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—That is giving information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know whether the Government is aware of any such recommendation.

श्री रामकरण जोशी—मुझे अन्य किसी रिकमन्डेशन का पता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या सरकार के खयाल में हर प्रकार के रोगी के लिए जेल-डाइट से कम होने में कोई ऐतराज नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि रोगी की डाइट स्वस्थ आदमी से कम होती है। हमारे और आपके समझने से कुछ नहीं होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जेल में डाइट प्रेस्काइब्ड है उससे भी कम कैलोरीज की डाइट अस्पतालों में देना क्या सरकार गैरवाजिब नहीं समझती ? मेरे खयाल से वह कम से कम उनके बराबर तो जरूर करेगी।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६४.

कपड़े की मिलों से सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज की दर महाराजा किशनगढ़ मिल से शेष वसूली

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या खाद्य तथा नागरिक रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) कपड़े की मिल्स से सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज किस रेट से वसूल करती है ?

(ख) क्या कोई रकम महाराजा किशनगढ़ मिल्स से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के तहत काबिल वसूल है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि महाराजा किशनगढ़ मिल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के दो लाख रुपये (या लगभग इसके आसपास की रकम) सरकार ने माफ कर दिये हैं ? अगर हाँ, तो यह माफी किन हालतों में दी गई है ?

(घ) क्या दूसरे मिल्स को भी इस तरह की रियायत सरकार ने दी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) इस समय कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वसूल नहीं किया जाता है ।

(ख) हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) नहीं ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या कभी पहले किया जाता था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हाँ ।

श्री वेदपाल त्यागी—तो क्या उसके तहत कोई माफी दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किसी को कोई माफी नहीं दी गई है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो किशनगढ़ मिल का जो रुपया डाइरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाइज़ के यहाँ जमा था वह उनको माफ कर दिया गया है या उससे रुपया लिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई रुपया माफ नहीं किया गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कपड़े को खुले बाज़ार में बेचने के सिलसिले में उन्हें रियायत दी गई है, प्रोडक्शन का ६० पर्सेन्ट ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

कु ० श्री जसवन्तसिंह—जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वसूल किया जाता था वह अब नहीं किया जाता है, तो कब से वह नहीं किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब एक साल हुआ।

कु ० श्री जसवन्तसिंह—किसी खास वजह से माफ किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। यह तो भारत सरकार की नीति है। भारत सरकार ने सारे हिन्दुस्तान का माफ किया तो राजस्थान सरकार को भी करना पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—१९५१-१९५२ में जो ६० पर्सेन्ट तक कपड़ा खुले बाजार में बेचने की रियायत दी गई तो और मिलों को क्यों नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई रियायत ६० पर्सेन्ट तो क्या १ परसेन्ट भी नहीं दी गई है।

प्रश्न संख्या ६५

जोधपुर की उद्योग व कृषि प्रदर्शनी में करवाया गया पशुयुद्ध तथा क्षति इत्यादि सम्बन्धी

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी में जानवरों की लड़ाई में कौन कौन से व कितने कितने जानवर आपस की लड़ाई में मारे गये व घायल हुए अथवा अधिक घायल होने पर गोली से मारना पड़ा ? और कितने व कौन कौन से अधिकारी, कर्मचारी व अन्य आदमी किस किस वजह से मारे गये अथवा घायल हुए ?

(ख) इस विभाग ने इस प्रदर्शनी में किन वस्तुओं के प्रदर्शन के हेतु किस प्रयोजन से कितने बड़े बड़े स्टॉल कितने रुपयों में किराये पर लिये गये ?

(ग) इस विभाग ने इस प्रदर्शनी में कुल कितने रुपये किस प्रयोजन से खर्च किये ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) कोई जानवर लड़ाई या गोली से नहीं मारा गया। न हीं कोई कर्मचारी व अन्य व्यक्ति मारा गया सिवाये एक गधे के (हँसी) जिसकी रीछ ने गरदन पकड़ ली थी थोड़ा सा घायल हुआ।

(ख) एक स्टॉल ६० रुपये किराये पर वन उपज के प्रदर्शन हेतु शिकारखाने का पुराना सामान बेचने के लिए लिया गया।

(ग) वन विभाग का इस प्रदर्शनी में कुछ भी खर्चा नहीं हुआ।

(घ) जानवरों की लड़ाई तारीख १४ व २१ फरवरी को हुई। टिकट प्रदर्शनी द्वारा लगाये गये व आमदनी भी उन्हीं को हुई।

[श्री अमृतलाल यादव]

(ड) जानवरों की लड़ाई की आमदनी में से सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि इस सम्बन्ध में सारा व्यय प्रदर्शनी का था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या सरकार यह बतलायेगी कि वह गधा कहाँ से लाया गया था ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—गुनहगार गधे को क्या सजा दी गई ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस दिन क्या कोई मन्त्री महोदय उद्घाटन करने नहीं गये थे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९६

श्री अध्यक्ष—श्री सन्तोषसिंह कछवाहा।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

चौड़ा से पीपाड़ सिटी, पीपाड़ सिटी से मेड़ता सिटी तथा पीपाड़ से भोपालगढ़ आगे गोठन तक पक्की सड़कों का निर्माण

श्री संतोषसिंह कछवाह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार की निम्नलिखित रास्तों पर इस वर्ष पक्की सड़कें बनाने की कोई योजना है ; अगर है तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(अ) (चौड़ा से पीपाड़ सिटी तक) चौड़ा, बेवड़, जाटियावास बुचकेला बांकलिया रीयां, जवासिया होती हुई पीपाड़ सिटी तक।

(ब) (पीपाड़ सिटी से मेड़ता सिटी) पीपाड़ सिटी, नानण, जालीवाड़ा खुर्द, जालीवाड़ा कलां, कोसाण, सीयारा, चौकड़ी, खवासपुरा, पुलु, बिटण, गठिया होती हुई मेड़ता सिटी तक।

(स) (पीपाड़ सिटी से भोपालगढ़ आगे गोठन तक) पीपाड़ सिटी, पीपाड़ रोड अटरिया कलां, कुड होती हुई भोपालगढ़ ..... आगे गोठन स्टेशन तक।

प्रश्न संख्या ९७

जोधपुर, बिलाड़ा, जैतारण तथा बर तक की पक्की सड़क का निर्माण कार्य।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर से बर वाया पाली, सोजत और जोधपुर से बर वाया बिलाड़ा, जैतारण कितने-कितने माइल्स हैं ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(ख) इसमें जोधपुर से जयपुर व अजमेर मोटर के रास्ते से होकर आने-जाने के वास्ते शॉर्टकट वाया पाली-सोजत की तरफ से है या वाया बिलाड़ा—जैतारण की तरफ से? कितने माइल्स का फर्क है?

(ग) सरकार जोधपुर बिलाड़ा, जैतारण और बर तक की पक्की सड़क जल्दी से कोलटार कब तक बनवा देगी?

श्री टीकाराम पालीवाल—(निर्माण मन्त्री) (क) जोधपुर से बर वाया पाली व सोजत ६८ मील है और जोधपुर से बर वाया बिलाड़ा और जैतारण ८० मील है।

(ख) जोधपुर से जयपुर व अजमेर मोटर के रास्ते से होकर आने-जाने वालों के लिए शॉर्टकट वाया बिलाड़ा, जैतारण की तरफ से है और १६ मील का अन्तर है।

(ग) जोधपुर, बिलाड़ा, जैतारण और बर तक की पक्की सड़क याने मेटल रोड बनाने का काम पंचवर्षीय योजना में रखा है और काम चालू कर दिया है। इस पर डामर डालने का कार्य अभी किसी योजना में नहीं आ सका है और इस कारण इसके लिये कोई अवधि अभी नहीं दी जा सकती।

प्रश्न संख्या ६८

देवगढ़ में नेहरू की बीमारी के कारण रोगियों के लिये सींचवा-जल दिलाना व बावड़ियें बन्द करना।

श्री संग्रामसिंह (वि० स० १३४)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) देवगढ़ में नेहरू की बिमारी प्रतिवर्ष हो जाने के कारण क्या सरकार बावडियों को बन्द कराकर सींचवा पानी निकालने का प्रबन्ध करेगी?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री)—देवगढ़ में नेहरू की बीमारी की रोक-थाम के लिये बराबर समय समय पर बावड़ियों को डिसइन्फेक्ट (disinfect) किया जाता है। बावड़ियों को बंद करने एवं उन पर कोट बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री धर्मपाल पंवार—यह नेहरू की बीमारी कहाँ-कहाँ होती है राजस्थान में?

श्री रामकरण जोशी—यह जानकारी के लिए अलग सवाल होना चाहिए।

प्रश्न संख्या ६६

गणेश्वर (तहसील तोरावाटी) के तीर्थ स्थान में सदावर्त

श्री मुक्तिलाल मोदी— क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) गणेश्वर (तहसील तोरावाटी) के तीर्थ स्थान में क्या जयपुर राज्य की ओर से सदावर्त चालू था ?

(ख) राजस्थान के धर्मार्थ डिपार्टमेंट ने भी इसे चालू रक्खा या नहीं ?

(ग) यदि चालू रखा तो राजस्थान बनने से आज तक कितनी रकम कब कब दी गई ?

(घ) यदि रकम नहीं दी गई तो उसके क्या कारण हैं ?

(ङ) यदि राजस्थान बनने के बाद इस तीर्थ स्थान का सदावर्त किया गया है तो किस कारण से ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मन्त्री)— (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग)

समय	तारीख चुकारा	रकम जो दी गई रु.	आ.	पा
१६-४-४८ से २८-२-४६	१६-५-४६	१८४	१	३
१-३-४६ से ३१-८-४६	१६-६-४६	१८१	१	३
१-६-४६ से २८-२-५०	१५-४-५०	१८४	१	३
१-३-५० से ३१-८-५०	२६-२-५१	१८४	१	३
		७३६	५	०

(घ) ता. १-६-५० ई० से रकम देने के लिए एकाउन्टेन्ट जनरल, राजस्थान, से पत्र-व्यवहार हो रहा है, जहां से रकम चुकाने में एतराज पैदा हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस तरह धर्मार्थ में औरों को सदावर्त दी जाती है तो इसको क्यों नहीं दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— उनसे कुछ जानकारी चाही थी और वह उनके द्वारा नहीं दी गई, इसलिए नहीं दी गई है।

श्री जवानसिंह— एकाउन्टेन्ट जनरल का क्या ऐतराज था ?

श्री पंड्या—उनको जब उनकी मुआफी सेंक्शन हुई थी तो उसकी एक प्रतिलिपि दी जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अब अगर जानकारी दी जायगी, तो क्या इस बारे में चालू करदी जायगी ?

श्री पंड्या— उस वक्त तक की वह दे दी जायगी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास— वह फैसले की प्रतिलिपि किसके पास रहती है ?

श्री पंड्या— उनसे प्रमाण माँगा गया था तो उनके पास था नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मुआफी देने के फैसले की असली प्रतिलिपि किसके पास है ?

श्री पंड्या— एक प्रतिलिपि सरकार के पास है। उनसे पूछा गया था लेकिन उनसे प्रमाण नहीं दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास— सरकार को प्रतिलिपि अपने पास से एकाउन्टेन्ट जनरल को भेजने में क्या एतराज है ?

श्री पंड्या— इनसे एक फार्म पर नक्शा भी माँगा था लेकिन वह नहीं भेज सके हैं। अब उनसे यह कहा गया है कि फार्म टी. आर. में अपनी माँगे भरवाकर भेजें तो उनको रुपया दिया जायगा। ज्योंही वह बिल पेश कर देंगे, वह रुपया मिल जायगा।

प्रश्न संख्या १००

राजस्थान वन विभाग के कर्मचारियों का एकीकरण

श्री जवानसिंह—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान वन विभाग के कर्मचारियों का एकीकरण अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है ?

(ख) यह एकीकरण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव (वनमन्त्री)— वन विभाग के सबोर्डिनेट सर्विस के अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों का एकीकरण हो चुका है। सबोर्डिनेट सर्विस का अस्थायी एकीकरण तो

[श्री अमृतलाल यादव]

कर दिया गया है और पूर्ण एकीकरण करने के लिए इकोनामी कमेटी की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और इस विषय में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायगा।

श्री जवानसिंह— कब से विचाराधीन है ?

श्री यादव— पिछले दो महिनों से।

एक सदस्य— यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री यादव— अब तो वह कार्य-रूप में परिणत शीघ्र हो जायगा ?

श्री जवान सिंह— "शीघ्र" कब तक हो जायगा पूरा ?

श्री यादव— "शीघ्र" का मतलब आप समझते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह विचार कब से शुरू किया गया है ?

श्री जवानसिंह— क्या बिहार से सफेद हाथी के आने के बाद भी यह रिकमन्डेशन विचाराधीन है ?

श्री यादव— अब कोई सफेद हाथी नहीं है।

श्री कँवरलाल जेलिया— क्या कुछ आदमियों को......

श्री अध्यक्ष— ऑर्डर, ऑर्डर। नेक्स्ट, श्री सज्जनसिंह।

प्रश्न संख्या १०१

डबलाना ग्राम (तहसील हिण्डोली) के समीप गोगलिया नले का निर्माण-कार्य

श्री सज्जनसिंह—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:—

(a) Whether a bridge promised to be constructed on the Goglia Nulla near Dablana village, Tehsil Hindoli, District Bundi, by the Minister in reply to my question in the last year's Budget Session, has been completed ?

(b) If not, will he kindly now take the matter in hand this year before the rains ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(a) Not yet.

(b) The matter is in hand and every effort will be taken to complete the work before the coming rainy season.

प्रश्न संख्या १०२

भजनेरी ग्राम तहसील नैनवाँ, के समीप के नले पर रपट या पुल का निर्माण कार्य

श्री सज्जनसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state:—

Whether the Government has considered the advisability of constructing a 'Rapat' or a small bridge over the Nulla near Bhajneri village on the road between Bansi and Dehi of Nainwan Tehsil, District Bundi, in view of its constant danger to the travelling of public by Buses which was brought to the notice of the Minister in the last Budget Session ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(a) Yes, Government do realise the advisability of constructing a 'Rapat' or a small bridge over the nulla near Bhajneri village on the road between Bansi and Dehi of Nainwan Tehsil, District Bundi. The work will be taken in hand as soon as funds are available for the purpose.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जाय कि सरकार को फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो यह काम कभी किया ही नहीं जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह तो साफ ही है कि जब फंड्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो कोई भी काम कैसे किया जा सकेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस काम के लिये फंड्स अवलेबल नहीं होते ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पिछले साल का बजट हाउस के सामने आ चुका है और इस साल का भी हाउस के सामने आयेगा।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०३

देवगढ़ डिस्पेन्सरी में इस वर्ष के बजट से औषधियाँ

श्री संग्रामसिंह (डि. सं. १३४)—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

देवगढ़ डिसपेन्सरी में इस वर्ष के बजट में से कितने रुपये की दवाइयें भेजी गईं और आयन्दा कितनी भेजी जावेंगी ?

Page No.33

श्री रामकरण जोशी—देवगढ़ डिस्पेन्सरी में दवा खरीद के मद में १५००) रुपए दिए जाते हैं। इस साल अब तक २,०३७) रुपयों की दवा जा चुकी है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और भी दवाई भेजी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०४

गालवा नदी का बाँध बँधवाना

श्री सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या गालवा नदी का बाँध बँधवाने की कोई योजना है ?

(ख) अगर है तो क्या सर्वे वगैरह हो चुकी है व बाँध किस जगह बाँधा जावेगा और क्या लागत होगी ?

(ग) इसमें कितनी सिंचाई हो सकेगी और किस किस हिस्से में ?

(घ) यह बाँध कब तक बँधने की सम्भावना है।

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) हाँ।

(ख) सर्वे हो रही है। खयाल है कि यह बाँध उणियारा के उत्तर में बाँधा जायगा। तकमीना अब बनेगा। करीब २० लाख रुपया व्यय होगा।

(ग) इससे १२ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और यह सिंचाई उणियारा से चौथ का बरवाड़ा के बीच के हिस्से में होगी।

(घ) इसके बनने में दो-तीन वर्ष का समय लगेगा। महीने दो महीने में तकमीना बन जायगा और मंजूरी होने पर वहां पर काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०५

बनेड़ा मुन्सफी का काम, कोई मुन्सिफ न होने के कारण सन् १९५२ से बन्द होने सम्बन्धी

श्री तेजमल बापना—क्या न्याय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बनेड़ा मुन्सिफी का काम वहां कोई मुन्सिफ न होने के कारण मई १९५२ से बन्द है ?

[श्री तेजमल बापना]

(ख) क्या यह भी सही है कि मांडलगढ़ मुन्सिफी भी सितम्बर १९५२ से उपरोक्त कारण से बन्द है ?

(ग) क्या यह दोनों कचहरियां अभी तक चालू हैं या दोनों को समाप्त (abolish) कर एक नई मुन्सफी मुकाम भीलवाड़ा में कायम कर दी गई है ? यदि हाँ, तो कब से कायम की गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस मुन्सिफी के लिये भी अब तक कोई मुन्सिफ नहीं भेजा गया है और काम दिनों दिन बढ़ रहा है ?

(ङ) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि डेढ़ पोने दो साल तक भी किसी न्यायालय के अफसर की नियुक्ति नहीं होने से जनसाधारण को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है ?

(च) क्या अब भी सरकार शीघ्रातिशीघ्र किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी ? हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (न्याय मन्त्री)—(क) बनेड़ा में मुन्सिफ के लिये पर्याप्त काम नहीं होने के कारण वहां पर तारीख ४-९-५२ से मुन्सफी का न्यायालय स्थगित रखा गया। इस न्यायालय द्वारा किये जाने वाले कार्य का भी भीलवाड़ा के मुन्सिफ के न्यायालय में स्थानान्तरित करने को आदेश दे दिया था। भीलवाड़ा के मुन्सिफ का न्यायालय हटने के बाद बनेड़ा के मुन्सिफ के मुकद्दमे भी भीलवाड़ा के सिविल जज द्वारा निर्णीत किये जा रहे हैं।

(ख) इसी प्रकार के कारण से मांडलगढ़ में भी मार्च १९५२ से मुन्सिफ न्यायालय स्थगित कर दिया गया और इस न्यायालय के मुकद्दमों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का प्रबन्ध किया गया।

(ग) आरम्भ में सरकार ने बनेड़ा और मांडलगढ़ के दो मुन्सिफ न्यायालयों को तोड़ देने और उनके बदले भीलवाड़ा में एक नया मुन्सिफ का न्यायालय स्थापित करने का निश्चय किया था, परन्तु यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि भीलवाड़ा में मुन्सिफ के पद पर नियुक्त करने के लिये कोई अफसर उपलब्ध नहीं था। अब सरकार बनेड़ा और मांडलगढ़ के मुन्सिफ के न्यायालय को समाप्त करके उनके अधिकार क्षेत्र को भीलवाड़ा की सिविल जजी को हस्तान्तरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इसका कारण यह है कि बनेड़ा और मांडलगढ़ के मुन्सिफ न्यायालयों में दायर किये जाने वाले मुकद्दमे इतने थोड़े होते हैं कि उनके लिये एक नया न्यायालय स्थापित करना उपयुक्त नहीं होगा। उच्च न्यायालय का कहना है कि बनेड़ा और मांडलगढ़ के मुन्सिफ न्यायालयों में दायर किये जाने वाले मुकद्दमों का फैसला भीलवाड़ा की सिविल जजी द्वारा बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। क्योंकि बनेड़ा और मांडलगढ़ के मुन्सिफ के न्यायालयों को समाप्त करने की अब तक कोई औपचारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है इसलिये वे अब भी विद्यमान समझे जायेंगे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(घ) भीलवाड़े के सिविल जज मुकद्दमों को निपटाते रहे हैं। वहाँ पर कोई काम इकट्ठा नहीं है। बनेड़ा और मांडलगढ़, दोनों के मुंसिफ न्यायालय में पेश किये जाने वाले मूल दावों की कुल संख्या १९५३ के वर्ष में कुल १०० थी।

(ङ) प्रश्न 'ग' और 'घ' के उत्तरों को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता।

श्री **तेजमल बापना**—क्या यह सच है कि उन मुकद्दमों को जो बनेड़ा और मांडलगढ़ मुन्सिफ कोर्ट की समाअत के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एफिडेविट पेश करके मुन्तकिल करवाया जाता है ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—हो सकता है। यह मुन्तकिल कराने का अधिकार तो पार्टी को रहता है।

श्री **तेजमल बापना**—मुन्तकिल करवाने का कारण यह था कि वहाँ मुन्सिफ डेढ़ साल तक नहीं थे, तो उनको ५) रुपये विशेष देकर असुविधा के कारण मुन्तकिल करवाना पड़ा ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—पार्टी एफिडेविट पेश करके मुकद्दमों को मुन्तकिल करवाये तो उनके अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में कोई भी अलग-अलग कारणों का मालूम करना मुश्किल है।

श्री **व्रजसुन्दर शर्मा**—तब तक अदालतों का स्टॉफ क्या करता रहा ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—काम करता रहा।

श्री **जवानसिंह**—एक मुन्सिफी के लिये कितना काम पर्याप्त माना गया है ?

श्री **व्रजसुन्दर शर्मा**—वहाँ काम ही नहीं रहा है।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—मैं जानकारी हासिल करूँगा।

श्री **जवानसिंह**—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि एक मुन्सिफ के लिए कितना काम पर्याप्त माना गया है ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—यह सब काम की नेचर पर है। कोई मुकद्दमा ऐसा होता है कि उसमें बहुत समय लग जाता है और कोई मुकद्दमा ऐसा होता है कि वह जल्दी ही तय हो जाता है।

श्री **जवानसिंह**—कितने मुकद्दमे दायर होने चाहिये, कितने डिसाइड होने चाहिये ?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर। श्री तेज मल बापना।

प्रश्न संख्या १०६

भीलवाड़ा नगर के गांधी-अस्पताल में रोगियों के लिये अधिक डाक्टरों की व्यवस्था

श्री तेजमल बापना—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भीलवाड़ा नगर में नये गांधी हॉस्पिटल का उद्घाटन कब हुआ ?

(ख) नये अस्पताल के उद्घाटन के पिछले ६ माह में मरीज़ों की औसत संख्या क्या थी और उद्घाटन के बाद अब क्या औसत संख्या है?

(ग) क्या यह सही है कि मरीजों की संख्या उद्घाटन के बाद तीन गुनी बढ़ गई जब कि डाक्टर एक भी नहीं बढ़ाया गया है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि दो डाक्टरों की जगह मंजूर शुदा होते हुए भी अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है ?

(ङ) क्या सरकार अब भी मंजूर शुदा दो डाक्टरों की नियुक्ति करने को तैयार है ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—(क) ५ नवम्बर, सन् १९५३ ।

(ख) उद्घाटन के ६ माह पूर्व के मरीजों की औसत संख्या प्रतिदिन ३८९.५५ थी और अब ३१८.०६ प्रति दिन है ।

(ग) उद्घाटन के बाद मरीजों की औसत संख्या बढ़ी नहीं है ।

(घ) मौजूदा डॉक्टरों के अलावा दो और डॉक्टरों की पूर्ती के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन को लिखा हुआ है ।

(ङ) जी हाँ । ज्योंही पब्लिक सर्विस कमिशन डॉक्टरों का चुनाव करके भेजेगी त्योंही वहाँ डाक्टर नियुक्त कर दिये जावेंगे ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेडिकल विभाग के कर्मचारियों का रीऑर्गेनाइजेशन विभाग द्वारा कितनी बार हो चुका है ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह आप अलग प्रश्न पूछें ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—जो डॉक्टरों की नियुक्ति में देरी हो रही है उसका कारण पब्लिक सर्विस कमीशन है या मेडिकल विभाग ?

श्री रामकरण जोशी—इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसका उत्तर मैंने दे दिया है कि अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन से तय नहीं हुआ है इसलिए नियुक्ति नहीं की गई है, होते ही नियुक्ति कर दी जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मेडिकल विभाग की ओर से चुनाव को रोका नहीं गया ?

श्री रामकरण जोशी—चुनाव के लिये आप अलग प्रश्न पूछिये। इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—देरी से इसका तालुक है। डॉक्टरों के चुनाव में देरी हुई। इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री रामकरण जोशी—वैसे तो राजस्थान में होने वाली देरी का ताल्लुक राजस्थान सरकार से है पर जो इस सवाल में बात है उसके उत्तर में मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों के नाम पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर नहीं आये हैं, इसलिये अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या १०७

किशनगढ़ से रूपनगर की सड़क पर व्यय

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ से रूपनगर तक सड़क कब बनी और उस पर कितना व्यय हुआ ?

(ख) उक्त सड़क का काम ठेके में कराया गया या अमानी में ?

(ग) उक्त सड़क की मौजूदा हालत कैसी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) (क) सड़क-निर्माण का काम अभी तक हो रहा है और इस पर निम्नलिखित धन लगा—

१९५०–५१	११६ रुपया
१९५१–५२	७६००१ रुपया
१९५२–५३	२२८१२४ रुपया
१९५३–५४	२५१७१ रुपया
कुल	३२९४१२ रुपया

(ख) इस सड़क के निर्माण का काम १९५१–५२ व १९५२–५३ में अकाल सहायता के अन्तर्गत अकाल ग्रस्त मजदूरों द्वारा इस विभाग ने करवाया। अब काम पूरा होने के लिये ठेका दिया गया है।

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) यह सड़क ६ मील से १५ मील तक निर्माण के अन्तर्गत है। मील १ से ५ तक का काम पूरा किया जा चुका है और अच्छी हालत में है।

श्री **चाँदमल मेहता**—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सड़क अब निर्माण के अन्तर्गत है वह सड़क पहले नहीं बनी थी?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—मेरी जानकारी में वह पहले नहीं बनी थी।

श्री **चाँदमल मेहता**—मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वह पहले बनी थी।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—इस जानकारी के लिये धन्यवाद।

प्रश्न संख्या १०८

किशनगढ़ से अराई तक सड़क बनाने का कार्य।

श्री **चाँदमल मेहता**—(डि० नं० ८७) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ से अराई तक सड़क बनाने का ठेका किसको कितने रुपये में दिया गया?

(ख) ठेका किन शर्तों पर दिया गया?

(ग) क्या काम ठेके की शर्तों के माफिक हो रहा है?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) (क) यह काम निम्नलिखित दिये गये—

जोन ए. मील १ से ५ तक श्री रवेलसिंह ठेकेदार को रुपये ८५८५० का काम दिया गया। जोन बी० मील ६ से १० तक श्री रवेलसिंह ठेकेदार को रुपये १,१२,५४६ का काम दिया गया। जोन सी० मील ११ से १५ तक मेसर्स जे. मोहन एन्ड कम्पनी ठेकेदार को रुपये १,१४,७०० का काम दिया गया।

(ख) राजस्थान सरकार के ठेके की शर्तें पी. डब्लू. डी. भवन व मार्ग के लिये मुद्रित आधार पर काम पूरा किया जाना है।

(ग) जी, हाँ।

श्री **चाँदमल मेहता**—क्या यह सड़क ठेके की शर्त के मुआफिक बनाई गई है? ठेके की शर्त के मुआफिक जितने चौड़े पत्थर आदि लगने चाहिये थे क्या वे लगे हैं?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—यह सारी जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितने पत्थर लगे।

Page No.39

श्री **चाँदमल मेहता**—मैंने यह पूछा है कि क्या ठेके की शर्त के मुआफिक काम हुआ है ? जितनी चौड़ी सड़क बननी चाहिये थी क्या वह बनी है ? मेरा मतलब यह था ।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—जी हाँ ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या यह सड़क इतनी चौड़ी है कि चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी भी साथ निकल सके ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—प्रश्नकर्त्ता की भी गाड़ी जा सकती है ।

श्री **चाँदमल मेहता**—क्या ठेकेदारों को रुपयों का पेमेन्ट किया जा चुका है ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०६

सवाई मानसिंह औषधालय में आउट डोर रोगियों के लिये बड़े डाक्टरों की व्यवस्था

श्री **नारायण चतुर्वेदी** (डि० न० १०६)—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई मानसिंह अस्पताल के बड़े-बड़े डाक्टर आउट पेशेंट वार्ड में भी मरीजों को अटेण्ड करते हैं या नहीं ?

(ख) क्या यह सही है कि दूर-दूर से आये हुए मरीजों को, बड़े डॉक्टरों को दिखाये बिना, निराश होना पड़ता है ?

(ग) अगर ऐसा है तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि बड़े डॉक्टर मरीजों को रेगुलर आउट डोर में देखा करें ?

श्री **रामकरण जोशी**—(क) जी हाँ, करते हैं ।

(ख) केवल वे ही मरीज देखे जाते हैं जिन्हें जूनियर डॉक्टर सलाह के लिये पेश करें ।

(ग) बड़े डॉक्टर अपनी-अपनी बारी से आउट डोर देखते हैं और उन मरीजों को देखते हैं जिन्हें उनका इलाज आवश्यक है अथवा जिन्हें जूनियर डॉक्टर पेश करना जरूरी समझते हैं ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—श्री नारायण चतुर्वेदी का नाम १०६ में कैसे शामिल हुआ ?

श्री **अध्यक्ष**—Do you envy that ? (हँसी)

श्री **रामकरण जोशी**—पहले नम्बर १० पर कई नाम आ चुके हैं ? (हँसी)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है :

मेजर आपजी श्री रघुराज सिंह (वि. सं. १२१)	दिनांक ५.३.५४ से १२.३.५४
श्री दिलीपसिंह	दिनांक ५.३.५४ से २४.३.५४
राजा श्री मानसिंह	दिनांक १०.३.५४ से २१.३.५४

(आज्ञा प्रदान की गई)

कुं. श्री जसवन्त सिंह—मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो बोर्ड लगा हुआ था वह हट गया है और जो सदस्य इधर आए हैं वे क्या विरोधी पक्ष के हो गए हैं ?

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—Now we come to the Rajpramukh's Address. Before that however, I want to place certain facts before the House. Yesterday 4 hours and 8 minutes were allotted to the party other than the Congress Party for discussion and day before, out of 2 hours no, no hitherto 4 hours and 8 minutes have been allotted to other parties than the Congress Party and one hour and 40 minutes to the Congress party. Now we want to discuss today. So those members who may not have an opportunity to discuss on the Rajpramukh's Address will please take their opportunity when the Budget comes and I think the Hon'ble Members will co-operate with me in so adjusting so that we may finish the debate to-day.

श्री वेदपाल त्यागी—Was this allotment made by the Treasury Benches ?

श्री अध्यक्ष—No, I have narrated what happened.

श्री वेदपाल त्यागी—It means they did not like to speak.

श्री अध्यक्ष—Not that

श्री जसवन्तसिंह— माननीय अध्यक्ष, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न पर आपत्ति उठाना चाहता हूँ और वह यह है कि अभी जैसा आपने फरमाया कि कांग्रेस पार्टी और अदर देन, क्या इसका मतलब यह लिया जाय कि विरोधी पार्टी का जो रिकोग्निशन था, क्या वह हटा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष— मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूँ कि ट्रेजरी बैंच के अलावा यानी अदर देन ट्रेजरी बैंच से मेरा मतलब था, चाहे वे विरोधी दल के हों चाहे इन्डिपेन्डेन्ट हों, सब

[श्री अध्यक्ष]

शामिल हैं। इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपने डेज़िग्नेशन का कोई खतरा नहीं समझना चाहिए।

कं. श्री जसवन्तसिंह— खतरा हो या न हो, तो भी यह तो एक कॉंस्टिट्युशनल बात है। जब तक रिकोग्निशन समझा जाता है तब तक हमारा हक है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे।

श्री मोहब्बत सिंह— माननीय अध्यक्ष, आज सदन के समक्ष पिछले दो दिनों से श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद दिया जावे या नहीं, इस पर वाद विवाद हो रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें फरमाई हैं और मेरे लिए बहुत थोड़ा विषय है कुछ कहने के लिए। फिर भी मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में आबू के लिए एक शब्द भी नहीं है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन व दूसरे सदस्यों ने भाषण दिये, मगर उनके भाषण में कहीं भी आबू के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया है। सिवाय खेतसिंह जी के किसी भी सदस्य ने आबू के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला। हम नहीं समझ सकते कि इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में कोई गौर नहीं करेगी ? श्रीमन् राजप्रमुख के चार भाषण हुए। राजप्रमुख के पहले भाषण में भी आबू की समस्या को इगनोर (Ignore) किया गया। इसके बाद जब इस पर वाद-विवाद होने लगा तो माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया और इसके पश्चात् सदन ने एक मत से प्रस्ताव पास किया कि हमें केन्द्रीय सरकार से आबू के लिए मांग करनी चाहिए। उसके पश्चात् जब राजप्रमुख का दूसरा भाषण हुआ उसमें आबू पर कुछ प्रकाश डाला और उसके बाद तीसरे भाषण में भी कुछ प्रकाश डाला गया था। लेकिन इस समय श्रीमन् राजप्रमुख और हमारी सरकार आबू के विषय पर प्रकाश डालना कैसे भूल गई, यह हमारी समझ में नहीं आया। क्या यह सत्य है कि मुरारजी देसाई से हमारी सरकार ने समझौता कर लिया है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोई बात कर ली है ? वैसे तो समय समय पर हमारे चीफ मिनिस्टर प्रेस में स्टेटमेंट देते हैं और अपने आपको आबू की समस्या से चिन्तित बतलाते हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसके अन्दर हमारी सरकार हमेशा ठोस काम करने में असमर्थ रही है और अब सरकार की अपनाई हुई नीति के कारण आज हमें कुछ भी विश्वास नहीं रहा है कि क्या आबू राजस्थान को वापिस मिलेगा या नहीं ?

राजस्थान के अन्दर २२ राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके अन्दर हमारा सिरोही राज्य ही ऐसा दुर्भाग्यशाली रहा है कि उसका पार्टीशन हुआ और हमारे कुछ भाई इसमें जुदा करके जनता की आवाज के विरुद्ध बम्बई सरकार में मिला दिये गये।

उसके पश्चात् मैं समझता हूँ कि मेरे इतना अर्ज कर देने के पश्चात् श्रीमान् मुख्य मन्त्री राजस्थान श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण का जब रिप्लाई (उत्तर) देंगे तो उसके अन्दर इसकी ओर अवश्य प्रकाश डालेंगे और हमें जानने को मिलेगा कि सरकार इस विषय में क्या प्रगति कर रही है ?

[श्री मोहब्बत सिंह]

इसके पश्चात् राजस्थान में व्यापक भ्रष्टाचार जो, आज मौजूद है, उसके लिए श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में कोई जिक्र नहीं है कि इस ओर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे इस भ्रष्टाचार को शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जाय ? भ्रष्टाचार के अलावा बेरोज़गारी और बेकारी जो राजस्थान के हर घर में फैली हुई है, इसके विषय में सरकार की नीति का कोई प्रदर्शन इस अभिभाषण में नहीं हुआ है।

इसके अलावा कॉमर्स और इन्डस्ट्री के विषय में भी इस अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कि सरकार की क्या नीति रहेगी और इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया जा चुका है ?

फोरेस्ट के डेवलप्मेन्ट के लिए जो कि नैशनल वेल्थ है, श्रीमन् राजप्रमुख की स्पीच में कोई जिक्र नहीं है। इस विषय में क्या नीति अब तक अपनाई गई है और आयन्दा क्या कार्य किया जाने वाला है इस सम्बन्ध में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में पुलिस की प्रशंसा की गई है। मैं मानता हूं कि पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है और जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। डकैतियों की संख्या में राजस्थान में कमी हुई है। ५२ पर्सेन्ट सन् १९५२ और ५३ में एक साल में कमी हुई है। अतः सरकार का इस ओर कदम अवश्य सराहनीय रहा है। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में कानून और व्यवस्था के लिए फरमाया गया कि कानून और व्यवस्था की दशा सुधर गई है। क्या मैं समझूं कि कानून और व्यवस्था का यही मतलब है कि डकैतियों का बन्द होजाना ? "कानून और व्यवस्था" बहुत विस्तृत शब्द है जिसके अन्दर कई चीजें आ जाती हैं। इसमें चोरियाँ, जुल्म और डिसिप्लिन भी हैं। कानून और व्यवस्था के अन्दर क्या उन्नति की इसका तो प्रदर्शन बीकानेर के अन्दर जो जन-आन्दोलन हुआ उस समय होगया था। यही नहीं जयपुर के अन्दर जब हड़ताल चल रही थी और उस समय में जब कि विधान सभा का अधिवेशन हो रहा था तब जो दिग्दर्शन हुआ इस कानून और व्यवस्था का, वह तो सब आपके सामने है। मैं पूछता हूँ कि कानून और व्यवस्था का मतलब क्या यही होता है कि मन्त्री और उच्च व्यक्ति सड़कों पर बिना प्रोटेक्शन के निकल ही न सकें ? कानून और व्यवस्था के अन्दर सरकार की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार की ओर से कानून और व्यवस्था के अलावा, पुलिस के दूसरे जो जुल्म हैं वे इतने बढ़ चुके हैं कि मेरे पूर्व वक्ता उन पर काफी बोल चुके हैं।

इसके अलावा शिक्षा की ओर सरकार की किसी नीति का इस अभिभाषण में दिग्दर्शन नहीं होता है। सरकार की कोई विशेष नीति शिक्षा की ओर नहीं रही है। यह तो जरूरी समझा गया है कि स्कूलें बढ़ादी जाती हैं, स्कूलें नई खोल दी जाती हैं। जनता को भी यह बता दिया जाता है कि कितनी स्कूलें और बढ़ाई गईं। मैं तो आपसे कहूँगा कि इनकी संख्यायें चाहे कम करदी जांय किन्तु कोई ठोस काम होना चाहिए, जो कुछ भी हो। नाममात्र के लिए सात हजार, आठ हजार स्कूलें खोल दी जाती हैं: जहाँ पूरे अध्यापक नहीं होते, कहीं अध्यापक होते हैं तो ब्लेक-बोर्ड नहीं होते, कहीं ब्लेक बोर्ड होते हैं तो अध्यापक नहीं होते। दूसरी

[श्री मोहब्बत सिंह]

योजना होती है पोल्ट्री (poultry) फार्म की। लेकिन उसका यह हाल होता है कि मुर्गियें ही अंडों को खा जाती हैं दूसरों को अंडे नहीं मिलते। कृषि विभाग के अन्दर जो मशीनें लाई जाती हैं उनके अन्दर बीच में कमीशन लिया जाता है मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा कि मन्त्रियों ने जो गाड़ियाँ सीधी मंगाई हैं वे भी संदेहजनक नहीं हैं।

(राज्य पक्ष द्वारा 'संदेहजनक नहीं' की आवाज तथा "हियर, हियर" की ध्वनि और हंसी)

"संदेह जनक नहीं है" यह समझ लीजिये।

श्री चन्दनमल वैद—सही बात अपने आप निकल आती है।

श्री मोहब्बत सिंह—इसके अलावा फाइव इयर प्लान के अन्दर कोई प्रोत्साहन दिखाई नहीं देता है। सदन के सदस्यों के अन्दर ही यह भाव प्रकट हो रहे हैं कि बीकानेर के लोग बीकानेर की उन्नति चाहते हैं, जोधपुर के लोग जोधपुर की और जयपुर के लोग जयपुर की। जिनका पलड़ा भारी होता है वे ही अपने डिवीज़न की उन्नति करने में लग जाते हैं। सदन के बाहर भी डिविज़नल भावना को ही प्रोत्साहन दिया जाता है मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि यही भावना रही और केवल डिवीज़नल भावना को प्रोत्साहन दिया गया तो राजस्थान, जिसकी तरक्की के लिए हम सभी उत्साहित हैं, कभी तरक्की पर नहीं आ सकता। फाइव इयर प्लान में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी हैं। जिस राजधानी का जोर होता है उसी राजधानी को बनाने के लिए योजनायें बनती हैं। योजनायें बनती हैं, गलती से योजनायें रह जाती हैं और वे कार्यरूप में परिणत नहीं होतीं।

पंचवर्षीय योजना में आपने जवाई-बन्ध का जिक्र किया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह तो आपकी योजना नहीं थी, भूतपूर्व जोधपुर सरकार की योजना थी। आप उसको अधूरा भी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए आपने उसको पूरा कराया। चम्बल और भाखरा योजनाओं के लिए भी कहूँगा कि ये पहले की सरकारों की नीतियों के कारण से हैं। भाखरा से पहले १२ लाख एकड़ सिंचाई होगी, ऐसा कहा गया, फिर ६ लाख रह गई और उसके बाद पाँच लाख रह गई। मैं समझता हूँ कि यह कहीं पाँच लाख से घट कर डेढ़ दो लाख न रह जाय।

अब मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सिर्फ दो मिनिट और चाहता हूँ।

हमारे जिले में कुछ नहीं हुआ है। कृष्णवती-घाटी-योजना के लिए दरख्वास्तें की गई हमें सूचना दी जाती है ओड़ा बाँध के लिये उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि ओड़ा बन्ध अलग है और कृष्णा-बन्ध अलग इससे सरकार की हालत का पता चल सकता है।

[श्री मोहब्बत सिंह]

इसके पश्चात् मैं यह कहूँगा कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है जिससे खेती-बाड़ी में उन्नति हो सके। एक तरफ तो आप श्रीमन् राजप्रमुख को बधाई देते हैं और दूसरी तरफ सिलिंग टैक्स, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, राजस्थान लैन्ड रिफार्म बिल का जिक्र आता है। जब टिनेन्सी बिल बन गया तो फिर राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स बिल और सिलिंग बिल की क्या जरूरत थी ? सिलिंग बिल अमल में आजायगा या एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बिल। ये बिल इतने कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं कि इससे सरकार की नीति का परिचय मिल जाता है। अतः सरकार की कोई नीति नहीं है।

इन्हीं कारणों को लेकर मैं सदन से निवेदन करूंगा कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में एक सराहनीय कार्य का और जिक्र आया है और वह है अनाज की स्थिति सन्तोषजनक होने के विषय में, तो वह तो कुदरत का कार्य है। इसमें सरकार का कोई सराहनीय कदम नहीं रहा है। कर्जे के विषय में सरकार ने सराहनीय कदम लिया है। कर्जा ले लिया किन्तु देने का नाम नहीं है। यदि यह हाल रहा तो राजस्थान सरकार दिवालिया बन जायगी। स्माल सेविंग्ज़ स्कीम भी फेल हो रही है। राजस्थान की जनता में सरकार का कोई विश्वास नहीं है। तो फिर यह पैसा वापिस किस तरह लौटायगी ? अतः मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि श्रीमन् राजप्रमुख को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद नहीं दिया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति का उल्लेख किया है और आँकड़ों के द्वारा उनका स्पष्टीकरण किया था। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष में राजस्थान के ३८ डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया, ३७ डाकुओं को जान से मारा गया और ४२३ डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कड़े और प्रभावशाली कदम उठाये जाने के कारण गत वर्ष के मुकाबले में १९५३ में डकैतियों की संख्या में ५२ प्रतिशत कमी हुई है। यह महज राय का सवाल नहीं, यह फेक्ट्स हैं जो कि राजप्रमुख ने अपने भाषण में रखे हैं: इसको डिनाइ करने का सवाल नहीं। आँकड़े अपने आप बोलते हैं कि सरकार की शान्ति और व्यवस्था की कार्यवाही पूर्णरूपेण सफल रही है, जैसा कि हमको इस विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के समय यह प्रतीत हो रहा था कि हमारे राजस्थान में अराजकता का बोलबाला है आज उस खतरे को रोक दिया गया है। न्याय-व्यवस्था और शान्ति-व्यवस्था के सुधार के कारण आज जनता अपने आपको सुरक्षित अनुभव कर रही है। आज जनता अपने आपको सुरक्षित समझने लगी है। उनको किसी भी प्रकार अपने जान-माल का खतरा नहीं है। यह स्थिति हमारी राजस्थान की पुलिस की कार्यवाही के कारण पैदा हो सकी है।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ, जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा कहा गया कि केवल डकैतियों के कम हो जाने से हम यह नहीं मानते कि हमारे यहाँ शान्ति-व्यवस्था ठीक हो गई है। जयपुर, बीकानेर में जो अभी अभी एजिटेशन चले, जिनकी ओर इशारा किया गया; उसके

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

लिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आन्दोलन हर सरकार के समय हुआ करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि गुमराह लोग ऐसी गलती हमेशा करते रहते हैं। इस प्रकार के एजिटेशन हर जमाने में हर शासन-प्रणाली में हमेशा होते आये हैं। यहां तक कि जिस जमाने को हम गोल्डन एज़ कहते हैं वह रामचन्द्रजी का जमाना था। उस समय भी उनसे सब लोग सन्तुष्ट नहीं थे, जैसा कि हमको अपने धर्मग्रन्थों में पढ़ने को मिलता है लोग उस संसार के महापुरुष के परिवार के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चा करते थे। इस प्रकार की बातें हमेशा होती आई हैं। यह मापदण्ड इस बात का प्रमाण नहीं कि जहाँ कहीं भी एजिटेशन होता है इसलिये सरकार की न्याय व कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि मिनिस्टरों की सुरक्षा के लिए पुलिस एस्कोर्ट का भी प्रबन्ध किया गया। उसके लिये मेरा निवेदन है कि यह उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वहाँ का पब्लिक की सुरक्षा के लिए, हमारे एम. एल. एज. की सुरक्षा के लिए यह प्रबन्ध किया गया थी क्योंकि उस समय लोग दुकानों के ताले तोड़ रहे थे। लूटपाट न कर सकें इसके लिए पुलिस का प्रबन्ध किया गया और हमें माननीय सदस्यों को विधान सभा भवन में आने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी आवश्यक थी।

श्री **वेदपाल त्यागी**--सदन के सदस्य तो उसमें पकड़े गये थे ?

श्री **जोशी**—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

हो सकता है किसी ने गलती की हो, उनको पकड़ा गया हो। जिन्होंने गलत कार्यवाही की होगी तो वे पकड़े गये होंगे।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में विगत वर्ष का लेखा-जोखा रहता है और आगामी वर्ष में सरकार की जो नीति होगी उसका दिग्दर्शन होता है और आगामी वर्ष में सरकार की क्या नीति होगी उसकी घोषणा होती है। राजप्रमुख को धन्यवाद देने का जहाँ तक सवाल है इस सदन के प्रत्येक सदस्य को जो इस सरकार के विगत वर्ष के कार्य से सन्तुष्ट है और आगामी वर्ष में जो कार्य सरकार करने जा रही है, अगर उसको वह सन्तोषजनक मानता है, तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिये। जिस सरकारी नीति का राजप्रमुख ने अपने भाषण में दिग्दर्शन कराया है अगर उसको आप ठीक समझते हैं तो आपको धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये।

विरोधी दल के बेन्चों पर बैठने वाले सदस्य अपने आपको जरूर जनता का प्रतिनिधि मानते हैं और कहते हैं......

कुं. श्री जसवन्त सिंह— जनता के प्रतिनिधि ही हैं।

श्री **जोशी**— (अपना भाषण जारी रखते हुए)

हालांकि कभी कभी जब जागीरों के सम्बन्ध में या जमीन के सम्बन्ध में बहस होती है तो वे एक वर्ग विशेष की वकालत करते हैं। मेरा निवेदन है कि आपको वर्ग विशेष की दृष्टि से नहीं

Page No.46

[श्री जोशी]

सोचना चाहिए। जहां कहीं भी इस प्रकार का वाद–विवाद होता है वहां जागीरदारों की तरफ़दारी करते हैं।

कु. श्री जसवन्त सिंह––बिल्कुल नहीं।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी–– मेरा कहना यह है कि आप ज़ाहिरा में तो दुनियां को बतलाते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको एक विशेष वर्ग की तरफ़दारी नहीं करनी चाहिए, आपको जनता की राय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजस्थान की जनता ने अपना स्पष्ट मत दिया है, पहले सेशन और इस सेशन के बीच ८ बाइ इलेक्शन्स हुए हैं जिसमें जनता ने अपने मत देकर कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था व विश्वास प्रगट किया है। उन ८ उप–चुनावों में कांग्रेस ने सात सीटों पर कब्जा किया है। इससे यह साफ़ ज़ाहिर है कि जनता की राय इस शासन के प्रति क्या है? बाइ इलेक्शन्स इस बात का एलान है कि जनता किस प्रकार की सरकार को पसन्द करती है? "Bye-elections are always regarded as an indication of the trend of public opinion in the country" प्रान्त की जनता किस पार्टी की सरकार चाहती है इसका निर्णय उप–चुनावों में होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रान्त में जो उप-चुनाव हुए, जितनी शानदार कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिली उस प्रकार की कामयाबी किसी भी प्रान्त जिसमें ए. बी. सी भी शामिल हैं, नहीं प्राप्त हुई। हमारे प्रान्त ने इस प्रकार की शानदार कामयाबी हांसिल की है वह इस बात का प्रमाण है, जनता कांग्रेस सरकार को चाहती है। हमने इन उप-चुनावों में ८ में से ७ सीटों को जीता। जनता अपना मत दे चुकी है क्योंकि जनता कांग्रेसी शासन की नीति में विश्वास करती है, कांग्रेसी शासन का समर्थन करती है, इसको वह सन्तोषप्रद मानती है तथा कांग्रेस की नीति में उसका विश्वास है। राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता की यह राय है। उसने अपना फ़ैसला कांग्रेस के पक्ष में दिया है। यह हमें हमारे बाइ इलेक्शन से पता चलता है। हमें इस अर्से में एक पार्लियामेंट के उप-चुनाव में भी सफलता मिली। अगर विरोधी दल की आलोचनाओं में कुछ तथ्य होता तो विरोधी दल की आलोचनाओं और तरीकों में जनता का विश्वास होता, उन लोगों का जनता पर प्रभाव होता और कांग्रेस को यह शानदार कामयाबी हांसिल नहीं होती। यह कामयाबी इस बात का सबूत है कि राजस्थान की जनता का कांग्रेस शासन में विश्वास है और वह कांग्रेस की नीति को पसन्द करती है।

विरोधी दल के सदस्य केवल विरोध करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इस तरह से वे अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, वे जनमत का विरोध करते हैं और केवल विरोध के कारण विरोध कर रहे हैं।

कु. श्री जसवन्त सिंह–– इस उप-चुनाव में जीतने के लिए राजस्थान सरकार को भी आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इसका भी उसमें हाथ था।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी––Indirectly it is a thanks to Government.

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

(विरोधी-दल की ओर से करतल-ध्वनि)

राजप्रमुख को उनके शिष्टाचार के नाते धन्यवाद नहीं दिया जाता, बल्कि यह एक प्रकार से सरकार की नीति में विश्वास प्रकट करने का वोट है ।

कुं. श्री जसवन्त सिंह— मैंने तो यह कहा था कि बाइ-इलेक्शन की जीत में सरकार का हाथ था ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Mr. Speaker, Sir, I am in possession of the House and it is not a parliamentary practice that I should be interrupted.

कुं. श्री जसवन्तसिंह— I am sorry.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— Thank you.

अब मैं आपके सामने पुलिस के आधुनिकरण के बारे में अर्ज करूंगा । इस एक साल के दर्मियान में इसका आधुनिकरण किया गया है । पुलिस की मोबाइल पॉवर बढ़ाने के लिए वायरलेस सिस्टम का प्रयोग किया गया है । जगह जगह स्थानों पर थानों में वायरलेस का इन्तजाम किया गया है, जिससे हम डाकुओं की कार्यवाही का जल्दी से जल्दी पता लगा सकें । इससे पुलिस का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और पुलिस की एफीशियेन्सी में काफी हद तक वृद्धि होगी । इसके अलावा फिंगर प्रिंट ब्युरो की भी स्थापना की गई है । ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिससे पुलिस का आधुनिकरण हो सके । इससे पुलिस की एफीशियेन्सी बढ़ने की पूरी सम्भावना है ।

मैं अब आपके सामने हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकाश डालूंगा । जहाँ तक हमारी आर्थिक स्थिति का सवाल है, जब हम पहले सेशन में यहाँ मिले थे तब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जिसको छुपाया नहीं जा सकता । हमें कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा । यह सही बात है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । लेकिन आज हमारी आर्थिक स्थिति संतोषप्रद है । हमारे प्रांत के पंचवर्षीय योजना के लिए १६.८१ लाख रुपये अलोट किये गये थे, जो हमारे इतने बड़े प्रांत के लिए अपर्याप्त थे । फिर राजस्थान सरकार के प्रयत्न के बाद इस रकम को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयत्न फलस्वरूप इसको २२ करोड़ ६७ लाख रुपया इस पंचवर्षीय योजना के लिए प्राप्त हुआ है । इससे हमको करीब ६ करोड़ १६ लाख रुपये ज्यादा अलोट किये गए हैं । इसके अतिरिक्त हमको १ करोड़ ७५ लाख रुपये माइनर इरीगेशन के लिए मिल चुके हैं । रूरल वाटर सप्लाई के लिए एक करोड़ रुपया इसके अलावा मिला है । इस प्रकार ६-१० करोड़ रुपया भारत सरकार से प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं । इन रुपयों से हम राजस्थान के देहातों की हालत और उनके नक्शे को बदलने में इन रुपयों को काम में लायेंगे । गाँवों में सड़कें औषधालय खोले जायेंगे । कम्युनिटी प्रोजेक्ट के जरिये हम देहातों में स्कूल अस्पताल आदि बनाकर वहाँ की तरक्की के लिए हर सम्भव उपाय कर सकेंगे ।

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

इस साल जैसा कि आप लोगों को पता है दो कम्युनिटी ब्लॉक खोले गये हैं तथा १२ नेशनल एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स की स्थापना की गई है।

शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी कल्याणकारी राज्य के जांचने का एक मापदण्ड होता है। शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य, जिनका जनता से सम्बन्ध है और इनसे किसी भी राज्य का मापदण्ड मापा जा सकता है। इन विषयों को सरकार ने कितना महत्व दिया है या देती है, इस बात से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम बजट में शिक्षा के लिए ६२ लाख का प्रोवीजन रखा गया था, विगत वर्ष में इसके लिए २-६१ लाख का प्रोवीजन रखा गया है इस तरह से शिक्षा के लिए १ करोड़ ६६ लाख रुपये ज्यादा सरकार ने इस मद में अलोट किया है। इस साल १३०० प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, ५० प्राइमरी स्कूलस् को मिडिल स्कूल बनाया गया है तथा १० मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल बनाया गया है एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए भ प्रबन्ध किया गया। कॉलेज भी बढ़ाये गए हैं।

जहाँ तक पब्लिक हैल्थ का सवाल है, यह भी हमारी वाकफियत में है कि ३५ आयुर्वेदिक औषधालय इस साल खोले गये हैं देहातों में, ३५ अगले साल खोले जाने वाले हैं और जिला बोर्डों द्वारा कई दर्जन ऐसे अस्पताल खोले गये हैं, जो इनके अतिरिक्त हैं।

इसके अतिरिक्त सवाई मानसिंह अस्पताल के रिकॉग्निशन का सवाल जो अरसे से चल रहा था और जिसकी वजह से हमारे यहाँ के मेडिकल के छात्रों को बड़ी कठिनाइयाँ अनुभव हो रही थीं तथा जिनका भविष्य अन्धकार में था, उस कार्य को भी पूरा कर लिया गया है। लेबोरेटरी आदि का जो स्टेन्डर्ड आवश्यक था ऐसे रिकॉग्निशन के लिए सभी शर्तें पूरी कर ली गई और अखिल भारतीय मेडिकल कॉलेज से रिकॉग्निशन प्राप्त कर लिया गया है।

अब मैं निवेदन करूँगा आबू के बारे में। आबू के बारे में कहा गया है कि राजस्थान के राजप्रमुख के भाषण में कोई जिक्र नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात इससे नहीं प्रतीत होती है कि आबू के प्रश्न को पीछे डाल दिया गया हो या प्रयत्नशील न हो हमारी प्रान्तीय सरकार। लेकिन यह सही है कि एक सरकार किसी एजीटेटर का रोल अदा नहीं कर सकती और सरकार के लिए यह बात वाजिब भी नहीं है कि हमेशा किसी मामले को आन्दोलन के रूप में चलावे।

जहाँ तक भारत सरकार से पत्र-व्यवहार और जोरदार मांग करने का सवाल है, सरकार यह कर चुकी है और इस विषय में जो बाउन्ड्री कमीशन बैठा है, जैसा कि सब आप लोगों को मालूम है, उसके सामने भी आबू का केस बहुत जोरदार तरीके से रखने के लिए और इस मामले को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिये वह सब यह सरकार कर रही है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि राजस्थान का आबू का दावा बड़े जोरदार ढंग से इस कमीशन के सामने रक्खा जावेगा और फिर जो भी निर्णय होगा वह सामने आवेगा। पर यह निश्चित बात है कि सरकार आन्दोलन का रोल नहीं प्ले कर सकती। आबू के सम्बन्ध में हम सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं फिर

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

अगर हर मौके पर उसी को लाकर खड़ा करते रहें तो इससे कोई खास हल नहीं निकलने वाला है। तो इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो मालूम होगा कि यह कोई मेटीरियल ओमीशन नहीं था राजप्रमुख के भाषण में।

इसके बाद में एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा और जिसके लिए मैं समझता हूँ कि इसका भी उल्लेख इस राजप्रमुख के भाषण में होना चाहिये था और वह है नेशनल डिफेन्स। हालांकि यह हमारा विषय नहीं है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक सरहदी इलाके पर रहने वाले लोग हैं और पाकिस्तान-अमरीका की फौजी सन्धि की जो भी प्रतिक्रिया होगी-उसका असर सबसे पहले हम पर सीधा पड़ सकता है और इसका भारी असर इस राजस्थान पर आ सकता है। तो इस दृष्टि से हम सबके दिमागों में यह चिन्ता है—सबसे बड़ी कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए, जोकि ६५० मील लम्बी पाकिस्तान से लगी हुई है, हमारी प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके आवश्यक इन्तजाम के लिए प्रयत्न करे। इस ट्रीटी के बाद हमारी सुरक्षा को कब किस समय खतरा पैदा हो सकता है यह कोई नहीं कह सकता। अतः इसके लिए मैं कहूँगा कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके इसका कोई इन्तजाम करे। ऐसा इन्तजाम हो जाना चाहिये; तभी हम महसूस कर सकते हैं कि हम बिलकुल सुरक्षित हैं और हमारी जान और माल खतरे में नहीं है। तो इसकी तरफ तवज्जह दिलाते हुए मैं इस जनतंत्री सरकार की नीति का समर्थन करता हूँ और इस भाषण पर धन्यवाद दिये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। यह जनतन्त्रीय सरकार की बात है। इसे फिलहाल होने वाले इन उपचुनावों की सफलताओं ने और भी साबित कर दिया है। इन सबकी उपेक्षा करके मेरे विरोधी पक्ष के साथी केवल विरोध की खातिर यदि विरोध करें तो यह ठीक नहीं है और इसलिए मैं भवन के सब सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे सब एकमत से इस राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करें और इसको पास करें।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, कल से, परसों से श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं संविधान में श्रद्धा रखता हूँ और संविधान में राजप्रमुख की एक पोज़ीशन है जिसके अनुसार वे इस स्टेट के हैड हैं। इसलिए, चूंकि उन्होंने यहाँ आकर एक भाषण दिया इसके लिए धन्यवाद तो हम सबको देना ही चाहिये, पर मैं आज इसको ऑपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसका कारण यह है कि हमारे राजप्रमुख ने सम्भवतः इंगलैंड में ही शिक्षा पाई है और हिन्दी से इतने वाकिफ नहीं हैं जिससे उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में पढ़ा हो। लेकिन प्रस्तावकर्त्ता महोदय, जिन्होंने अपना भाषण तो हिन्दी में दिया, इस प्रस्ताव को, धन्यवाद देने के प्रस्ताव को, अंग्रेजी में रक्खा। अगर हम इस प्रस्ताव को इसी रूप में राजप्रमुख के पास भेजेंगे (आंग्ल भाषा में) तो इसका मतलब यह होगा कि सदन भी इस आंग्ल भाषा को स्वीकार करता है, जब कि हमारी भाषा हिन्दी है। हमें हिन्दी में ही बोलना चाहिये। हमें प्रस्ताव भी हिन्दी में ही प्रस्तुत करना चाहिये था। इसलिए हिन्दी के प्रेमियों से मैं यह कहूँगा कि उनको चाहे कैसा भी व्हिप मिले लेकिन वे इस बात को जोरदार शब्दों में रक्खें कि हम आंग्ल भाषा में इस सदन से प्रस्ताव

[श्री वेदपाल त्यागी]

राजप्रमुख के पास नहीं भेज सकते हैं और इसका सीधा-सा रास्ता यह है कि आप लोगों में से कोई भी एक संशोधन रख दीजिये कि यह प्रस्ताव हिन्दी में हो और उसको फिर स्वीकार कर लीजिये। इसलिए मैं राजप्रमुख को धन्यवाद देने के खिलाफ नहीं, लेकिन धन्यवाद का प्रस्ताव आंग्ल भाषा में भेजने के बहुत खिलाफ हूँ; इसलिए मैं इसको आज ऑपोज करने को खड़ा हुआ हूँ और ऑपोज करूँगा।

अब मैं राजप्रमुख ने जो भाषण दिया है उसके ऊपर दो-चार शब्द कहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेटिक सरकार जहाँ पर होती है, वहाँ पर यह परम्परा है कि साल के शुरू में हैड ऑफ दी स्टेट आता है और वह सरकार की पोलिसी का स्टेटमेंट पढ़ता है और उस पर वाद-विवाद होता है। इस पोलिसी के स्टेटमेन्ट में दो चीजें होती हैं। एक तो जो कुछ पिछले साल में गवर्नमेन्ट ने काम किया है उसका ब्यौरा होता है एवं दूसरा आगे की नीति का उल्लेख होता है।

इस भाषण में पिछले साल का ब्यौरा तो मिलता है लेकिन आगे क्या पोलिसी है इसका उल्लेख नहीं मिलता। भविष्य की नीति ही वाद-विवाद का विषय रहता है। जो पालिसी अगले वर्ष के लिए निर्धारित की गई है, उसको हाउस ठीक तरह से सपोर्ट करता है या नहीं या उस पर अगर संशोधन आते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीति को कार्यान्वित करती है। पर, दुख है कि राजप्रमुख के इस भाषण में पिछले साल के कार्य की सरकार की रिपोर्ट तो मिलती है पर आगे सरकार क्या करना चाहती है, आगे (आने वाले) साल की उसकी क्या नीति होगी अथवा अगले साल सरकार क्या करना चाहेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है।

लेकिन उल्लेख न होते हुए भी मैं दो-चार बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि सरकार के मन्त्रियों में से कोई यहाँ नहीं बैठा है। एक उपमन्त्री महोदय जरूर बैठे हैं।

श्री चन्दनमल वेद (उप मन्त्री, न्याय विभाग)—मैं अकेला ही काफी हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—वे केबिनेट में नहीं बैठते हैं, इसलिए काफी नहीं हैं। तमाम पोलिसी सरकार की केबिनेट ही तय करती है और आप केबिनेट में बैठने का अधिकार नहीं रखते हैं, इसलिए काफी नहीं है।

('हियर, हियर' की आवाज)

श्री चन्दनमल वेद—मुझे अफसोस है कि इसकी पूरी जानकारी आपको नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—मुझे जानकारी है; मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, इसलिये।

[श्री वेदपाल त्यागी]

तो सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ मैं आज सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि हमेशा पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में इस सदन में उस गवर्नमेंट से, इन (दल विरोधी की) बैंचों पर बैठने वाले प्रतिनिधि अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यह स्पष्ट बात है और वे इस सदन के मातहत काम करते हैं। (आवाज "वे तो अपने को बड़ा समझते हैं") वे ऐसा मानें तो मानें। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में यह लिखा है कि हम स्वस्थ परम्पराएँ कायम करेंगे, इस प्रकार की परम्पराएं कायम करेंगे जिससे हमारी डेमोक्रेसी की नींव मजबूत होगी। पर इस नींव मजबूत करने वालों में मैं देखता हूँ कि इस हाउस के प्रति जो श्रद्धा है वह शून्य है, उनका रवैया वास्तव में अनुचित है। मुझे दुख होता है इस बात को देखकर कि हमारे मन्त्रीगण किस प्रकार इस हाउस की अवहेलना करते हैं। यही नहीं कि आज वे एबसेन्ट हैं, पर जिस प्रकार के सवालों के जवाब देते हैं और जिस प्रकार के यहाँ वादे करते हैं और बाद में उनकी अवहेलना करते हैं, उससे पता लगता है कि वे सदन की लेशमात्र भी परवाह नहीं करते। इसको तो सिर्फ उन्होंने वाद-विवाद का भवन बना लिया है। अब मैं यह आपसे निवेदन करूँ कि हमारे प्रस्तावक महोदय और उनका अनुमोदन करने वाले जो महाशय थे उन्होंने भी कई गल्तियाँ सरकार की बतलाईं, लेकिन सरकार तो सिर्फ यह समझती है कि इस वक्त जो उनके हाथ में शक्ति है उसके तहत चाहे वे उस शक्ति का दुरुपयोग करें और सदन की अवहेलना करें। मैं दो-चार इन्स्टान्सेज़ (instances) इस प्रकार की बतलाऊंगा कि सरकार किस प्रकार अवहेलना करती है, किस प्रकार जवाब देती है, किस प्रकार वायदे करती है और वायदों को करने के बाद भी वायदों को क्रियान्वित नहीं करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सदन बना और इसके बाद पहला अधिवेशन सन् ५२ के मार्च में हुआ तो श्री कपिलदेवजी ने एक सवाल पूछा था। उस सवाल का नंबर ३७ है। उसमें मेडिकल सर्विसेज़ के विषय में उन्होंने कुछ सवाल किया था। उस पर उस वक्त जो मिनिस्टर थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कन्डेन्स्ड एम. बी. बी. एस. (उनके संबन्ध में सवाल था) का एकीकरण बहुत जल्दी कर रहे हैं, वह बहुत जल्दी हो जायगा। उस वक्त राजस्थान बने ३ साल हो गये थे, वह एकीकरण नहीं हो पाया था। वह आश्वासन १४.४.५२ को मन्त्री महोदय ने दिया था। उसके बाद दूसरी बार ६.१०.५२ को सवाल नं० ४५ श्री दामोदर व्यास ने पूछा था। उनके जवाब में भी यह उत्तर मिला कि उनका एकीकरण बहुत जल्दी कर दिया जायगा। इसके बाद सन् ५३ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें २५.२.५३ को क्वेश्चन नं० २३७ श्री दामोदर व्यास ने दुबार पूछा कि एकीकरण कब तक समाप्त हो जायगा; उस पर भी वही आश्वासन फिर मिला था। फिर २७.६.५३ का क्वेश्चन नं० ४६ श्री मुक्तिलाल मोदी द्वारा किया गया था, इसमें भी यही आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्दी एकीकरण समाप्त हो जायगा। लेकिन मुझे दुख है कि इस भाषण के अन्दर पेरा नं० २२ में यह बतलाया गया है कि हमने मेडिकल सर्विसेज़ को आर्गेनाइज़ कर लिया है। उनको इस लेवल पर ला दिया है जिस लेवल पर वे दूसरे प्रोविन्सेज़ में organised हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बात बिल्कुल असत्य है, सदन को जो बार-बार आश्वासन दिये गये हैं उनकी अवहेलना की गई है। यह नियम तोड़ा गया है, जिस तरह वे उल्लेख करते हैं कि उन्होंने उसे आर्गेनाइज़ (organise) किया है, तो मैं यह निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठने वाले लोगों

[श्री वेदपाल त्यागी]

से कि अगर वे डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) की स्वस्थ परम्परा डालना चाहते हैं, वे अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ जनतन्त्रवाद पनपे, तो उनको चाहिये कि वे स्वस्थ परम्पराएं डालने में सबसे आगे रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है, जो अपोज़िशन में बैठने वाले आपके सामने विचार रखते हैं, जो टीका टिप्पणी कर सकते हैं, तो उनको कार्य रूप में पारिणत करने का भार आपके कन्धों पर है । आप लोगों को चाहिये कि स्वस्थ परम्पराएं डालें । राजप्रमुख के भाषण में लिखने के बजाय अपने कार्य से सिद्ध करें कि आप वास्तव में स्वस्थ परम्पराएं डाल रहे हैं ।

दूसरा मुझे एतराज यह है कि पिछले ४ भाषण जो हुए हैं उनको मिला कर देखें तो चारों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि सरकार बढ़ती हुई शिथिलता को, सरकार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को दूर करने का ध्यान किस प्रकार दे रही है, इन भाषणों में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है । जैसा कि मेरे एक मित्र अभी बोल रहे थे कि इतने डाकू पकड़ लिए गये हैं, तो इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिये ही । यह डाकू पकड़ने का आपका सामान्य कार्य है । अगर कुछ एन्टीसोशल एलीमेंट (anti social element) हैं तो उनको पकड़ने का भार आप पर है, उस पर गौरव नहीं करना चाहिये । हाँ अगर आप कोई ऐसा काम जो लोगों की तरक्की का हो करें तो उसमें आप धन्यवाद के पात्र समझे जायेंगे । जो सामान्य कार्य आप रोजाना करते चले आ रहे हैं और करना चाहिए उनका उल्लेख करके अपने आपको बधाई का पात्र नहीं मानना चाहिये ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का कारण सरकार को ढूँढ़ना चाहिये, बढ़ती हुई इस शिथिलता का कारण ढूंढना चाहिये । सबसे बड़ा कारण मेरी राय में तो यह है कि दूसरी तरफ बैठने वाले हमारे कांग्रेस मित्रों का इन्टरफियरेन्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमारे यहाँ की सर्विसेज़ ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकती हैं । उसका नमूना मैं आपके सामने एक ऐसा प्रमाण पढ़कर पेश करूंगा जिसका उत्तर इस संबन्ध में उधर बैठने वाले दोस्तों से सम्भवतः न बन पड़े । हाईकोर्ट ने अभी अपने एक फैसले में लिखा है जिसकी कि ३ लाइनें मैं पढ़कर सुनाऊंगा । वह फैसला छपा है, ऑल इन्डिया रिपोर्टर १९५३ के दिसम्बर महिने में । वह इस प्रकार है—

"On 2-7-52, the Education Minister and the Collector Jhunjhunu, accompanied by Shri Kumbha Ram and Herlal Singh visited village Chindcholi and at their instance, the sub-Divisional Magistrate, ordered on 7th, 14th and 17th July, 1952, whereby the opposite parties were declared in possession of the plot which were in fact in the petitioner's occupation."

('शेम, शेम' की ध्वनि)

आगे जाकर हाई कोर्ट ने लिखा है :—

"Their Lordships of the High Court observed:—

[श्री वेदपाल त्यागी]

'It is high time that the authorities in charge of the District and the sub-division should realise that the Constitution of India guarantees certain fundamental rights to the citizens of India and they should not violate them by such old-time methods.'

मैं यह निवेदन करूँगा कि इस तरह के इन्टरफियरेन्स, यही नहीं बल्कि हर तबादले में, हर नियुक्ति में किये जाते हैं और दखल करते हैं। तबादलों में और नियुक्तियों में कभी-कभी दो दलों के कांग्रेसी काम करते हैं।..........

श्री जयनारायण व्यास—यह फैसले की जो रिपोर्ट हुई है उसकी क्या तारीख है?

श्री वेदपाल त्यागी—यह ऑल इण्डिया रिपोर्ट १९५३ दिसम्बर महीने की है। वह राजस्थान सैक्शन के २०२ पेज पर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो ऑल इण्डिया रिपोर्ट से फमीलियर नहीं हैं उनके लिए तारीख बता दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद—हम लोग सब फेमीलियर हैं, आप क्यो चिन्ता करते हैं?

श्री वेदपाल त्यागी—जिन व्यक्तियों का नाम इसमें आया है वह एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वह एक बहुत ऊँचे पदाधिकारी रहे हैं। उस वक्त उनमें से एक सज्जन मिनिस्टर थे। इस तरह से डे टू डे वर्क में इन्टर्फियरेन्स करके लोगों को कब्जा दिलाया करते थे। मैं यह निवेदन करूँगा कि सर्विसेज़ में यह भावना पैदा हो जाती है कि कुछ लोगों को प्रसन्न करना है और उनको प्रसन्न करेंगे तो हम उनसे अपना काम करवा सकेंगे अन्यथा नहीं करवा सकेंगे। इस तरह की भावनाएं हमारी सर्विसेज़ में बढ़ रही हैं कि उनको एक सेट ऑफ पीपल (set of people) को ही प्रश्न करने में उनका सुरक्षण है और यही कारण है कि इतनी अंधाधुन्धी हो रही है और लोगों का यह विश्वास बनता जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ लोगों की है, पीपल्स गवर्नमेंट (people's Government) नहीं है बल्कि एक सेट आफ पीपल (set of people) की गवर्नमेंट है और उनके लिए ही यह कार्य करती है। मगर सरकार में इस तरह का इन्टरफियरेन्स उन लोगों द्वारा, जिनका कि शासन में कोई अधिकार नहीं है, आर्गेनाइज़ेशन में हो तो उनको अपनी आर्गेनाइज़ेशन के द्वारा ही सरकार का ध्यान दिलायें, लेकिन इस प्रकार के तबादले और नियुक्तियों में दखलन्दाजी नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि काम ठीक हो। लेकिन यह ठीक तभी होगा जबकि उस तरफ के बैठने वाले इस बात की प्रतिज्ञा करें कि उन लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें, चाहे उनके द्वारा ही अपनाये जाते हों या नहीं। जो हमारे शासन में शिथिलता बढ़ने और भ्रष्टाचार पैदा करने में बहुत सहयोग दे रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा।

श्री वेदपाल त्यागी—बहुत जोरों के साथ इस बात का दावा किया गया कि बाइ इलेक्शन (bye election) में कांग्रेस ने ९ सीटें जीतीं। मैं यह जानता हूँ कि हमारे मुख्य मन्त्री को इसके लिए धन्यवाद मिला है, बधाई के पात्र हैं वे और बधाई भी दी गई है। एक बाइ इलेक्शन देखने के लिए मैं भी गया था। उसका बयान आपके सामने रखूं तो पता लगेगा कि बाइ इलेक्शन कांग्रेस ने नहीं बल्कि राजस्थान सरकार ने जीता है। (विरोधी पक्ष की ओर से करतलध्वनि) सरकार के मन्त्री अपने फौज-फांटे के साथ वहाँ जाते थे। मैंने स्वयं अपनी आँखों से इस बात को देखा है कि एक शहर में एक मन्त्री महोदय को घुसने नहीं दिया था तो उस स्टेशन पर १०० जवान भेजे गये। वहां ऐसा आतंक बनाया गया कि लोगबाग विरोध करने नहीं आये। अगर यही तरीका इलेक्शन जीतने का है, अगर वे यही स्टेन्डर्ड इलेक्शन का कायम चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि वह पीपल्स डेमोक्रेसी होगी। वह पीपल्स डेमोक्रेसी हरगिज़ नहीं होगी। आप उन लोगों को चाहे सत्ता से दबायें या पैसों से लेकिन जनतन्त्र की नींव पैसों से नहीं डाली जा सकती। अगर इस आधार पर ही आप समाज को बदलना चाहते हैं तो यह उन सिद्धान्तों पर नहीं है जिन सिद्धान्तों को महात्माजी ने बतलाया है। सिर्फ सत्ता को कायम रखने के लिये सिद्धान्तों को छोड़ देना में उचित नहीं मानता। इसलिये यह जो गर्व किया जा रहा है कि आज जनता उनको मानती है वह झूठा है। यदि आप जगह-जगह पर होने वाले म्युनिसिपल चुनावों को देखें तो आपको पता लग जायगा कि किस तरह वहाँ हार पर हार हो रही है। म्युनिसिपल चुनाव भी जनता की आवाज़ है। उनसे आपको मान लेना चाहिये कि आज जनता आपके राज्य को नहीं चाहती है, जनता स्वराज्य चाहती है। स्वराज्य कायम करने की कोशिश कीजियेगा, तब तो आप कायम रहेंगे। सत्ता के बल पर और बड़े-बड़े पूँजीपतियों के बल पर, पैसा खर्च करके आप अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकते।

श्री लालबहादुर—अध्यक्ष महोदय, आज तीन दिन से सदन में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश होने पर उस पर बहस चल रही है। जहाँ तक राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का सवाल है मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जब मैं यह देखता हूँ कि इस अभिभाषण में गई साल का सिंहावलोकन किया है और आगे के लिए हमारे सरकार की नीति निर्धारित की है तो मेरे दिमाग में जो बात आती है वह मैं सरकार तक आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष, पहुँचाना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

पहली बात तो यह है कि वह एड्रेस इङ्गलिश में दिया गया है और उस पर कई सदस्यों ने एतराज किया है; उनमें से एक मैं भी हूँ। राजप्रमुख कोटा में पढ़े हैं और रहे हैं और मैं जानता हूँ कि वे हिन्दी भली प्रकार से बोल सकते हैं। तब फिर न मालूम उन्होंने अंग्रेजी में अपना भाषण क्यों पढ़ा, जबकि सदन में हिन्दी में काम करने के लिए उन्होंने खुद ने आज्ञा निकाली है और उसकी उन्होंने खुद ने अवहेलना की है।

श्री जसवन्तसिंह—हिन्दी से शायद उन्हें घृणा है?

श्री तेजमल बापना—शायद आप इस बात को ज्यादा जानते हैं।

श्री लालबहादुर—(भाषण जारी रखते हुए) दूसरी बात यह कही गई है कि लॉ एन्ड ऑर्डर भली प्रकार से स्थापित कर दिया गया है। एक मर्तबा मुझे माननीय मुख्य मन्त्रीजी से इस बारे में बातचीत करने का मौका मिला था, जबकि कोटा से डी. आई. जी. पी. का हेड क्वार्टर उठाने का सवाल था। उस समय उन्होंने फरमाया था कि कोटा जिले की व्यवस्था अच्छी है। इस बात को सुनकर मैं बहुत घबराया और मैंने कहा कि या तो मुख्य मन्त्रीजी को जो इत्तला मिली है वह गलत है या मेरी जानकारी गलत है। मैंने यह जानने की कोशिश की कि सही मामला क्या है? तब मैंने एक वाकया देखा जो यह है कि किशनगंज में २७ डकैतियां की वारदातें हुईं और २७ दरख्वास्तें पुलिस के सामने आईं। उनमें से पुलिस ने एक दर्ज की और २६ दरख्वास्त देनेवालों से कहा कि एक अर्ज़ी दर्ज कर रहे हैं। जब इसके मुलजिमों का पता लग जायगा तब तुमको बुलाया जायगा और वह दरख्वास्त भी ३७६ में दर्ज की गई और डकैती के केस में दर्ज नहीं की गई। यदि ये सभी दरख्वास्तें डकैती में दर्ज की जातीं तो मुख्य मन्त्रीजी के कानों तक भी खबर जाती कि एक साथ वहाँ २७ डकैतियाँ हो गई हैं। लेकिन ये अधिकारी गवर्नमेंट को पूरी इत्तला भी नहीं देना चाहते और फैक्ट्स को दबा देते हैं। रियासत कोटा में आबाद हुए मुझे ३० साल हो गये हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी आदमी को डाकू उठा कर ले गये हों। मगर आज जिला कोटा के शाबाद में ऐसी घटना दिखाई देती है। वहाँ यह भी दिखाई देता है कि वहाँ की जनता जो बहुत डरी हुई है, चोरों और डाकुओं के जगहों पर खुद जाकर उनको रुपये देकर फैसला करती है कि हम तुमको इतना रुपया देंगे, तुम हमको लूटना-खसोटना मत, मारना मत। तहसील किशनगंज में विभिन्न तरह के चित्र नज़र आते हैं। वहाँ "might is right" का सवाल चल रहा है। वहाँ लोगों का आराम से रहना कठिन हो गया है। मौजा ब्यावर जो २॥–३ हजार की बस्ती है, दिन के ५ बजे दिन दहाड़े लोगों को लूट कर ८ ऊँट भर कर सामान ले गये, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। ऐसी डकैतियाँ-चोरियाँ मन चाहे जब वहाँ हो जाती हैं। इस पर भी कहा यह जाता है कि लॉ एण्ड ऑर्डर भली प्रकार से जारी है। यदि इसको लॉ एण्ड ऑर्डर कहा जाता है तो फिर डिसऑर्डर क्या होगा? (हियर हियर)

इर्रिगेशन के बाबत यह कहा गया है कि हमने बहुत अच्छा इन्तजाम किया है। गड़ा तालाब से रामगढ़ तक नहर निकालकर २० हजार बीघा जमीन को सिंचाई करने की तजवीज पहले की गई थी। आज इतनी मेहनत के बाद भी ४ हजार बीघा जमीन से अधिक की सिंचाई नहीं हो रही है और बचे हुए १६,००० बीघा जमीन के लिये वहाँ की गरीब जनता से टेक्स वसूल किया जायगा। यदि सरकार ध्यान देती और गोपालपुर के तालाब को बना देती तो वहाँ नहर से आबपाशी होती और एक इलाका सरसब्ज होता और सरकार और किसानों को लाभ होता। चंबल से कोटा जिले को इतना फायदा नहीं पहुँचाया गया है जितना दूसरी जगहों को वहाँ इन्जीनियरों की लड़ाई का नतीजा जनता को भोगना पड़ रहा है। पहले जो योजना थी उससे बारा टेन्क नहर पहुँचती और किशनगंज के आधे इलाके को पानी देती हुई मध्यभारत को पहुँचने की तजबीज थी। अब वह स्कीम तर्क कर दी गई है। अब वह नहर रामगढ़ के नीचे से गुजरेगी जिससे करीब गाँवों को आबपाशी का लाभ नहीं होगा।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एज्युकेशन का सवाल है। इस सम्बन्ध में भी जहाँ जहाँ की रियाया की आवाज हाई स्कूल खोलने के लिये थी वहाँ हाई स्कूलें अब तक नहीं खोली गई हैं। बारा हाई स्कूल में मेट्रिक के "जी" तक सेक्शन है और वहाँ के लोगों ने इसे इन्टर कॉलेज करने की कई

[श्री लालबहादुर]

बार माँग की है पर वहाँ इन्टर कॉलेज नहीं खोली गई है । दूसरी तरफ जबकि धारासभा बनने के बाद, जहाँ पर १२-१३ लड़के हैं वहाँ भी इन्टर कॉलेज खोल दी गई है । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन सब बातों के लिए मिनिस्टर साहबान जिम्मेवार हैं क्योंकि जो जिस जगह से आये हैं वे उसी जगह का दौरा करते हैं । यदि कोटा के इन्टीरियर में घुसने की कोशिश करते तो शाहबाद और किशनगंज की ओर उनका ध्यान जरूर गया होता । अभी दरबार कोटा ने वहाँ पर हिस्ट्री की सीट के लिए १ लाख रुपये दिये थे पर वह वहाँ नहीं खोली गई, जब कि कोटा कॉलेज में लगभग डेढ़ हजार लड़के पढ़ते हैं । कोटा को अब तक निग्लेक्ट किया गया है । कहीं आगे भी इसे निग्लेक्ट नहीं किया जावे इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं वहाँ की जनता की आवाज यहाँ तक पहुँचा देना चाहता हूँ, Medical help भी रियासत के जमाने से ज्यादा नहीं दी गई ।

डा० श्री मंगलसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख साहब ने कृपा पूर्वक जो सत्र के आरम्भ में भाषण दिया है, जिसमें पिछले कार्यों का दिग्दर्शन और आगे की नीति का पथप्रदर्शन किया है उसके ऊपर जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूँ । लगभग सभी सदस्यों ने यह माना है कि सरकार की ओर से जो कानून-व्यवस्था, खाद्य-स्थिति और आर्थिक-स्थिति में उन्नति सरकार ने की है वह अवश्य प्रशंसनीय है । उनमें बहुत सी खामियां हैं यह भी सच है और वह दूर की जायंगी । इसके बारे में आगे की नीति में मार्ग दर्शन किया है वह आगे आवेगा ।

हमारे दूसरी ओर के सदस्यों के नेता ने इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के एक अङ्ग में अभी तक समुचित उन्नति नहीं हुई है और वह यह कि यह ठीक है कि डाकू पकड़े गये हैं और डाकू और उनका आतंक जो प्रदेश में फैला हुआ था वह अवश्य कम हुआ है, परन्तु जो जनता की हिफाजत का सवाल है उन्होंने मिसाल देकर बताया कि जयपुर, बीकानेर आदि शहरों में आन्दोलन हुए और उस समय जनता की स्वतन्त्रता के ऊपर बंधन पड़ गया, आना-जाना बन्द हो गया और इस प्रकार से सब कार्यों में बंधन पड़ा । यह भी कानून-व्यवस्था का ही एक अङ्ग है और इसकी ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना ध्यान सरकार ने नहीं दिया है ।

इस सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर में जिस वक्त आन्दोलन चल रहा था तो उन नागरिकों को और खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और पुलिस को भी डर था और डर ही नहीं अपितु उनका आजादी के साथ निकलना तक बन्द था और उनकी यह शिकायत थी कि यह सरकार की कमजोर नीति के कारण था कि ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं होने के कारण उन लोगों की ऐसी हालत हुई ।

तो यह शिकायत कमजोर नीति की कीगई ।

श्री जसवन्तसिंह—अयोग्यता की शिकायत, कमजोर नीति की नहीं ।

डा० श्री मंगलसिंह—उसी ओर के मेरे एक मित्र ने, दूसरी ओर यह शिकायत की थी कि जिस बीकानेर या दूसरी जाह इस प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे और आन्दोलनकारी प्रदर्शन करने जा रहे थे, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिये पुलिस आई और उसने प्रदर्शनकारियों को रोका तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिये जिससे ५-७ पुलिस के अफसरों के चोटें आई । लेकिन जब अपने निजी बचाव के लिये पुलिस ने जो बल-प्रयोग किया वह अत्यधिक था और निज बचाव के लिये किये गये इस बल प्रयोग से पुलिस ने बहुत से लोगों को लाटी चार्ज किया या दूसरे प्रकार से घायल कर दिया; इतना बल प्रयोग करना उचित नहीं था ।

तो एक ओर तो, अयोग्यता कहिये या कमजोर नीति कहिये; इसकी शिकायत की जाती है और दूसरी ओर यह शिकायत की जाती है कि जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जाता है ।

तो मैं कहता हूँ कि सरकार क्या करे ? और कहा जाता है कि हम जो सुझाव देते हैं उनकी परवाह नहीं की जाती है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि परवाह की जाती है दोनों तरह के मतों की और सरकार ऐसी हालत में जनता के भावों की कद्र करके बीच का रास्ता खोजती है । जहां मुलायम नीति से काम चल सकता है वहां सरकार मुलायम नीति से काम लेती है और जहां मुलायम नीति से काम नहीं चल सकता है वहां उसे कुछ बल प्रयोग करना ही पड़ता है । उस ओर के लोगों को भी देखना चाहिये कि सरकार क्या करे, कौनसा रास्ता अख्त्यार करे ? जब मुलायम नीति को अख्त्यार करे तब तो यह शिकायत की जाती है कि सरकार कमजोर नीति को अख्त्यार करती है और जब बल प्रयोग किया जाता है तो यह शिकायात की जाती है कि बहुत बल प्रयोग किया गया । तो अब आखिर सरकार करे क्या ? सरकार जिम्मेदारी से काम करती है और जितने बल प्रयोग की आवश्यकता होती है उतना ही बल प्रयोग करती है ।

डाके डालने वालों के लिये बताया गया कि इतने डाके डालने वाले मारे गये, इतने पकड़े गये और इतना माल बरामद हो गया । लेकिन में यह अर्ज करूंगा कि जो सबसे बड़ा डाका है, चोरी और डाके के शब्दों का अगर में प्रयोग करूंगा तो वह ज्यादा सख्त रहेगा, इसके लिये "अपहरण" शब्द तो अवश्य प्रयोग में आ सकता है; वह अपहरण किसी व्यक्ति का अपहरण नहीं, किसी वर्ग विशेष का अपहरण नहीं बल्कि वह सरकार का अपहरण हुआ है, खुद राजस्थान सरकार का अपहरण हुआ है और राजस्थान के अन्तर्गत सिरोही जिले के अन्दर राजस्थान के एक इतने बड़े हिस्से का अपहरण हो गया है । और इस अपहरण के सम्बन्ध में यह भी मालूम हैं कि वह अपहरण किसने किया है, अपहरण किया हुआ माल भी मौजूद है फिर भी उसका हासिल नहीं होना; यह कितनी बड़ी शर्म की बात है ।

इस सदन में भी इस तरह का प्रश्न आया, प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को आगे भेजा गया, फिर आगे क्या हुआ- इसका जिक्र श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में नहीं है ।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री और दूसरे मन्त्री जब इस वाद-विवाद में भाग लेंगे तब इस विषय पर, इस सबसे बड़े अपहरण पर अवश्य प्रकाश डालेंगे ।

[डा० श्री मंगलसिंह]

यह केवल सिरोही का सवाल नहीं है, बल्कि यह सारे राजस्थान का प्रश्न है। यह राजस्थान का अंग नहीं, बल्कि सिर कट गया; इस पर भी हम बड़े इत्मिनान से इन्तजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिसका एक ऐसा प्रधान अंग कट गया हो जिससे वह आसानी से रोज खाना खाता हो, उसको इस चीज का फिक्र ही नहीं हो, यह बड़ी शर्म की बात है।

मैं समझता हूँ हम सबको इस ओर ध्यान देकर इसको जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिये। यह केवल सिरोही का ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान का प्रश्न है। आबू पर केवल सिरोही का ही नहीं सारे राजस्थान का हक है।

यह मैं मानता हूँ कि सिरोही के किसी हिस्से के लोग दूसरे प्रान्त में जाना चाहते हों, और अगर इसमें उन्हें लाभ हो तो उनको स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वे जहां जाना चाहें जांय, किन्तु आबू केवल सिरोही का ही नहीं है राजस्थान का है। राजस्थान में आबू ही एक ऐसा स्थान है जहाँ ग्रीष्म ऋतु में लोग जा सकते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में हम सब का विशेष ध्यान जाना चाहिये।

दूसरे पक्ष के सदस्यों ने और इधर के सदस्यों ने भी राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रुपये लेकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की है। जब कोई कर वसूल करने की बात आती है तो यह एतराज किया जाता है कि आगे ही जनता पर बड़ा बोझा है फिर यह नया टेक्स क्यों लगाया जा रहा है? उधर यह शिकायतें आती हैं कि हमारे यहाँ स्कूलें नहीं हैं, हमारे यहाँ औषधालय वगैरह नहीं खोले; यह सब खुलने चाहिये। खर्चे का मद तो बतलाया जाता है परन्तु जब आमदनी की सूरत बतलायी जाती है तो उसका विरोध किया जाता है और जब केन्द्रीय सरकार से मदद ले ली जाय तो इसमें भी एतराज होता है कि इस तरह से केन्द्रीय सरकार से मदद लेकर आर्थिक स्थिति का सुधार किया गया है।

मैं तो यह कहूँगा कि जब दूसरों से रुपया ले कर ही हम अपना काम चला लेते हैं और कर न बढ़ाये जावें तो इससे ज्यादा धन्यवाद की बात क्या हो सकती है। आप इस पर भी एतराज करते है और दूसरी बातों पर भी ऐतराज उठाते हैं कि कर नहीं बढ़ाये जावें। हर एक बात पर एतराज करते हैं, फिर काम किस प्रकार से हो।

मेरे दो मित्रों ने बेरोजगारी पर भी कहा है कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं यह कह रहा हूँ कि जो सिंचाई आदि का कार्य हो रहा है, बांध बन रहे हैं, बिजली का प्रबन्ध हो रहा है; क्या ये सारे के सारे काम ऐसे नहीं हैं कि जिससे बेरोजगारी हटाई जावे? स्कूलें और होस्पिटल खोले जा रहे हैं; क्या इससे पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी? क्या यह बेरोजगारी का निराकरण नहीं है? इसी प्रकार से धीरे-धीरे यह सब बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें हैं जिनके लिये हमें कुछ इन्तजार करना पड़ता है और जो बाद में ली जा सकती हैं। अगर आप टिकट लेने के लिये जावें तो जब टिकट बंटने लगते हैं तो आपको एक ही तरीके से टिकट मिलते हैं और उसके लिये आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हो सकता है कि आपका नम्बर पीछे आवे

[डा० श्री मंगलसिंह]

तो आपको टिकट पीछे मिलेगा। इसी तरह से नम्बर से किसी का नाम पहले, तो किसी का बाद में। कहने का मतलब यह कि किसी जगह स्कूलें आदि अभी खुल गई हैं तो दूसरी जगह बाद में खुल जावेंगीं। चार वर्ष में सब काम हो जावें यह तो सम्भव नहीं है। जहाँ स्कूलें आदि खुल गई हैं और जहाँ नहीं खुली हैं वहाँ अब खुलेंगी।

आपके खाद्य स्थिति के बारे में सब जगह उन्नति हुई है और इस प्रान्त में भी हुई है और जो सिंचाई के साधन और बिजली की उन्नति होगी तो मैं समझता हूँ कि यह प्रान्त भी किसी तरह से दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में पीछे नहीं रहेगा।

यह जो दूसरी बात ऐसी कही है जिसमें मैं समझता हूँ कि सदन में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जिसकी सहानुभूति या जिसका मत ऐसा नहीं हो कि जिस भाषा में प्रस्ताव रखा गया है न रख कर हमको हमारी राष्ट्र भाषा में ही रखना चाहिये था। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो मत नहीं हो सकते। श्रीमन् राजप्रमुख ने अंग्रेजी में जो भाषण दिया उसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने ऐसा करके हमारी भावनाओं की अवहेलना की हो या राष्ट्र भाषा से उनको कोई द्वेष हो या कोई दूसरा कारण हो। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं यह समझता हूँ कि वह शायद उनकी व्यक्तिगत कठिनाई होगी और हम सब आशा करते हैं कि आयन्दा इसका विशेष रूप से खयाल रखा जावेगा और ऐसी भूल फिर नहीं होगी।

एक बात प्रस्ताव के अनुमोदित करने वालों ने रखी और वह है हमारी सरहद की हिफ़ाज़त। आज दुर्भाग्य से अमेरिका ने जो पाकिस्तान के साथ शस्त्र-अस्त्र देने का समझौता किया है वह हमारे प्रान्त के लिये ही नहीं सारे देश के लिये खतरनाक है और इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अमेरिका ने हमें एक बार नहीं कई बार हानि पहुँचाने की कोशिश की है। अमेरिका ने, जब हमारे यहाँ अन्न की कमी थी उस समय अन्न नहीं दिया और जिस वक्त पंडित नेहरू अमेरिका गये थे उस वक्त उनका स्वागत करके उनसे यह कहलाना चाहते थे कि आप अमेरिका के बारे में अपने विचार बदल दें लेकिन उन्होंने जब चलते वक्त यह कहा कि हमारी जो नीति है वह ऐसी है कि हर एक विषय के महत्व को समझ कर ही उस पर फैसला होना चाहिये और हम ऐसा ही करेंगे। जब अमेरिका ने यह देखा तो उसने तरह-तरह की धमकियें दी। काश्मीर में शेख अब्दुल्ला को अपनाया और पाकिस्तान से बातचीत की, वह आप लोगों से छिपी नहीं है; जो असफल हुई और जो वह बात फेल हुई तब यह चाल सोची। हम अमेरिका को साफ कह देना चाहते हैं कि भारतवर्ष इस बात को कतई सहन नहीं करेगा। अंग्रेज एवं अमेरिकनों ने मुसलमान भाइयों को एक बार जिन्हा को साथ मिलाकर देश के दो टुकड़े करा दिये। आज भी फिर वे पाकिस्तान के भाइयों को फुसला कर कि उनको स्वतन्त्रता मिल जावेगी, उन्नति होगी, यह कह रहे हैं। उनको स्वतन्त्रता दी जावेगी, लेकिन दूसरे देशों की स्वतन्त्रता को खतरा अवश्य आता है। पाकिस्तान का यह कहना है कि हमने जो अस्त्र-शस्त्र लिये हैं वे हमारे लिये हैं और दूसरे देशों की भी हम हिफ़ाजत करेंगे। पाकिस्तान को, हम मानते हैं

[डा० श्री मंगलसिंह]

कि वह इस मामले में स्वतन्त्र हैं, कहीं से सामान मिले; किसी को कुछ कहने का हक नहीं है ; लेकिन पाकिस्तान को यह हक नहीं है कि वह किसी प्रकार ऐसा काम करे जिससे पड़ोसी देशों को नुकसान हो। चार मकान बने हुए हैं, आपको अपने मकान में रहने का पूर्ण अधिकार है लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप पेट्रोल डालकर अपने मकान में आग लगा दें जिससे दूसरे पड़ोसियों को मुसीबत हो जावे। यह हक किसी को नहीं होता। इसलिये पाकिस्तान को भी यह समझ लेना चाहिये लेकिन वह समझे या न समझे; हमको अपने घर की हिफाजत करना बहुत आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि यह प्रश्न सेन्टर का प्रश्न है लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह केवल सेन्टर का ही प्रश्न नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने हिफाजत के लिये पुलिस और फौज रखी है किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने मोहल्ले और घर की हिफाजत खुद नहीं करें। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस बात को देखेगी, लेकिन ६०० मील से ज्यादा हमारी सरहद पाकिस्तान से मिलती है, इसलिये हमको भी हमारे घर की हिफाजत करने का हक है। इस तमाम हिस्से पर फौज रखी जाती है तो पाकिस्तान यह कह सकता है कि यह क्यों रखी जा रही है लेकिन हमें अपने घर की हिफाजत करनी है हमसे कोई शिकायत नहीं कर सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये मैं इस बात को जोर से कहना चाहता हूँ कि हमको अपने प्रदेश की हिफाजत करने का पूरा प्रयत्न और प्रबन्ध करना चाहिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय उपाध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दो रोज से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं भी अपने विभिन्न दृष्टिकोण से अपने विचार प्रकट करता हूँ। मैं श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण को दो हिस्सों में बाँटता हूँ—

(१) प्रसाशन कार्य।

(२) निर्माण कार्य। (विराम)

माननीय मन्त्रीजी साहब सुनिए।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—मैं सुन भी रहा हूँ और नोट भी कर रहा हूँ।

श्री कंवरलाल जेलिया—जो निर्माण का कार्य हुआ है उस बारे में मैं यह मानूंगा कि राजस्थान ने भाखरा, जवाई, चम्बल योजना और छोटी-मोटी नदियों से सिंचाई की योजना का जो प्रबन्ध किया है उससे सिंचाई हो सकती है; इस माने में तो यह सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो शासकीय प्रवृत्ति है और जो पुनर्संगठन की योजना है वह इस बात को दिखाती है कि उनमें उपेक्षा की नीति एक तरह से काम करती है और उसमें वे डिविजन आते हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं। मैं एक-दो उदाहरण देकर बताऊं कि पुलिस और सहकारिता के पुनर्गठन में कोटा डिविजन की किस तरह से उपेक्षा की गई है? यह नहीं समझा जाना चाहिये कि

[श्री कंवरलाल जेलिया]

इस डिविजन का प्रतिनिधि नहीं है इसलिये इसकी उपेक्षा की जावे। हमारे चीफ मिनिस्टर भाषण देने में बहुत दक्ष हो सकते हैं। पुलिस और पुनर्गठन की चर्चा को बहुत सुन्दर तरीके से कह सकते हैं। मैं सदन का ध्यान जोशी लालबहादुर जी ने कहा उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ कि कोटा जिले से ब्यावर में दिन दहाड़े दिन के तीन बजे डाका पड़ा और उसका पता पुलिस अभी तक नहीं चला सकी। कोटा एक डिविजन है, फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर किस तरह से वहाँ डी. आई. जी. का हेड क्वार्टर रखना मुनासिब नहीं समझते? समझ में नहीं आता कि वहाँ से डी. आई. जी. का हैडक्वार्टर क्यों तोड़ा गया? क्या मैं यह समझूं कि कोटा के साथ इस सम्बन्ध उपेक्षा की जा रही है? कोटा की जनता भी सोच सकती है। यह पुनर्गठन का सवाल है। राजस्थान में एक डिविजन के साथ बड़ी मीठी बातें बना कर उनकी वाजिब आवाज को दबाया जावे तो मैं यह कहूँगा कि कोटा की जनता इसके लिए तैयार नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो आन्दोलन शुरू कीजिए।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह बिल्कुल गलत तरीका है आन्दोलन करने का।

(हंसी)

मैं उन साम्यवादी साथियों को, जो जनता को उभाड़ने की कोशिश करते हैं और कोटा के अस्पताल के नाम पर गलत तरीके से उन्हें (मजदूरों) उभाड़ा गया और जन-निर्माण के कार्य में राजनैतिक भावना को प्रोत्साहन देने की कोशिश की, कह देना चाहता हूँ कि यह एक घृणा की चीज है। यदि हमें देश का निर्माण करना है तो किसी बहकावे में हमें नहीं जाना चाहिए।

तो जिस तरह से सहकारी (कोऑपरेटिव) बैंक, अपेक्स बैंक के मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने कोटा के साथ उपेक्षा की और कोटा सहकारी बैंक के साथ अवहेलना की, वह सोचने का विषय है। जो सहकारी बैंक कोटा में कई वर्षों से चल रहा है, रिज़र्व बैंक ने जिसको मान्यता दी, उसकी उपेक्षा करके और कोटा की उपेक्षा करके जयपुर में अपेक्स बैंक बना दिया गया। इस निर्मित अपेक्स बैंक की पूंजी कोटा सहकारी बैंक से भी कम है। यह चीज है, अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान गवर्नमेंट के मन्त्री कर रहे हैं। वे इस बात को जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं? जयपुर में किस तरह से बैंक बना दिया गया इस सम्बन्ध में राजस्थान के मन्त्रीमण्डल के सामने मांग रखी गई, किन्तु उसका अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। रिजर्व बैंक को क्या रिपोर्ट पेश की यह तो वे ही जानें; किन्तु जयपुर में अपेक्स बैंक बना ही लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोटा के कोऔपरेटिव बैंक की हिस्सेदाराना पूंजी इतनी है कि जितनी राजस्थान सरकार ने जो अपेक्स बैंक बनाया है उसकी भी नहीं है। मैंने किसी भावना विशेष से आपका ध्यान नहीं दिलाया है। इसको किसी भी माने में लिया जाय। इससे पूर्व मैंने आपका ध्यान डी० आई० जी० हेड्क्वार्टर्स के कोटा से हटाये जाने के बारे में आकर्षित किया था। कोटा से हटाकर इसको जयपुर कर दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोटा से हटा देने पर राजस्थान सरकार को किस प्रकार की बचत हो गई है? डी० आई० जी० जब कोटा जावेंगे तो क्या टी० ए० और डी० ए० का खर्चा नहीं होगा? श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में......

Page No.62

[श्री कंवरलाल जेलिया]

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं पांच मिनिट और चाहूँगा। कोटा के लोगों को वैसे ही कम समय मिलता है।

(हंसी)

मास्टर भोलानाथजी आप सुनिये जरा।

(हंसी)

हमारे राजस्थान का सवाल है, दूसरे का नहीं। माननीय मन्त्री लोग जोर से बातें करके बीच-बीच में भाषण में बाधा डालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप रिलेवेन्ट बोलियेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया--मैं बोल रहा हूँ, जरा माननीय मन्त्री लोग ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष—Why do you disturb yourself ?

श्री कंवरलाल जेलिया--मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक माननीय सदस्य ने पुलिस की शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में किशनगंज और सांगोद का जो उदाहरण दिया है उससे मुझे इस बात का दुख है कि राजस्थान सरकार की पुलिस के सम्बन्ध में क्या नीति है ? पुनर्गठन का सवाल इतने संतोष का विषय नहीं है जितना कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी मान कर बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूँगा कि वे इस पर फिर से विचार करें।

अब मैं आपका सामुदायिक योजनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार और राजस्थान सरकार गाँवों का विकास भविष्य में किस तरह से करना चाहती है ? इस सामुदायिक योजना की ओर किसी मेम्बर ने सदन का ध्यान नहीं दिलाया। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए एस. डी. ओ. की इस विषयक क्या कार्य-पद्धति है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफीसर हैं वे एडवाइज़री बोर्ड बनाते हैं। वह महज दिखावा मात्र है। माननीय गुलजारीलाल जी नन्दा जब कोटा में आये तो मैंने उनके सामने भी इस सम्बन्ध में आवाज बुलन्द की। राजस्थान गवर्नमेन्ट इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित कर रही है। सामुदायिक योजनाओं में और एडवाइजरी बोर्ड में किस प्रकार का सामन्जस्य हो यह उन्हें नहीं मालूम है। यह केवल कागजों पर दिखाने की चीज़ नहीं है। जनता और ऑफिसर्स में परस्पर सहयोग चाहिए, उनका किसानों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। केवल शासकीय वृत्ति से किये जाने वाले कामों में जनता का सहयोग नहीं मिलता। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि आज की जो मशीनरी है, आज के जो ऑफिसर्स हैं वे हुकूमत करना चाहते हैं, जनता की सेवा नहीं करना चाहते। एक एस. डी. ओ. पुलिस के मार्फत किसानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अमुक मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, अतः अमुक काम करो। यह है सामुदायिक विकास योजनाओं की गति। राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि यदि

[श्री कंवरलाल जेलिया]

जन-सम्पर्क और जन-शक्ति को पनपाना है तो सरकारी मशीनरी की ऐसी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। कोई मिनिस्टर बीच-बीच में बोलकर जनता की ताकता को क्या दबाना चाहते हैं? जो मिनिस्टर साहब बार-बार बोल रहे हैं वे दो रोज कोटा में रहे, उन्होंने शिक्षा के लिए वहाँ क्या किया, जब कोटा के कॉलेज और स्कूलों के अध्यापक उनसे मिले। अध्यापकों ने पेट की आवाज को रखा तो माननीय शिक्षा मन्त्री ने उनको कहा कि क्यों ऊलजलूल बकते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लोक-कल्याण

(विपक्ष द्वारा "हियर हियर")

और शिक्षा का विकास इस तरह से हो रहा है? आप कोटा की जनता की आवाज को दबा नहीं सकते, किन्तु बीच-बीच में टोक सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

राजस्थान में पंचायत एक्ट..........

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर!

श्री कंवरलाल जेलिया—दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—Finished. Shri Bhogi Lal Pandya.

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, मैं तीन-चार बार बोलने के लिए खड़ा हुआ, किन्तु मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—आप फिर बजट के वक्त पर बोल लीजियेगा।

(विराम)

श्री भोगीलाल पंड्या।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय कुछ मित्रों ने अपने भाषण में पिछड़ी जाति पर खर्च होने वाली रकम के बारे में और इसी तरह बीकानेर के गेहूँ आन्दोलन के बारे में कुछ बताया। मैं उन्हीं के भाषणों में से कुछ बातें लेकर यह बताना चाहता हूँ कि उनका कहना ठीक नहीं है। बीकानेर आन्दोलन के प्रमुख सज्जनों में से एक विरोधी दल के मेरे माननीय मित्र ने आरम्भ में यह कहा कि "बीकानेर का आन्दोलन गेहूँ के नाम का आन्दोलन था, लेकिन उसके पीछे जनता के प्रति जो दुर्भावना और वहाँ के लोगों के साथ जो सोतेली मां का व्यवहार किया जा रहा था उस बात के असंतोष को वहाँ की जनता ने प्रकट करने के लिये ही वह मार्ग चुना था;" ये हैं वे शब्द आन्दोलन में भाग लेने वाले एक प्रमुख मित्र के।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—आप नाम बता दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता दूँगा।

श्री अध्यक्ष—जो व्यक्ति जिस कॉन्स्टिट्यूएन्सी से आये हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी का नाम बताने की परिपाटी है, नाम नहीं लिया जाता।

श्री भोगीलाल पंड्या— बीकानेर खास।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

मैं यह मान लेता हूँ कि सरकार यह सोचती है कि उसने गलत या सही कदम उठाया। लेकिन उसका स्पष्टीकरण तो होना था। लेवी ली अनाज बेचने के लिए और उस अनाज को बगैर टेन्डर कॉल किये ही बाहर भेज दिया गया, यह प्रमुख आन्दोलन कर्त्ता की शिकायत थी। शिकायत ही सुनानी थी तो उनको गेहूं का बहाना मिला। उनकी शिकायत यह भी थी कि वहां के लोगों को लेवी का लिया हुआ अनाज सस्ता क्यों नहीं दिया गया?

जिन सज्जनों ने ये दो एतराजात उठाये हैं उनको भलीभांति मालूम है और उनको कहा गया था कि आप बीकानेर के लिए १३) रुपये मन गेहूँ एफ. ओ. आर. जितना चाहें उतना ले लीजिये ताकि वहां आप १४), १४॥) व १५) रु. मन गेहूं भलीभांति बेच सकें। माननीय सदस्य का कहना था कि बात तो ठीक है किन्तु अब क्या करें? यहां कोई लेने वाला नहीं क्योंकि बाजार में गेहूं मिल जाता है। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं आप गेहूँ हमें १२) रुपये मन देते हैं जब कि आपने बारह रुपये मन खरीदा है?

दूसरी बात जो कही गई कि इसके लिए टेन्डर नहीं लिये गये और आगे चलकर आप ही कहते हैं कि टेन्डर राजस्थान के लिए था और बाहर अनाज़ कैसे भेजा। इसके लिए मैं विरोधी दल के मित्र को बतादूं कि यह बाहर कैसे भेजा?

कुं॰ श्री जसवन्त सिंह— वे विरोधी दल के तो अब हुए हैं पहले तो कांग्रेस के सदस्य ही थे।

श्री भोगीलाल पंड्या— (अपना भाषण जारी रखते हुए) वे जब बोले तब विरोधी दल से बोले थे, ऐसा मेरा ख्याल है।

मैं यह स्पष्टीकरण कर दूं, उन्होंने दो बातें कहीं, जो उनके वक्तव्य से खुद ही स्पष्ट हो गई है। आन्दोलन करने का इश्यू गलत था।

एक दूसरे माननीय मित्र ने यह बात बतायी है कि यह हमारा अधिकार है कि गेहूं बाहर भेज सकते हैं आदि आदि। मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता था, किन्तु जब मुझे पूछा गया था तब मैंने बता दिया था कि १३) रुपये मन में जितना गेहूं चाहिये उतना मैं एफ. ओ. आर. दिलवाने को तैयार हूँ......

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आपने तेरह रुपये की बात उस समय बतायी थी? क्या सरकार ने इस प्रकार का ऐलान इस आन्दोलन के शुरू होने से पहले कर दिया था और आप अब यह करने के लिए तैयार हैं कि १३) रुपये मन एफ. ओ. आर. देने के लिए तैयार हैं?

श्री जयनारायण व्यास—आप एफ. ओ. आर. का मतलब नहीं समझे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एफ. ओ. आर. का बहाना लेकर बात छिपायी जाती है।

श्री भोगीलाल पंड्या--अब तो मैं नाम बता सकता हूँ। मैंने आपको ही बताया था १३) रुपये मन गेहूँ एफ. ओ. आर. में देने के लिए तैयार हूँ; जितना भी आप चाहें देने के लिए तैयार हूँ, आप किसी व्यापारी को तैयार कीजिए। यह बात मैंने आन्दोलन चला उसके पहले कह दी थी, आपकी गिरफ्तारी होने के पहले मैं बता चुका था...

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वह वक्तव्य आप सदन की मेज पर रख सकते हैं? वह आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

वक्तव्य के टेबल पर रखने की कोई बात नहीं है, यह वक्तव्य बहुत-से समाचार पत्रों में निकल चुका है; स्वयं मेरे माननीय मित्र को भी यह पता था। स्वयं माननीय मित्र ने बताया था कि इस तरह से लड़ना था, आन्दोलन करना था; लेकिन इश्यू गलत ले लिया गया। इस पर क्या हो सकता था? वहाँ के लोगों को जिस किसी भी तरह समझा-बुझा कर, बातचीत करके समाप्त कराया गया; यह एक अलग बात है। माननीय मित्र ने खुद ने माना है कि इसको अनावश्यक इश्यू बना दिया है।

साथ ही आपने यह भी बतलाया कि दो वर्ष पहले ११।) रु, १२) रुपये मन गेहूँ खरीदा गया जब कि बाजार भाव १६) रुपये मन था। मुझे यह उनके मुँह से सुनकर आश्चर्य हुआ। गवर्नमेंट ने कभी भी इन दो या तीन सालों में कभी भी ११।) रुपये मन गेहूँ नहीं खरीदा। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने किस प्रकार यह बात इस सदन के फ्लोर पर कह दी। अभी जब कि अनाज खरीदा गया उस समय भी १६) रु. का भाव था। गवर्नमेंट को अनाज खरीदना था। सरकार ने किसानों से लेवी नहीं ली। व्यापारियों से लेवी ली गई उस समय भी गेहूँ का भाव करीब करीब वही था। उसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारी लोग अपने आप मन से सरकार को गेहूं देने लगे। विवश होकर व्यापारियों से लेवी का अनाज लेना बन्द करना पड़ा और बन्द कर दिया गया। साथ ही आपने बताया कि ११।) रु० मन गेहूँ लेकर १७) रुपया मन के हिसाब से वेचने की व्यवस्था की गई, उस पर न किसी प्रकार का मुनाफा लिया गया और न सरकार का आयन्दा इस प्रकार मुनाफा कमाने की नीयत है।

आगे चलते हुए आपने अपने भाषण में कहा कि इस तरह से गेहूं की सप्लाई में गवर्नमेंट को काफी रुपये का घाटा हुआ। सरकार तो हमेशा जनता को सस्ता अनाज देने के लिए अपना नुक्सान भी सहन करती है, जनता को सस्ता अनाज देना अपना कर्त्तव्य समझती है। पिछले दो वर्ष हमारे यहां भीषण अकाल के निकल गये किन्तु कहीं से भी अनाज की कमी की शिकायत नहीं आई। जिस समय गेहूँ का भाव २१) रुपये मन था सरकार ने २७) रुपये मन के भाव से जनता को दिया। इस सम्बन्ध में न बीकानेर से शिकायत आई, न राजस्थान के अन्य किसी कोने से शिकायत आई, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। जहाँ कहीं भी अनाज मँहगा था वहाँ हमने १७) रु. मन के भाव से गेहूँ दिया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— आपने जो अनाज सड़ाया है, उससे जो नुक्सान हुआ उसका क्या हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या— गवर्नमेंट के पास न किसी प्रकार का सड़ा हुआ अनाज था और न है ।

(विराम)

आपने बताया कि पंजाब में जहाँ गेहूँ पैदा होता है, वहाँ की मिल को नहीं दिया गया और राजस्थान सरकार से दिया गया । वहाँ पंजाब में इन्डीजीनस गेहूँ का मैदा या सूजी बनाने की पंजाब सरकार की स्वीकृति नहीं थी इसलिये नहीं दिया गया । यह कोई कारण नहीं था, नहीं दे । राजस्थान सरकार को मन्जूरी मिली थी, इसलिये दिया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभाव ग्रस्त ४१२ गाँव हैं, वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा कि आप जाकर वहाँ देखें । हमारी सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें खोल रखी हैं । वहाँ सरकार का अनाज नहीं बिक रहा है । आज राजस्थान के कौने-कौने में सस्ता और अच्छा अनाज मिल रहा है । आज वहाँ के लोगों में सन्तोष है । सरकार द्वारा सस्ते अनाज की व्यवस्था कर दी गई है ।

संक्षेप में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बीकानेर का आन्दोलन केवल आन्दोलन करने के लिए खड़ा किया गया, वह किसी खास कारणवश शुरू किया गया था । एक हमारे दूसरे माननीय मित्र ने बतलाया कि उनको तो लड़ना था, इश्यू गलत था, वहाँ किसी प्रकार के अनाज की कमी नहीं है । आज भी बीकानेर में १४) रुपये से लेकर १५।।) रुपये मन तक नया गेहूँ आसानी से मिलता है । सरकारी दुकानों पर कोई अनाज लेने वाला नहीं मिलता है । इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप जब महँगा अनाज देते हैं तो कौन लेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार अपना सब हिसाब-किताब लगा कर अनाज का भाव निर्धारित करती है । इस हिसाब के बीच सरकार की जो नीति रहती है वह यह कि जनता को सस्ता और अच्छा अनाज मिल सके । बाजार के भावों को सन्तुलित रखने के लिए सरकार अपने पास बफर स्टॉक रखती है ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि शिड्यूल ट्राइब्ज़ आदि को जो सहायता भारत सरकार से मिलती है, वह उन पर खर्च नहीं की जाती है । मेरा इस विषय में यह निवेदन है कि जिस काम के लिए भारत सरकार से हमें सहायता मिलती है, वह रुपया उसी काम में खर्च होता है । अगर वह रुपया इधर-उधर के काम में खर्च हो जाता है तो अकाउन्टस् वाले ही पहले एतराज कर देते हैं । उन्होंने न मालूम यह कैसे कहा कि शिड्यूल कास्ट पर एक पाई भी खर्च नहीं की जाती है ।

श्री गोपीलाल यादव—Only about Backward classes.

श्री भोगीलाल पंड्या—बैकवर्ड क्लासेज़ में शैड्यूल ट्राइब और शैड्यूल कास्ट्स भी आ जाती हैं।

श्री गोपीलाल—This is Confusion.

श्री भोगीलाल पंड्या—बैकवर्ड क्लास के चार भेद हैं :

(१) शैड्यूल ट्राइब, (२) शैड्यूल कास्ट,

(३) विमुक्त जाति (एक्स क्रिमिनल ट्राइब) और (४) अदर बैकवर्ड क्लासेज़।

लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लाखों रुपया जब शैड्यूल कास्ट पर खर्च हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं खर्च हो रहा है, केवल छात्रों की छात्रवृत्ति पर कुछ खर्च किया जा रहा है।

साथ ही यह भी बताया गया है कि केन्द्र के कोई पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी हैं, वे कहते हैं कि राजस्थान सरकार तो कभी पैसा देती ही नहीं, हम से कोई माँगता ही नहीं। और मैं कहता हूँ इन पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब को इतना भी पता नहीं कि हम तो काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, काफी पैसा लगा चुके हैं और यह कहते हैं कि हमको जो ४० लाख रुपये देते थे उसमें से २० लाख तो मद्रास ले गया, राजस्थान ने कुछ नहीं लिया। मैं कहता हूँ सेन्टर से करोड़ों रुपया इसके लिए निकलता है और राजस्थान को जितना मिलता है, उतना हर हालत में उसको मिलता है।

श्री गोपीलाल यादव—On a point of information, Sir, वहाँ वजीफे से मेरा मतलब था। वजीफे के लिए ४० लाख रुपये रक्खे गये थे।

श्री भोगीलाल पंड्या—वजीफा शब्द कहीं भी भाषण में होता तो मैं समझता। वह तो बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए रक्खा है, पर राजस्थान ने उनकी सूची नहीं भेजी, इसलिए राजस्थान को नहीं मिल रहा है; यह कहा जा रहा है। जहाँ कि भारत सरकार के अधिकारी यह कहते हैं कि राजस्थान को जितना मिलता है उतना तो वे ले ही जा रहे हैं, पर फिर भी वे राजस्थान वाले बार बार काफी प्रयत्न करके अधिक रुपया ले जाने की कोशिश करते हैं। खैर।

आपने आगे बताया कि कोई रिपोर्ट नहीं दी गई बैकवर्ड क्लासेज़ की। मैं बताऊँ इसके लिए कि गाडगिल कमेटी के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें यह सब विगत दी गई है और इसकी एक एक प्रति माननीय सदस्यों को भी मिली है। भारत सरकार को तो पहले भेजी जा चुकी है। उसमें भी विगत थी कि ३ लाख १६ हजार शेड्यूल ट्राइब—

१७ लाख शेड्यूल कास्ट

६८ लाख अदर बैकवर्ड क्लासेज़

[श्री भोगीलाल पंड्या]

यह राजस्थान की जन संख्या का साठ प्रतिशत है। यह भारत सरकार को राजस्थान सरकार बहुत टाइम पहले ही भेज चुकी है। इसलिए सम्भव है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की भूल रह गई है कहीं या उनको पता नहीं पड़ा है और इसी कारण गलतफहमी रह गई है और अगर यह गाडगिल कमेटी के सामने दी गई रिपोर्ट, जिसकी एक प्रति माननीय सदस्य को भी दी गई है, नहीं पढ़ी है माननीय सदस्य ने तो मैं निवेदन करूंगा कि वे यह रिपोर्ट भी पढ़ लें। राजस्थान सरकार बराबर ऐसा लेने की कोशिश करती है। यही मुझे कहना था - और मैं आशा करता हूँ कि जो गलतफहमी हो गई है वह निकल जावेगी।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के प्रति धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया था उस प्रस्ताव के सिलसिले में काफी दिलचस्प भाषण हुए हैं और साथ ही साथ काफी गरमा-गरम भाषण भी हुए हैं।

मैं समझता हूँ कि ये भाषण उस मनोवृत्ति के द्योतक हैं जो मनोवृत्ति भिन्न-भिन्न दलों के लोग अपने मस्तिष्क में रखते हैं। मेरा खयाल है कि जहाँ तक भाषणों से सम्बन्ध है, जैसी माननीय राजप्रमुख ने हमको सलाह दी थी, हमें कुछ संयम रखना पड़ेगा, कुछ परम्पराएं निकालनी पड़ेंगी और कुछ मनोवृत्ति भी बदलनी पड़ेगी। मैं खासतौर पर यह कहूँगा कि अगर सरकार को कुछ गरम बातें कही जायें, कुछ गलत बातें भी कही जायें और उसके विरोध में बहुत सी अन्य बातें भी की जावें तो मैं ऐसा मान लूंगा कि यह जो एक बड़ा कारखाना यहाँ पर है उसकी एग्जोस्ट पाइप (exhaust pipe) से कुछ स्टीम निकल रही है, उसे निकलने दें। और अगर वे सरकार पर ही इतने खफा हो जावें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

लेकिन मैं यह परस्पर में छींटाकशी की जो भावना दिखने में आती है, माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि उस छींटाकशी को रोका जावे। यह आपकी मारफत सदन से भी मैं अपील करूंगा।

मैं खास तौर पर राजा मानसिंहजी के भाषण की तरफ, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ जिस भाषण में एक वर्ग के प्रति घृणा प्रकट की गई थी और ऐसे शब्द कहे गये थे जो किसी विधान सभा के सदस्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

मैं अब भी यह कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि अगर माननीय सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनकी बहादुरी इसी बात में है कि उन शब्दों के लिए उस वर्ग से क्षमा-याचना करे और आपसे यह प्रार्थना करें कि वे शब्द निकाल दिये जावें कार्यवाही से। नहीं तो मैं यह प्रार्थना करूंगा, श्रीमन् (अध्यक्ष महोदय), आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उन शब्दों को कार्यवाही में न रहने दें। ऐसे शब्द हमारी विधान सभा को जो प्रोसीडिंग्ज़ हैं उनके लिए एक कलंक के तौर पर होंगे।

दूसरी बात.........

श्री जसवन्त सिंह— मैंने भी इसके लिए ऐतराज किया था, पर उसको सुना नहीं गया।

श्री अध्यक्ष— मैं कुछ कहदूं। दुर्भाग्य से मैं उस वक्त यहां नहीं था और माननीय उपाध्यक्ष थे और वह माननीय सदस्य, जिनका कि जिक्र हो रहा है मेरे पास चेम्बर में आये थे और उन्होंने कहा कि, "मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, मैंने कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द कह दिये जिसके लिए मुझे स्वयं को दुःख है।" मैंने कहा कि यह सारी बात आप लिखित में दीजियेगा। लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने अभी तक लिखित में नहीं दिया।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— दूसरी बात, एक भाषण जो श्री भैरोंसिंहजी का हुआ था, मैं उसकी तरफ भी, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाये। अगर वे कांग्रेस से घृणा करते हैं तो यह उनका हक है। उनको हक है कांग्रेस से घृणा करने का क्योंकि उनकी मनोवृत्ति कांग्रेस की मनोवृत्ति नहीं है। कांग्रेस का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को मानने की मनोवृत्ति उनकी नहीं है; कांग्रेस का जो आदर्श है उसके आदर्श को मानने की उनकी मनोवृत्ति नहीं है इसलिए उनका हक मैं मानता हूँ। लेकिन जो लोग कांग्रेस की तरफ यहां आयें या कांग्रेस को छोड़कर दूसरी तरफ जावें तो यह जायें या आयें या जाने का इरादा करें, उनके बारे में ऐसे अनुचित शब्द कहना यह कोई शोभा की बात नहीं है और इस तरह के शब्दों का ....

श्री भैंरूसिंह— (वि. सं. १६) On a point of personal explanation, Sir,—

श्री अध्यक्ष— Order please !

श्री भैंरूसिंह— वे कौन से शब्द हैं ?

श्री जयनारायण व्यास— मेरे पास उनका भाषण भी मौजूद है और मेरा ऐसा खयाल है कि मुझसे ज्यादा अपने भाषण को वे खुद जानते हैं और अगर अपने शब्दों को नहीं जानते तो मुझे अफसोस है।

श्री भैंरूसिंह— मेरे खयाल से व्यक्तिगत आरोप मैंने नहीं लगाये।

श्री जयनारायण व्यास— मैंने व्यक्तियों का नाम नहीं लिया था। सिंगुलर और प्लुरल में ग्रामर के हिसाब से फरक है। और यह आरोप कि उनको कोई प्रलोभन है या लोभ है और जरा बहुत लाइट वर्ड्स में इसका हमारे लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन भी समर्थन सा करदें तो यह ज़रा अच्छा नहीं रहता है।

हमें अच्छी परम्पराएं बनानी हैं। अब मैं भाषण के जो मुख्य-मुख्य अंश हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ।

मैं सदन से सबसे पहले क्षमा माँगता हूँ। क्षमा इस बात के लिए कि राजप्रमुख का भाषण इस बार भी हिन्दी में नहीं हो सका।

(हियर-हियर)

[श्री जयनारायण व्यास]

इसके लिए जो राजप्रमुख के बारे में कहा गया है कि उनको हिन्दी का शौक नहीं है, अंग्रेजी का शौक है और भी इसी तरह की कई बातें कही गई हैं तो जो भी बातें इस बारे में कही गई हैं वे ठीक नहीं हैं। यह सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ इसलिये कि वह भाषण······

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--क्या हम यह समझें कि आपने उन्हें कहा कि अंग्रेजी में भाषण दें।

श्री जयनारायण व्यास--मैं बोल ही रहा हूँ, मैंने अभी समाप्त नहीं किया है। इसमें कोई शक नहीं कि भाषण हिन्दी में हो। इसका मैंने राजप्रमुख से उल्लेख भी किया था और उनकी भी तैयारी थी। लेकिन इस भाषण की तैयारी में कुछ समय लग गया और दुर्भाग्य से हिन्दी के शब्दों को पसन्द करने में बड़ी दिक्कत सामने आई और राजप्रमुख के लिए, जिस तरह की हिन्दी आजकल बन रही है और जो सरल हो नहीं सकी समय को कमी की वजह से, उस तरह की हिन्दी में भाषण देना मुश्किल रहा और फिर अभी तक अंग्रेजी भाषा भी १५ वर्ष के लिए मान्य है इसलिए उन्होंने उस रियायत का फायदा इसलिये उठाया कि हम सरल हिन्दी में उस भाषण का समयाभाव से अनुवाद नहीं दे सके। हम आगे इसके लिये कोशिश करेंगे। कभी-कभी स्थितियां ऐसी आजाती हैं और स्थितियां आ नहीं जाती हैं, पैदा की जाती हैं।

आज जिन परिस्थितियों के कारण हमें दूसरी तरफ ध्यान देना पड़ता है, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूँ जिनसे दूसरे कामों की तरफ हमारा ध्यान खिंच जाता है, और उसमें हमारे माननीय सदस्यों में से बहुत सों की जिम्मेदारी होती है, तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें दूसरे कामों में उलझा रखा है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण हिन्दी में भाषण नहीं हुआ लेकिन इसके नहीं होने से कोई इतनी बड़ी खराबी नहीं थी और इसका कारण अंग्रेजी के प्रति मोह नहीं था और इसमें हाउस का अपमान करने की बात नहीं थी।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने यह उल्लेख किया था कि सब परम्पराएं बहुत अच्छी बन रही हैं और उन अच्छी बनने वाली परम्पराओं की एक बात यह कही थी कि हिन्दी में भाषण नहीं हुआ इसलिए दो-तीन व्यक्ति उठ कर चले गये। मैं समझता हूँ कि यह बेसब्री की परम्परा कोई अच्छी परम्परा नहीं है। उनको अगर कुछ कहना है तो जिस तरह से इसको विरोधी पक्ष के नेता ने नापसन्द किया, कटु भाषा में भी कहा और कहीं कहीं तो राजप्रमुख के लिए कुछ शब्द ऐसे कहे जो उनके अन्दर की भावना को बताते थे; फिर भी उनको कहने का हक है, वे कह सकते हैं। उठ कर चला जाना ठीक नहीं था। भाषण तो छपा हुआ था ही, फिर भी उनको मिल गया। अंग्रेजी में भी मिल गया, हिन्दी में भी मिल गया। यह रोष की चीज अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी परम्परा से काम किया जा सकता है।

अब मैं मुख्य विषयों की तरफ, जो इस भाषण में आये हैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। विरोधी पक्ष के नेता के पहले श्री मथुरादास जी माथुर ने प्रस्ताव रखा था और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही थीं, कुछ पक्ष में कही थीं और कुछ विपक्ष में कही थीं; कुछ टीका टिप्पणी भी की थी; लेकिन जहां तक लॉ एन्ड आर्डर, शांति और व्यवस्था, का ताल्लुक है कुंवर

[श्री जयनारायण व्यास]

जसवन्तसिंहजी ने, जो कि मेरे मित्र हैं विरोधी पक्ष के नेता ही नहीं, बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने कुछ बढ़ा-चढ़ा कर वे बातें कहीं, या कहते वक्त गम्भीरता नहीं रखी। मुझे कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने एक बात बताई कि साहब, कुछ डाकू मारे गये या कुछ चोरियां कम हो गई हैं उससे मामला हल नहीं होता है, असन्तोष तो कायम है। और उन्होंने मिसाल दी कि डा० काटजू जब बीकानेर में आये तो कुछ लोगों ने प्रदर्शन किये कि गोहत्या बन्द करो, कुम्भारामजी के खिलाफ बोले। यह बात ठीक है। मैं भी उस वक्त था। मैं इस बात को मानता हूँ। जगजीवनरामजी आये थे तो उस वक्त भी प्रदर्शन किया, उनसे कहा गया कि उन्हें घुसने नहीं देंगे। मैं इस बात को नहीं कह सकता। कोई प्रदर्शन तो देखने में आया नहीं। कुछ जुलूस निकाल लिया हो। यादवजी उस वक्त थे।... -

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—वे जुलूस में नहीं आये थे। स्टेशन से उन्हें शहर में डूंगर कॉलेज के छात्रों ने नहीं जाने दिया।

श्री जयनारायण व्यास—मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि छात्रों ने कुछ किया और उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा करदी और कहा कि हम नहीं जाने देंगे, हम विरोध करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। छात्रों के लिए ऐसा कुछ करना बड़ी बात नहीं है। अब भी कुछ एलीमेंट हैं, आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यह आपकी बात है। यह बात अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकूंगा। दूसरी तरफ की बैंचों पर बैठे हुए सदस्यों से आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति आता है अपने शहर में तो छात्र ऐसा करेंगे इस नाम पर या उस नाम पर या कोई मिनिस्टर आता है तो कोई गड़बड़ करनी चाहिए ? इस पर यदि मिनिस्टर जान बूझकर नाराजी जाहिर नहीं करे या सरकार कोई ऐसा कदम उठाकर उनका दमन नहीं करे तो उस में सरकार की कमजोरी नहीं होती है बल्कि सरकार जानती है कि यह प्रजातन्त्र के प्रादुर्भाव की शुरूआत है और वह प्रजातन्त्र के विरोधीतत्व अब भी मौजूद हैं, बीकानेर में भी मौजूद हैं, वह प्रजातन्त्र की हर एक कार्यवाही को, प्रजातन्त्रीय सरकार के हरेक व्यक्ति को, प्रजातन्त्र के हरेक सिद्धान्त को खत्म करने के लिए कुछ भी कारवाही करेंगे। मगर वे कार्यवाही कर सकते हैं और बीकानेर में भी प्रदर्शन हो सकता है और इस कारण थोडा असन्तोष रह सकता है, तो उसके हेतु सरकार के लिए कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो उन लोगों के लिये होनी चाहिए जो वहाँ रहते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसी बातों को नहीं रोक सकते हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर सकते हैं तो ऐसे असन्तोष को सरकार नहीं रोक सकती है। मैं जानता हूँ कि ऐसा असन्तोष वास्तव में होता नहीं है, मगर पैदा कर दिया जाता है। मैं जानता हूँ किकहीं कहीं कुछ पैसे देकर कुछ भडेतियों को आगे कर दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो क्या सरकार उन भडेतियों पर लाठी चलाये, गोली चलाये ? तो इस तरह सरकार शक्ति का प्रदर्शन न करके कई बार ऐसी चीजों को बर्दाश्त करती है। हमें इस नये प्रजातन्त्र को पनपाना है, दमन के जरिये नहीं पनपाना है; बल्कि धीरे-धीरे पनपाना है। हमें उपद्रवों से बचाकर उस प्रजातन्त्र को पनपाना है जिस प्रजातन्त्र को कायम करने के लिए उन लोगों ने जो आज सरकारी बेन्चों पर बैठे हैं थोडा सा कष्ट उठाया है। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि सन् ४७ के अन्दर जब

[श्री जयनारायण व्यास]

हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो कई लोगों ने खून-खच्चर की एक नीति शुरू की थी और हिन्दू मुसलमानों को आपस में भड़का कर बुराई की तरफ प्रेरित किया था, अशान्ति पैदा की थी; ताकि वे लोगों से कह सकें कि यह प्रजातन्त्र बहुत बुरी चीज है; ऐसा होने पर अशान्ति होगी। जब कोई नई चीज की शुरूआत होती है तो ऐसी बातें होती ही हैं, यह एक प्रॉसेस है डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट का। इस प्रॉसेस से बच कर हम नहीं निकल सकते। इस प्रॉसेस को बरदाश्त करना पडेगा। अपने यहां ही देख लीजियेगा कि जब असेम्बली चालू ही हुई थी तो यहां कोई न कोई ऐसी क्रिया हुई ही। कभी किसान आ गये तो कभी कोई मजदूर आ गये और धरना दे दिया और कहा कि हम आने नहीं देगें। यहां दरवाजे के सामने सोगये। इस तरह का कुछ न कुछ काम होता ही था; प्रजातन्त्र के विरोधी तत्व इसका नेतृत्व करते ही थे। यह करके उन्होंने कहा ही था कि असन्तोष है, अव्यवस्था है, यह है, वह है, मिनिस्टर लोग पिछले दरवाजे से आ गये, आदि आदि बहुत सारी बातें कही थीं। यह होता ही है, क्योंकि अब तक लोगों को पता नहीं है कि अभी भी इस हिन्दुस्तान के अन्दर वे तत्व मौजूद हैं जो प्रजातन्त्र के दुश्मन हैं, वे अभी खत्म नहीं हुए हैं। प्रजातन्त्रीय सरकार उन्हें दमन के जरिये खत्म नहीं करना चाहती है बल्कि प्रजा को समझा कर इन तत्वों को समाप्त करना चाहती है। उन्हें समझा कर, डिटेल्स में समझा कर, इनकी कार्यवाहियों को समझा कर, इनकी नीति को समझा-कर खत्म करना चाहती है (हंसी) और कुछ समय के बाद वह उनको समझ जायगी, प्रजा आप ही आप। धीरे धीरे ज्यों ज्यों लोगों की समझ में आयेगा यह बातें मिटती जायगी। यह तरीका प्रजातन्त्र स्वीकार करता है। इसलिये यह कहा जाता है कि अभी अशान्ति मौजूद है। इसके मायने यह नहीं कि जो बच्चे हैं, जो बेचारे निर्दोष हैं जो अज्ञानी हैं उन पर दमन करे। हमारा एक प्रॉसेस है और हम उस प्रॉसेस में से गुजरेंगे।...

श्री वेदपाल त्यागी—दोषी को तो मारना चाहिए।

श्री जयनारायण व्यास--दोषी तो पीछे रह जाते हैं (हंसी)

मैं बीकानेर की बात कह रहा हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास-- क्या वहां के डी. आई. जी. पी. से नारे लगवाए गये, यह बात आपके ध्यान में है ?

श्री जयनारायण व्यास— यह बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसी टीका का नोटिस लेना नहीं चाहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास— आई विटनेस (eye witness) मौजूद हैं।

श्री जयनारायण व्यास— आप आई विटनेस (eye witness) कैसे पैदा कर सकते हैं इसको मैं जानता हूं।

[श्री जयनारायण व्यास]

हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि आन्दोलन सफल हुआ और उसमें सरकार को मात मिली । बड़े अच्छे शतरंज के खिलाड़ी के शब्दों में उन्होंने आन्दोलन का वर्णन किया । गेहूँ की क्या स्थिति थी, आन्दोलन क्यों शुरू हुआ, ये सब बातें मेरे साथी श्री भोगीलालजी ने बतादी है । अब सरकार को कैसे मात मिली है, यह मैं बताना चाहता हूं । मात मिली है और बराबर मिली है क्योंकि जिस समय आन्दोलन शुरू था उस समय सरकार ने यह तय किया कि यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कदम उठाया है । कुंवर साहब उस समय जयपुर में थे और खजांन्चीजी बम्बई में थे । बागड़ीजी ने लोगों को समझाया और उनसे अपील की और जब लोगों ने यह मंजूर किया कि हम हड़ताल तोड़ देंगे तब लोगों को छोड़ दिया गया । इसको वे मात समझते हैं । एक सप्ताह के बाद जब लोग छोड़े गये तो उनको फूलों के हार पहनाये गये । उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हारे हुए सिपाही माला नहीं पहनते । ऐसे भी आदमी मिल सकते हैं जो यह कहें कि हारे हुए माला नहीं पहनते । जब लोग छोड़े गये तो उनके स्वागत की व्यवस्था कर डाली गई । बराबर स्वागत होना चाहिए । आखिर दो–चार दिन तो वे जेल में रहकर ही तो आये थे । मैं औरतों में भी मैं बहादुरी पैदा करना चाहता हूँ । बीकानेर से अनाज बाद में बाहर निकला है लेकिन बाद में भी किसी ने उसे निकलने से रोका नहीं । कुंवर साहब ने कहा कि वाजिब आन्दोलन था । जब वाजिब आन्दोलन था तो बाद में जब अनाज निकला तब तो सत्याग्रह करके उसे रोकते । क्या धरा था जयपुर की आबहवा में ? इस चीज को समझना चाहिये था । अपने साथियों को तार देना चाहिए था ....

कुं. श्री जसवन्त सिंह— आप मुझे पूछते हैं ? लेकिन आपके जयपुर की आबहवा से मुझे बीकानेर की आबहवा ज्यादा जंचती है ।

श्री जयनरायण व्यास—लेकिन आन्दोलन के दिनों में अच्छी नहीं लगती है । आन्दोलन के पहिले और बाद के दिनों में अच्छी लगती है । उन दिनों में बीकानेर जाने की इच्छा नहीं थी । बाद में शायद आपने पैसा दिया उसके लिए हरिकृष्णजी आपको धन्यवाद दे सकते-हैं । लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान में धन्यवाद नहीं दिया ।

अब मैं डाकुओं के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ । श्री यादवजी ने यह बात कही कि अभी तक डाकू मौजूद हैं । मैं भी स्वीकार करता हूँ कि अभी तक डाकू मौजूद हैं । मैंने यह कभी नहीं कहा कि सब डाकुओं को खत्म कर दिया है । मैंने तो यह कहा था कि अधिकांश डाकू या तो खत्म हो गये हैं या गिरफ्तार कर लिये गये हैं या सरेन्डर हो गये हैं या छिप गये हैं । फिर भी कभी कभी घटनाएं होती हैं, इसको मैं मानता हूं । अब वे उनकी लिस्ट पूछते हैं कि डाकुओं की लिस्ट क्या है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि हमको प्रश्न पूछा जाय कि सिविल सर्विस में एस. डी. ओज़. की लिस्ट बताई जाय तो पांच दिन लगा कर लिस्ट तैयार करानी पड़ेगी । पर डाकू तो रजिस्ट्रेशन कराते नहीं । आज कोई भला आदमी है वही कल डाकू हो सकता है । मैं जेल में रहा हूँ । डाकुओं के साथ रहा हूँ (हियर-हियर)

श्री गोपीलाल यादव—मुझे शायद गलत समझा गया है। मैंने तो डकैतियों की संख्या पूछी थी, न कि डाकुओं की।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जेल में डाकुओं के साथ रहने से क्या उनका असर आप पर नहीं हुआ?

श्री जयनारायण व्यास—बराबर असर हुआ इस बात का कि डाकुओं को कैसे टेकल (tackle) किया जाय। इसी तरह कम्युनिस्टों के साथ रहने से यह असर हुआ कि उनको कैसे टेकल किया जाय।

अभी शाहबाद के बारे में श्री लालबहादुरजी ने कहा, उसको मैं मानता हूँ। वे घबड़ा जाते हैं दो-चार डकैतियों को देखकर ही।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—वे शायद बच्चे हैं।

श्री जयनारायण व्यास—(भाषण जारी रखते हुए) क्यों कि इतनी डकैतियाँ वहां पहले कभी नहीं हुईं। लेकिन शाहबाद की स्थिति दूसरी तरह की है। वह मध्य भारत और राजस्थान की सीमा के पास है। इधर से पहले हमने कॉन्सेन्ट्रेट किया था रेगिस्तान के ऊपर। रेगिस्तान के डाकू कुछ पाकिस्तान चले गये, कुछ मारे गये और कुछ ने सरेन्डर कर दिया। तब अरावली पर कॉन्सेन्ट्रेट किया। अब भी एक दो दल वहाँ हो सकता है। कुछ वहां से भाग गये। एक तो हाल ही में कलकत्ते में पकड़ा गया था। जगमन को खत्म किया गया, शंकर ने सरेन्डर किया और भी कइयों ने सरेन्डर किया। कुछ मध्य भारत में भाग गये, मध्यभारत की पुलिस उनका चतुराई से पीछा कर रही है। जो हिस्सा मध्यभारत और राजस्थान के किनारे पर है उनमें कभी कभी ये आते हैं और चोरी करके या डाका डाल कर चले जाते हैं। इधर चोरी करते हैं तो उधर चले जाते हैं और उधर करते हैं तो इधर आ जाते हैं। जो बच गये हैं उनको मध्य भारत और राजस्थान दोनों की पुलिस के मेल जोल से जल्दी ही खत्म किया जायगा।

कोटा डिवीजन से डी० आई० जी० पी० का हैड क्वार्टर उठा देने के बारे में भी आपने कहा। इस बारे में मेरी अर्ज यह है कि डी० आई० जी० पी० के दफ्तर या कलम से तो डाकू मरते नहीं हैं। डाकू मरते हैं पुलिस फोर्स से और वह जिला कोटा में काफी रखी गई है। कोटा डिवीजन का क्षेत्र बहुत छोटा है। शायद जयपुर डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा होगा। डी० आई० जी० पी० का हैड क्वार्टर उदयपुर में रहते हुए भी वे बराबर कोटा का दौरा करेंगे। एक डी० आई० जी० पी० हमने आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी के लिये रखा है, इसलिये कोटा से कमी की गई है। यदि कोटा में बढ़ाने की जरूरत हुई तो हम बढ़ा सकते हैं; पर फिलहाल वहां डी० आई० जी० पी० की जरूरत नहीं है। एक दो चोरी या डकैती से कभी शान्ति या सन्तुलन नहीं खोना चाहिये, यही अर्ज करना चाहता हूँ।

खजान्चीजी ने तो सारे राज्य को गुण्डा राज्य और भ्रष्टाचार का राज्य कह दिया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—वे आपकी पार्टी में रह आये हैं इसलिये साफ देख आये हैं।

श्री जयनारायण व्यास—किस कदर वे हमारी पार्टी में आये और अब आपके पक्ष में रहेंगे। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारी मदद की है वैसी ही वे आपकी भी मदद करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे अन्दर की बातें देख कर आये हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है वे अन्दर की बातें देख कर आये हैं। जिस तरह के डिसिप्लिन की बात कांग्रेस में है वे शायद उनके लिये ठीक नहीं हैं। मुमकिन है अब वे कॉम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर की बातें देखें।

चोरियों के बारे में यादवजी ने भरतपुर के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर लोग मिलते नहीं हैं और सुनवाई नहीं करते हैं। मिलते नहीं हैं, यह क्या बात है? यह बात मुझे ठीक नहीं जंचती है। मुझे खुद को भरतपुर, डीग, नगर जाने का और इस इलाके में घूमने का मौका मिला था एक जगह तमाखू के मामले में काफी गड़बड़ हुई थी और उससे फायदा उठाना हमारे भाई चाहते थे। मैं खुद गांवों में गया हूँ और वहां के लोगों से बातचीत की है। दूसरे मिनिस्टर भी जाते है। ऐसी सुनी-सुनाई बात पर यादवजी जैसे गंभीर आदमी को विश्वास करना ठीक नहीं है। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि चोरियों की बात ध्यान में लायें। हो सकता है कि जल्दी-जल्दी नहीं पकड़ी जांय क्योंकि चोर चोरियां एलानिया नहीं करते: लेकिन उनको पकड़ने का प्रयास किया जायगा।

श्री गोपीलाल यादव—इस बारे में आपको श्री घीसीसिंह पूरी जानकारी देंगे।

श्री जयनारायण व्यास—मैं धन्यवाद के साथ आपके सजेशन के माफिक श्री घीसी सिंहजी से बात करूंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगा।

अभी एक हमारे जगतसिंहजी झाला ने यह कहा कि साहब, प्रतापगढ़ से कुछ कैदी भाग गये, इसलिये लॉ एन्ड ऑर्डर व्यवस्थित नहीं है। मैं मानता हूँ प्रतापगढ़ से ही नहीं और भी दूसरी कई जगहों से कैदी भाग गये। हम कैदखानों को देखते हैं, लॉक अप्स (lock-ups) को भी देखते हैं, कई जगह बिल्कुल निकम्मे लोक अप्स हैं। खास तौर से उदयपुर डिविजन में, जोधपुर डिविजन के वेस्ट के हिस्से में खामियें हैं। हमें जो राजस्थान विरासत में मिला है वहाँ खामियाँ भी विरासत में मिली हैं। कई जगह पुलिस के थाने झोंपड़ों में बने हुए हैं। जो प्रोपर्टी रिकवर होती है वह झोंपड़ों में रखी जाती है। कैदी बाहर खुले मैदान में जंजीरों से बांध कर रक्खे जाते हैं। बरसात के समय में उन्हें किसी बरामदे में रखा जाता है। यह कह दिया जा सकता है कि यह कैदियों के साथ निर्दयता है। पर दर असल बात यह है कि हजारों सैकड़ों मील में इस इलाके में लोक अप ही नहीं है।

राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार के ध्यान में भी यह बात ला चुकी है। अब बहुत सारे लोक अप और पुलिस थाने बन रहे हैं और जो कमियें हमें विरासत में मिली हैं उनको दूर करने की

[श्री जयनारायण व्यास]

कोशिश की जा रही है । फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, कि अब लोक अप से भागने की घटनायें कम हो गई हैं । कोई पुरानी घटनाओं का गाना गाता जाय तो अलग बात है । अब जो घटनायें हुई हैं उनको और जो पहले घटनायें हुई हैं उनको देखा जाय तो यह बात मालूम हो सकती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास ने राष्ट्र दूत को क्वोट (quote) करते हुए जोधपुर की चोरियों का जिक्र किया है, जो उसमें प्रकाशित हुई हैं और कहा है कि राष्ट्रदूत के संपादक कांग्रेसमैन हैं। कांग्रेसमैन होने से क्या कोई ईमानदारी को छोड़ देगा, या पत्रकार नहीं रहेगा ? मैं एक पत्रकार हूँ और सदन को बता देना चाहता हूँ कि एडिटर हर न्यूज को पूछ-पूछ कर नहीं छापता है क्योंकि इससे वह न्यूज डेड (dead) हो जाती है; पुरानी बासी न्यूज हो जाती है। इसलिये जो खबर आती है वही छापी जाती है । कई बार न्यूज़ गलत भी हो जाती है, कई बार बढ़ी-चढ़ी भी हो जाती है । तो कभी राष्ट्रदूत में या किसी दूसरे दूत में जो भी कुछ छप गया तो उससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वे सारी बातें किसी भूत के द्वारा किये हुए काम की तरह ही होती हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास ने यह भी कहा है कि जनता में सरकार के प्रति बड़ा रोष है, इसी लिये सारी जगह यह गड़बड़ी और अशांति हुई । मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं । मैंने मिसाल दी थी सन् १९४७ के दंगे फिसादों की; जहाँ भरतपुर-अलवर में मेवों को खदेड़-खदेड़ कर निकाल दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, उनके घरों को लूट लिया गया, ट्रेनों को लूट लिया गया, छुरे भोंक दिये गये । यह क्या जोश था ? रोष था ?

बीकानेर में दफ्तर के काँच का शीशा फोड़ दिया गया तो एक वकील साहब कहते हैं कि तीस रुपये छः आने की कीमत का था, उसके लिऐ गिरफ्तार करने की क्या बात थी । अगर काम्युनिस्ट ऐसा कहते हैं तो उनको ऐसा कहना ही चाहिये ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्यों क्या बात है, कहना ही क्यों चाहिये ?

श्री जयनारायण व्यास—यह भी बताता हूँ क्योंकि यही एक उनका ध्येय है ।

They foment trouble, they create trouble, wherever there is trouble they go there. They propogate trouble, they develop trouble, this is their way to get Communism in the country."

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आपको कहाँ से पता चला है ?

श्री जयनारायण व्यास—आपके आचार से ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप अपनी सरकार के आचार को भी देखिये ।

श्री **जयनारायण व्यास**—यह मैंने कई जगह देखा है कि कहीं भी कोई थोड़ी सी बात होती है तो वहां अड्डा खड़ा कर दिया जाता है, पहले विस्परिंग (whispering) होता है, कानाफूसी होती है और एक ट्रबल (trouble) खड़ा कर दिया जाता है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि "जो कोई जावे जान जावे मैं तीजो तुरक तैयार।" तो कहीं भी कोई थोड़ी सी बात हो तो हमारे मित्र वहाँ बराबर तैयारी के साथ जावेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसमें भी हिम्मत का काम है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि आप ही ऐसी हिम्मत की तारीफ करेंगे। मैं तो उसी हिम्मत की तारीफ कर सकता हूँ जो हिम्मत देश की तरक्की करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिये होती है, जो रचनात्मक काम करते हैं उनको मदद देने की होती है। सन् १९४७ में जो दंगे फसाद हुए उनसे देश में प्रगति में कितनी बाधाएं पड़ीं, शरणार्थियों की समस्या अगर हमारे देश में पैदा नहीं हुई होती तो आज कभी का हमारा देश आगे बढ़ गया होता, तरक्की कर गया होता, कम्युनिटी प्रोजेक्टस का काम कभी पूरा हो गया होता। तो इस तरह की अशांति पैदा करने की जो बातें हैं वे देश की प्रगति के लिए बाधक हैं। इसलिये मैं तो इस तरह की हिम्मत की सराहना नहीं करूंगा, विरोधी पक्ष के नेता इसकी प्रशंसा कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—देश को आगे बढ़ाने का किसी ने ठेका नहीं लिया है।

श्री जयनारायण व्यास—ट्रबल पैदा करने का तो ठेका लिया है। आप धैर्य रखिये। बजट के दिन हैं, बजट के मौके पर बोलने का समय मिलेगा।

हाँ, तो तीन बातें हैं जिन पर खास तौर से बड़ा जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बेकारी है, भुखमरी है और यहाँ बीमारी है।

मैं बेकारी के ऊपर खास तौर से कहना चाहता हूँ। लेकिन पहले भूख जरूरी है इसलिए भूख पर ही कहता हूँ। भूख जरूर है। आज जो अशांति है, व गरम-गरम भाषण हैं इनके पीछे भूख है। वह भूख है सत्ता की। कहीं भी कुछ काम हुआ तो झण्डा उठाया और चल दिये, कभी लाल उठा लिया तो कभी काला उठा लिया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कभी तिरंगा उठा लिया (हँसी)

श्री जयनारायण व्यास—और बीमारी भी है, वह यह है कि देश हित के कार्य हों, कांग्रेस के जरिये हों या विरोधी के जरिये से हों, उसके बारे में कहने की। यह ठीक नहीं है, बीमारी है इस तरह के देश-हित के कार्यों को रोकने की।

तो इस तरह भुखमरी, बेकारी और बीमारी तीनों मौजूद हैं। यह भी मैं आशा करता हूँ कि ये मिटने वाली नहीं हैं।

Page No.78

[श्री जयनारायण व्यास]

अब मैं बेकारी के बारे में दो एक शब्द कहूँगा। श्री खजान्ची ने, श्री हरिकृष्ण व्यास ने और दूसरे लोगों ने इसके लिए असंतोष प्रकट किया है कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में बेकारी के लिए कुछ नहीं कहा गया और इसको मिटाने के लिये आश्वासन नहीं दिया गया कि इसको मिटाया जायगा। केवल उस आधार पर कि उन "एम्लोयमेंट" शब्द को नहीं लिया गया है इसलिए श्रीमन् राजप्रमुख के दिमाग में ऐसी बेकारी को मिटाने का मसला नहीं था; ऐसा कहना जरा गलत नीति होगी। जितनी बातें श्रीमन् राजप्रमुख ने कही हैं उनमें बेकारी को दूर करने की भावना है।

अकाल क्षेत्र में जो ४६ लाख रुपया लगा, क्या वह बेकारी को मिटाने में नहीं लगा, क्या वह रुपया जो बेकार लोग थे उनको काम देने में नहीं लगा ? मैं दर्याफ्त करना चाहता हूँ कि सिचाई के कामों में जो २ करोड़ ७ लाख रुपया लगाया गया क्या वह ठीक नहीं है ? वैसे सिंचाई के काम में कुल ७ करोड़ ५३ लाख रुपये लगाने को है। ये जो रुपये लग रहे हैं क्या बेकारी को दूर करने के लिए नहीं लग रहे हैं ? अभी जवाई में ६२ हजार बीघा जमीन बेकार थी जो सिंचाई में आई; क्या इससे बेकारी दूर नहीं होगी ? पौने दो करोड़ रुपया माइनर इरिगेशन में लग रहा है क्या वह बेकारी को हल करने में नहीं है ? २२५ मील मेटल्ड (metalled) रोड़ और २०० मील अनमेटल्ड रोड़ तैयार हो चुकी है और इसमें सवा करोड़ रुपया लगा है, क्या इससे बेकारी की समस्या को हल करने में सहायता नहीं मिली ? शिक्षा के मामले में १३०० अध्यापक रख लिये गये हैं और १००० अध्यापक उनको रिलीव (relieve) करने के लिए, जब वे छुट्टी आदि पर जावें, और रखे जा रहे हैं और १३०० मास्टर और रखे जावेंगे अगले साल। इस तरह २७०० मास्टर रखे जा रहे हैं, क्या यह बेकारी दूर करने का तरीका नहीं है ? नये आयुर्वेदिक पोस्ट खोले जा रहे हैं। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एक्स्टेंशन ब्लोक खोले जा रहे हैं। भाकरा, चम्बल का काम चल रहा है। दूसरे मेजर और माइनर इरिगेशन चल रहे हैं। ये सारी बातें बेकारी को दूर करने के लिये ही तो हो रही हैं और अगर कोई यह समझे कि काम हो रहा है वह बेकारी को दूर करने के लिए नहीं, तो मेरा खयाल यह है कि बेकारी को दूर करने का तरीका यह होगा कि पर्चे छपाये जावें और कुछ आदमियों को ६ आने के पैसे देकर वे पर्चे उनके द्वारा बँटवाए जावें। इसलिए यह कहना कि बेकारी दूर नहीं हो रही है और बेकारी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि यह वास्तविकता पर परदा डालना होगा और सरकार की नीति और राजप्रमुख के भाषण को अच्छी तरह नहीं समझना होगा।

मैं अब थोड़ी सी मुतफरकात बातों पर कुछ कहूँगा।

श्री मथुरादास ने यह कहा था कि शिक्षा के बारे में कोई नीति नहीं है।

(हियर-हियर)

मैं कहता हूँ कि शिक्षा के बारे में हमारी नीति बिल्कुल साफ है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो हमारे दिमाग में उलझन पैदा कर रही है और वह बात यह है कि अगर हम

[श्री जयनारायण व्यास]

कालेजेज, इन्टरमीजियट कालेजेज और हाई स्कूल बढ़ाते ही जावें तो इसके बाद में बेकारी बढ़ती ही जावेगी। इसलिए सरकार बराबर सोच रही है कि इसके बदले में क्या किया जावे। लेकिन जिस क्षेत्र में काम हो रहा है वह यह है कि शिक्षा ऐसी नहीं हो जो आदमियों को और ज्यादा बेकार बनाए। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में तजवीज चल रही है। वह तजवीज वेटरनरी कालेज, एग्रिकलचर कालेज, एग्रिकलचर स्कूल आदि नये खोले जाने की है ताकि हमारी शिक्षा जो हो वह केवल बाबू लोगों की शिक्षा और शोर-गुल का "इन्किलाब जिन्दाबाद" पैदा करने के लिए न हो लेकिन वास्तव में ऐसी शिक्षा हो जो वास्तविक इन्किलाब जिन्दाबाद करे और दी फेस ऑफ दी अर्थ को बदले।

एक सदस्य—God help Rajasthan.

एक अन्य सदस्य—वह सदन के सामने भी आवेगी क्या ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इतना ही निवेदन करना चहता हूँ कि वह आवेगी। इस तरफ ध्यान देना राजस्थान के विधान सभा के सदस्यों के लिए आवश्यक है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि अभी हम बहुत सारी डिटेल्स तय नहीं कर पाये हैं कि शिक्षा को किस तरह ढालना चाहिए और बेकारी को मिटाने और संस्कृति को कायम रखने के लिये कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहिये और जब तक हम इसको पूरी तरह से तय न करलें तब तक उसे सदन के सामने न लाना ही ठीक होगा। अकलमन्द को इशारा ही काफी है। मैं समझता हूँ कि यह इशारा श्री वेदपाल त्यागी जैसे अकलमन्दों के लिए काफी होना चाहिए।

अब मैं जो छोटी-छोटी बातें सदन में कही गई हैं उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, श्री यादवजी ने यह कहा कि राजस्थान में तो अनाज की कमी नहीं थी। मुझे तो बहुत खुशी होती कि यादवजी की यह भविष्य वाणी, वर्तमान वाणी या भूतवाणी जैसा भी कहना चाहें कही गई हो, हमेशा राजस्थान के ऊपर कायम रहे। लेकिन स्थिति दूसरी तरह की है। राजस्थान डेफिसिट (deficit) स्टेट है। यादवजी ऐसी राय रखते हैं कि यह डेफिसिट स्टेट नहीं है, वह इसलिये कि उनके आस-पास के गाँवों में जहाँ वे रहते हैं थोड़े बहुत अच्छे खेत हैं। लेकिन में जैसलमेर, जोधपुर और रणबंका राठाड़ों की भूमि जहाँ कुँ० जसवन्तसिंहजी रहते हैं बीकानेर राजस्थान रेगिस्तान है। बीकानेर में गंगानगर को छोड़ कर अकाल की स्थिति रहती है। मगर इस बार खुशी की बात है, वैसा नहीं है।

इसके अलावा यादवजी ने कहा कि इतना अनाज क्यों इकट्ठा किया गया ? साफ बात है कि ५ साल तक अगर अकाल पड़ा रहे तो ऐसी हालत में राजस्थान को जागरूक रहना और अनाज रोकना पड़ेगा। सड़ने की हालत होगी तो बेचना पड़ेगा। अब यह कहा जाता है कि दूसरे क्षेत्रों में क्यों भेजा। अनावृष्टि के क्षेत्रों में भेजना था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसके पास अनाज मौजूद है वहाँ पर भेजना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं। फालतू पैसा ट्रान्सपोर्ट में जाया होता है। शासक इतने बुद्धिमान जरूर हैं कि फालतू पैसा जाया न होने दें, और इस तरह की राय

[श्री जयनारायण व्यास]

को नहीं माने। गई साल अच्छी वर्षा हुई और ५०० गाँवों को छोड़कर सब जगह ईश्वर की कृपा रही। मगर फिर भी हमारे यहाँ लोकस्ट (टिड्डी) आती रहती है और कभी-कभी गड़-बड़ हो ही जाती है इसलिये थोड़ी सी सावधानी बरतलें तो कोई बुराई की बात नहीं। फिर भी मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूँगा कि राजस्थान में अनाज की समस्या पैदा न हो और यह राजस्थान धन-धान्य से भरा पूरा हो। मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा और यादवजी से भी प्रार्थना करूँगा कि वे भी इसमें मेरे साथ रहेंगे।

कुँ० जसवन्तसिंहजी ने एक बात कही कि फेमिन के पैसों का राजनैतिक व्यक्तियों ने ही फायदा उटाने की कोशिश नहीं की बल्कि एक विशेष दल ने तीन-चार बार तकावी लेली और फायदा उठाने की कोशिश की।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने तो श्री माथुर को जबाव देते हुए कहा था कि एक राजनैतिक दल ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया।

श्री जयनारायण व्यास—मैं उसका जबाब दे रहा हूँ। आम तौर पर ऐसी बात है कि कोई भी चीज जो वाजिब हो तो भी यह कह दिया जाता है कि यह चीज पार्टी के लिये हुई है। यदि ट्रान्सफर हो तो कह देते हैं कि इसमें कांग्रेस के लोग फायदा उटाते हैं। यदि किसी स्थान पर जोधपुर या उदयपुर का अफसर हो तो लोग यह कह देते हैं कि जोधपुर या उदयपुर वालों ने फायादा उठाया और यह बात मानी भी जा सकती है। मगर मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि वे बतावें कि किन-किन व्यक्तियों ने दो-तीन बार तकावी ली और मैं बराबर वादा करता हूँ कि यदि वे अब भी बतावेंगे तो मैं बराबर जाँच करूँगा और यह भी बता देना चाहता हूँ कि यदि वह व्यक्ति कांग्रेस का हो या और कोई भी हो और उसने उसका दुरुपयोग किया तो हम उसको सजा देंगे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—हम नहीं मान सकते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मशीनरी की तकाबी के बारे में भी क्या आपका यह आश्वासन है ?

श्री जयनारायण व्यास—हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो वे नहीं, मैं बताने के लिये तैयार हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—अगर दुरुपयोग किया है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—वाकई दुरुपयोग हुआ है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर्स दूसरी तकावी है और यह अजीब बात जरूर है। (विपक्ष द्वारा हियर-हियर)

[श्री जयनारायण व्यास]

यह तकावी उन लोगों को मिली हो जिनके पास जमीन अधिक है एवं दस खेतों को मिला कर खेती के लिए ट्रेक्टर लेने वाले अभी नहीं हैं : मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जिनके पास ज्यादा जमीन है और जिनको ट्रेक्टर तकावी मिली है वह भारत सरकार की नीति के अनुसार मिली है और उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अगर कोई दुरुपयोग हुआ है तो मैं उसकी जांच करवा सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप दुरुपयोग की बात बतावें। वाकई दुरुपयोग हुआ है, यह मैं कह सकता हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—अगर दुरुपयोग की बात है तो मैं कहूँगा कि दुरुपयोग की बात का मैं सदुपयोग भी करूंगा।

(हंसी)

उस पर उचित और समुचित कार्यवाही करूंगा यह मैं विश्वास दिला सकता हूँ।

मुझे अभी राजस्व मन्त्री साहब ने बताया कि यह बात ठीक है। कुछ लोगों ने लोन्स ले लिये थे किन्तु ट्रेक्टर्स नहीं खरीदे। उनके प्रति एक्शन लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह संतोष की बात होनी चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनको बगैर जांच किये ही लोन्स दे दिये गए थे ?

श्री जयनारायण व्यास—ट्रेक्टर्स तकावी के लिए उन्होंने दरख्वास्तें दी होंगीं। इन एन्टीसिपेशन (in anticipation) लिख दिया गया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रसीदें बताने तक के लिए हम तैयार हैं।

श्री जयनारायण व्यास—रौंग रिसीप्टस (wrong receipts) होगी। वैसे मैं हाउस के सामने कैसे कह सकता हूँ जिसकी मुझे जानकारी नहीं है।

माथुरजी ने कहा था और एक दूसरे सज्जन ने भी कहा था कि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की कमी है। मैं इस बात को मानता हूँ। यह इलाका रेगिस्तान है और जिसको कहते हैं पानी की कमी का इलाका और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कई जगहों पर खारा पानी निकलता है, और वह पानी विषैला होता है जिसको विराना पानी भी कहते हैं। दो-दो दिन में एक बार जानवर पानी पीते हैं, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। लेकिन इन सारे गांवों में एक दम पानी लेजाना या कहीं से पानी लाकर देना आर्थिक और व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। फिर भी पानी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए योजना है और मेरा ऐसा खयाल है कि पंच वर्षीय योजना में एक करोड़ रुपया इस कार्य के लिए खर्च किया जावेगा।। मेरा ऐसा खयाल है कि जो लोग पानी की कमी की बात कहते हैं उनको इससे संतोष होगा।

[श्री जयनारायण व्यास]

श्री माथुरजी ने भी जिक्र किया था कि लिफ्ट इरिगेशन की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई। राजस्थान में लिफ्ट इरिगेशन की बहुत थोड़ी गुन्जाइश है। जमीन से लिफ्ट इरिगेशन किया जा सकता है। मैं सदन को सूचना देना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और यू० पी० की सरकार के बीच में बातचीत चल रही है और मैं आशा करता हूँ कि वह बातचीत सफलता की ओर जा रही है। मिनिस्टरों से बातचीत की गई है। इससे फायदा होगा सिर्फ भरतपुर के एक हिस्से को। श्री गोपीलालजी को इससे संतोष हो जायगा।

श्री माथुरजी ने और श्री कासलीवालजी ने एक विषय के बारे में भिन्न-भिन्न रायें जाहिर की हैं और कुछ लोगों ने उस भिन्नता का लाभ उठाने की कोशिश की। उन्होंने (माथुरजी ने) युनिवर्सिटी के सिलसिले में कहा था कि यह एक ही जगह क्यों हो, सारे साधन एक ही जगह क्यों हों? जोधपुर में हो जाय और जोधपुर के महाराजा के एक शर्तनामे की बात भी उन्होंने जाहिर कर दी। उसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि उदयपुर में होनी चाहिए। कासलीवालजी ने अपनी स्वतन्त्र राय जाहिर की कि यह काम युनिवर्सिटी पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और वह ही तय कर ले। यह तो एक स्वतन्त्र राय जाहिर करने की बात है। परस्पर विरोधी भावना नहीं होनी चाहिए थी। एक विषय पर एक कांग्रेसमैन एक राय रख सकता है दूसरा कांग्रेसमैन दूसरी राय रख सकता है। कांग्रेसमैन का दिमाग, मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूँ कि लकड़ी का दिमाग नहीं है जिसमें एक कोरणी की गई हो। अलग-अलग बातें हैं, अलग-अलग रायें हो सकती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पत्थर का मालूम होता है।

श्री जयनारायण व्यास—पत्थर को मैं कीमती और सुन्दर मानता हूँ। उसको ज्यादा कड़ा कह कर पत्थर का अपमान करना है। मैं तो यह कहूँगा कि पत्थर को अपमानित करने के लिए ही 'पाषाण हृदय' आदि विशेषण लगाये जाते हैं। खैर! यह अलग चीज़ है। यदि पत्थर का अपमान ही करना है तो इन्सान को हृदयहीन कहना अच्छा होगा।

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या दिमाग को कोरणी करने का मौका नहीं दिया जाता है।

श्री जयनारायण व्यास—केपिटल्स के बारे में मैं फिर दुबारा इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ओल्ड केपिटल्स का जो स्थान पहले था वह अब नहीं है। एक औसत (दर्जा) होती है शहर की, एक औसत होती है कस्बे की और वह इसलिए होती है कि पहले शहर और कस्बे एक विशेष हस्ती रखते थे और खास तौर पर जो राजधानियाँ थीं उनकी हस्ती विशेष थी। सारे कस्बों, देहातों का पैसा बह-बह कर राजधानियों में आता था, रोशनी और सजावट में लगता था। अच्छी सड़कें, बहुत अच्छी रोशनी, सेठों के अच्छे सम्पन्न स्थान आदि शहरों में केन्द्रित होते थे। और राजधानियों में रहने वाले सुयोग्य होकर अच्छी नौकरियों पर लग जाते थे, राजाओं के नजदीक होने पर जागीरियें मिल जाती थीं तथा और भी लाभ होते थे। इन राजधानियों के हट जाने से और जयपुर ही एक राजधानी होने से उन राजधानियों की शान और शौकत में कमी जरूर आ गई है। और बड़ी कमी आई है

[श्री जयनारायण व्यास]

और वह कमी है हमारे राजस्थान की विधान सभा में बैठे हुए १६० सदस्य, जो सारे शहरों के नहीं है, वे देहातों के भी हैं और वे अब यह आशा करते हैं कि जो सुख के साधन हैं वे सब शहरों में ही केन्द्रित न करें, जो देहातों के पास है वह सारा शहरों में ही मत लगाइये। सेन्ट्रल एड जो आई है वह देहातों की तरफ ज्यादा गई है, स्कूल खोले गये हैं तो वे देहातों की तरफ ज्यादा खोले गये हैं, आयुर्वेद एड पोस्ट्स खुल रहे हैं, देहातों में ज्यादा खुल रहे हैं, कम्युनिटि प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है तो देहातों में ज्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ आर्थिक कानून कायदे भी जो बन रहे हैं देहातों पर बने हैं और बन रहे हैं। बड़े-बड़े बन्ध और छोटे-छोटे बन्ध देहातों के फायदे के लिये ही बनाये जा रहे हैं। जागीरें रिज्यूम हो जाएँगी तो देहातों को ही फायदा है। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा दृष्टिकोण देहातों की तरफ गया है। इसलिए शहरों से मांग की जाती है कि आप देहातों के ऊपर पैरासाइट की तरह, जोंक की तरह न लगें, और आप अपना खर्चा खुद उठावें। जो लोग शहर वालों को पैरासाइट के नाम से पुकारते थे और वे शब्द आज भी शहरियों में मशहूर है, वे ही लोग कहते हैं कि हाउस टैक्स मत लगाइये, ऑक्ट्राय ड्युटी नहीं हो सकती; यह जुल्म हो रहा है, वह जुल्म हो रहा है। मैं जानता हूँ कि अगर वे सत्ता में आ जाय, मेरा विश्वास है कि वे आयेंगे कभी नह, वे शहर वालों की हत्या करने में आगे रहेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आबियाना का भी शहर से ताल्लुक होता होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मुख्य मन्त्री का इरादा है कि शहर जो हैं उनको बरबाद कर दिया जाय।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि शहरों को बरबाद कर दिया जाय, किन्तु उन शहरों को अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देनी चाहिये। उन्हें गाँवों के ऊपर मुनस्सर नहीं होना चाहिये। गाँवों के सारे सुखों को छीनकर शहरों की हवेलियाँ हम आबाद नहीं करना चाहते। अब वह समय आ गया है जब कि बड़ी-बड़ी इमारतें नहीं रहने वाली हैं, बड़ी इमारतें ढाई जाने वाली हैं चाहे आप कितनी ही कोशिश करें·····

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अगर बड़ी-बड़ी हवेलियाँ ढह जायेंगी तो माननीय मन्त्री महोदय कहाँ रहेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हवेलियाँ ढह जाँय और हमारे गाँव सरसब्ज हों। मन्त्री लोग अपने दफ्तरों में रहेंगे, झोंपड़ों में भी रह सकते हैं·······

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप उदाहरण तो सेट करिये। आज एक-एक मिनिस्टर के लिए पाँच-पाँच हजार माहवार आप कैसे खर्च करते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह गलत बात है।

Page No.84

श्री गोपीलाल यादव—(बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—There should not be any interruption. He is in possession of the House.

श्री जयनारायण व्यास—I am in possession of my voice, Sir.'

(विराम)

पुरानी राजधानियों को यह आशा नहीं करनी चाहिये कि दूसरों के सारे साधन लेकर उन पर खर्च कर दिया जाय। इसके लिए राजधानियों को थोड़ा-थोड़ा खर्चा अपने लिए खुद को करना चाहिये। वह अपना खर्चा शहरी लोगों से पैदा करे। जब हम उनसे इस प्रकार का काम करने को कहते हैं तो थोड़ी उनमें नाराजगी पैदा होती है। ठीक है जैसी कि एक मारवाड़ी कहावत है 'ऊँट पीलाणताई' अड़ावें, अर्थात् जब उंट पर पीलाण रखी जाती है तो वह अड़ाता है, उसी प्रकार जब हमें राजधानियों को थोड़ा बहुत पिलाण पड़ता है तो यह स्वाभाविक है कि वे अड़ावेंगी। इस तरह से धीरे-धीरे वे अपने को इस चीज़ का आदि बना लेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि टैक्सेज वगैरह के ठीक हो जाने पर वहाँ की हालत ठीक हो जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार पर भी पिलाण डाली जानी चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मुझे ऐसा जान पड़ता है कि भाषा के बारे में भी हमारे यहाँ क्लास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। शब्दार्थ, भावार्थ, लक्षणार्थ भी समझाने की सदस्यों को जरूरत है। किन्तु मैं इन बातों में जाकर सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता।

अब मैं विरोधी दल के नेता की एक बात पर जो कि मुझे बहुत भावनापूर्ण मालूम हुई, कुछ कहूँगा। वह बात थी पाक-अमरिकन ट्रीटी (Pak American Treaty) के सिलसिले में। पाक अमरिकन ट्रीटी के बारे में मैं कोई विशेष भावना प्रगट नहीं करना चाहता लेकिन एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि यह भावना प्रगट होती है अलग-अलग दृष्टिकोण रखने वालों की तरफ से, अलग-अलग प्रकार से होती है। जो रूसी पक्ष का होता है, वह रूस विरोधी अमेरिकी भावना प्रकट करता है, जो मुसलिम विरोधी दृष्टिकोण वाला होता है वह चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है उस दृष्टि से अपनी भावना प्रकट करता है, और जो सुरक्षा पक्ष का होता है वह बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इसको देखता है। मैं इस पाक-अमेरिकी ट्रीटी को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते हैं। हमारे देखने की दिशा भी वे ही बनाते हैं, इसलिये हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिये। मेरा ऐसा खयाल है कि जैसा कि भय किया जाता है वह भय हमें नहीं है। ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है कि कुँवर साहब को जाना पड़ेगा तलवार और बन्दूक लेकर। ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। अगर ऐसी स्थिति आ भी गई और जरूरत हुई तो बराबर उनको निमन्त्रण दिया जायगा। उनको अच्छा पद देने की, जैसी कि उनकी हैसियत होगी, कोशिश की जायगी। उनको सम्मान के साथ भारत सरकार आमन्त्रण देगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने व्यक्तिगत रूप में न तो आमन्त्रण देने के लिए ही कहा था और न इस प्रकार की इच्छा ही प्रगट की थी। श्री कासलीवालजी ने जब राजपूत जाति के लिए कहा था कि ऐसा समय आने वाला है उसके लिए राजपूत जाति को तैयार रहना चाहिये तो मैंने कहा कि राजपूत जाति हमेशा तैयार है और रहेगी।

श्री जयनारायण व्यास—मैं कुँवर साहब को इस जाति का प्रवक्ता समझता हूँ और जिस समय मैं बन्दूक, तलवार और शस्त्रास्त्र की बात करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि वे अकेले ही जायेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि उनके साथ, सारी राजपूत जाति होगी और मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि गैर-राजपूत जाति के लोग भी उनका साथ देंगे।

कुँ श्री० जसवन्तसिंह—माननीय मुख्य मन्त्री जिस सर्कास्टिक भाषा में कह रहे हैं यह उनके पद के लिए उनको शोभा नहीं देता। मैं इसको ऑब्जेक्शनेबल मानता हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—कुँवर साहब इसको सर्कास्टिक समझते हैं, इस बात का मुझे खेद है। उन्होंने राजपूत जाति के लिए कहा है उन्होंने उस जाति की ओर से जो यह आश्वासन दिया है कि पाक-अमरिकी संधि या अन्य किसी कारण से देश पर हमला हुआ तो उस वक्त राजपूत जाति बराबर सरकार का साथ देगी। मैं इस आश्वासन का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको भी दूसरे रूप में नहीं लेंगे। आप राजपूत जाति के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से बोलने के हकदार हैं। उस जाति के प्रवक्ता होने के नाते जो कुछ उन्होंने कहा है उसी के अनुसार कार्य करेंगे, इसमें मुझे शंका मालूम नहीं पड़ती और उन्हें इसको सर्कास्टिक समझने की आवश्यकता नहीं।

अभी मुझे बहुत सारी बातें कहनी हैं। मुझे ऐसा लगता है उन सब बातों को छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए मैं जो एक आवश्यक बात है उसको अर्ज करना पसंद करूँगा। श्री हरिकृष्ण व्यास और कुछ दूसरे लोगों ने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने यह कहा है कि गंगानगर के अन्दर जो शुगर फेक्ट्री है उस शुगर फेक्ट्री के किसी सेठ को मदद देने के लिए चालू किया गया है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने मदद देने के लिए नहीं कहा, बल्कि यह कहा कि लीज़ पर लिया गया है।

श्री जयनारायण व्यास—लीज़ पर लिया गया या चालू करने के लिए, यह बहस का विषय नहीं है। यह बात सही है कि गंगानगर एक शक्कर पैदा करने वाला इलाका है। गत वर्ष वहाँ जो ईख पैदा हुआ था उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ। मैं खुद दिल्ली गया और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से मैंने इस सम्बन्ध में बातचीत की। ठेकेदारों से बातचीत की। जो रामनाथ सेठ हैं उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने इसको चालू नहीं किया। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ जो ईख पैदा हुई थी वह ईख फिजूल चली गई, कुछ का गुड़ अवश्य बना। इस साल भी यही परिस्थिति होने वाली थी। सेठ रामनाथ के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमको नुकसान होता है। चाहे इससे मजदूरों को फायदा होता हो लेकिन हम इस फायदे में पड़ने वाले नहीं। ईख खतम हो या कुछ भी हो हमको पाँच लाख

[श्री जयनारायण व्यास]

रुपये का नुकसान होता है, यह उनका खयाल था। हमने वहां के लोगों से पता लगाया तो हमें उनका यह खयाल गलत लगा। इसलिए एक साल के लिए जैसा कि मैंने कल बताया था इसको लीज़ पर लिया गया है। हमने यह कल्पना भी कर ली थी कि यदि नुकसान भी हुआ तो हम बर्दास्त करेंगे क्योंकि इस फेक्ट्री के चालू रहने से तीन फायदे थे; एक तो यह कि मजदूरों को मजदूरी मिलती, दूसरा यह कि यदि फेक्ट्री नहीं चलती है तो वहाँ जो ईख पैदा होती है वह बन्द हो जाती। इससे राजस्थान का बड़ा नुकसान होता। और तीसरा कारण यह था कि एक इन्डस्ट्री खत्म हो जाती और चौथा कारण यह भी था कि यह फेक्ट्री कोरी सेठ की हो ऐसी बात नहीं, इसमें राजस्थान सरकार का १८-१६ लाख रुपया लगा हुआ है जिसकी राजस्थान सरकार गार्जियन है। राजस्थान सरकार को यह रुपया देना है इसलिये भी हमें इसको जिन्दा रखना है। यह सब बातें राजस्थान सरकार के ध्यान में थीं और राजस्थान सरकार अब तक पाँच लाख मन गन्ना क्रश (crush) करवा चुकी है। अब उम्मीद होने लग गई है और मैं आशा करता हूँ कि नुकसान की बात तो दूर रही, इस फेक्ट्री से हमें फायदा होने वाला है। यह कहना कि डेढ़ लाख रुपये पर लीज़ पर ली गई, यह बात गलत है। नोमीनली अब तक दफ्तरों का खर्च आदि भी हमने देने की तैयारी नहीं की है। फेक्ट्री के रवैये को देख कर यह तय किया जायगा। हमने चोटी अपने हाथ में रखी है। हम इतने गये गुजरे खिलाड़ी नहीं जो इतनी बड़ी गलती कर सकें।

जो यह समझते हैं कि राजस्थान सरकार जो कुछ भी कार्य करती है वह बेईमानी से करती है, तो मुझे उनकी अक्ल पर, उनके सोचने के तरीके पर कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—आज सरकार......

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री **जयनारायण व्यास**—मेरा ऐसा खयाल है कि हम लोग क्वेश्चन ऑवर के बड़े आदी हो गये हैं इसलिए हर प्रश्न पर क्वेश्चन और सप्लीमेन्टरी, अध्यक्ष महोदय, आ ही जाते हैं। इसका कुछ इलाज मुझे कम दिखाई देता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गलत इत्तला देते हैं इसलिए।

श्री जयनारायण व्यास—इत्तलाएँ ठीक होती हैं, पर समझने की शक्ति नहीं उसका मैं क्या करूं ? अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे श्रद्धेय मित्र श्री मंगलसिंहजी ने अपने भाषण में राजस्थान सरकार की कई बातों का समर्थन करते हुए लॉ एन्ड ऑर्डर के सिलसिले में एक बड़ी डकैती का जो जिक्र किया कि आदमी लेजाना तो आसान है, बहुत आदमी उठाकर ले जाये गये हैं और एक इलाका भी ले लिया गया है। उनका मतलब आबू से था।

मैं सदन को कई बार सूचना दे चुका था कि इस बारे में हम केन्द्रीय सरकार के सामने अपना मसला रख चुके हैं, रखते रहे हैं, लेकिन बद-किस्मती से, दुर्भाग्य से, हम जिस तरह से पुराना

[श्री जयनारायण व्यास]

तरीका था कि कोई इलाका इधर से उधर हो जावे और इधर से उधर ले लिया जावे और आज उस तरीके के निशान बहुत से किलों पर किसी तोप के रूप में या किसी किंवाड़ के रूप में या किसी हाथी की अम्बाड़ी के रूप में मौजूद हैं, वह तरीका हम काम में नहीं ला सकते। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मामला शायद जो सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, जो छोटी सी समिति बनी है वह भी हम से पूछताछ करे। इस मामले को हमें बहुत ही गम्भीरता से लेना है और मजबूती से अपने पक्ष को रखना है। जबर्दस्ती आबू छीन लें ऐसी सम्भावना और ऐसा संकेत भी नहीं है और इसमें औचित्य भी नहीं है और चूंकि अभी तक आबू वापिस नहीं आया इसलिए इसका फायदा उठाकर कोई सरकार को कोसता रहे तो वह कोसता रह सकता है। लेकिन यह मामला आपस में एक दूसरे को कोसने का नहीं है बल्कि यह मामला आपस में बैठकर सोचने का है कि किस तरह से हम चलें कि जिससे हमारा यह खोया हुआ इलाका हमें वापिस मिल जावे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने से, मैं समझता हूँ, बहुत लाभ नहीं होगा।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—लेकिन बम्बई वाले कर रहे हैं। अगर लाभ नहीं है तो वे क्यों कर रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर कहीं बम्बई के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं......

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—कुछ लोग ही नहीं वहाँ के मुख्य मन्त्री......

श्री जयनारायण व्यास—मुख्यमन्त्री ने मना कर दिया था, जब उससे जिक्र किया गया इस बारे में। बहुत थोड़ा उन्होंने इस बारे में कहा था और जो कुछ बात कही उसका यहाँ के मुख्य मन्त्री ने भी जवाब दे दिया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—थोड़ा ढीला जवाब था।

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मन्त्री) हरेक जिम्मेदार आदमी थोड़ा धीमाई की तरफ रहेगा और तेजी और अनुचित तेजी नहीं रक्खेगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या हम यह मानें कि बम्बई के मुख्य मन्त्री जिम्मेदार नहीं थे ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं जवाब की बात कर रहा था।

हां, हिन्दी के सिलसिले में मैंने निवेदन तो कर दिया था। पर भाषण करते समय विरोधी दल के नेता ने कुछ शब्द कहे, जिन पर थोड़ा सा मुझको दुख हुआ। वे शब्द थे 'अगले सैशन तक राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति इस स्थान को ग्रहण करेगा जो हिन्दी में भाषण देगा और पब्लिक की जो मांग है उसको पूरी करेगा'। मैं समझता हूँ कि वही व्यक्ति हिन्दी में भाषण दे सकेगा। कुँवर साहब को उतावला होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से श्री हरिकृष्ण व्यास उतावले हो रहे हैं कि यह संस्था बहुत भारी संस्था है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह सरकारी आंकड़ें हैं और पब्लिश्ड हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। पर इतना कह सकता हूँ कि ये सरकारी आंकड़े नहीं हो सकते।

बहुत से राजाओं पर खर्चा होता है वह तो केन्द्र से होता है। देश का रुपया खर्च होता है इस संस्था पर, वह ठीक है या बेठीक है यह देश को तय करना पड़ेगा। लेकिन इस समय जिन परिस्थितियों में हम हैं उन परिस्थितियों में इससे ज्यादा कोई अक्लमन्दी की व्यवस्था हो नहीं सकती है। जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि किसी भी हालत में सभी तत्वों में अशान्ति पैदा करके केओस (अराजकता) पैदा कर दिया जावे, उनके लिए यह बात ठीक हो सकती है; लेकिन जो व्यवस्था लाना चाहते हैं और क्रमशः व्यवस्था लाना चाहते हैं और बड़ों का एक्सप्लोइटेशन बन्द करना चाहते हैं वह ऐसा रास्ता बराबर अपनावेंगे जो रास्ता व्यावहारिक है और जिस रास्ते में बीच में अशान्ति और अव्यवस्था पैदा न हो, वही रास्ता हम अपनावेंगे और वे रास्ते अपनाये जावेंगे और अपनाये जा रहे हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह फरमाया कि उनको दुख हुआ मैंने ऐसा कहा इसलिए। इसमें दुख की ऐसी क्या बात हुई? कभी आपके भी तो ऐसे ही विचार थे। क्या आप नहीं चाहते कि राजप्रमुख इस पद को ग्रहण नहीं करें?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरा......

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री जयनारायण व्यास—अब मैं एक शब्द, श्री कासलीवालजी से जो पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह के बारे में बात कही कि उनको चार-चार हजार मिल जाते हैं और यह ज्यादा नहीं मिलनी चाहिये, कुछ कम होना चाहिये। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कासलीवालजी जिस एक्स्ट्रीम पर गये थे उससे दूसरे एक्स्ट्रीम पर हमारे कुँवर जसवन्तसिंहजी चले गये और उन्होंने अपने भाव इस रूप में व्यक्त किये कि मेरी गाय तो चोरी नहीं करती है क्योंकि उसको काफी खाने को मिलता है और दूसरों की गाय चोरी कर जाती है क्योंकि उसको खाने को पूरा नहीं मिलता।

("यह तो यादवजी ने कहा था" एक आवाज)

यह यादवजी ने कहा होगा। लेकिन कुँवर साहब ने भी कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कहा, जरूर कहा।

श्री **जयनारायण व्यास**—चीफ सेक्रेट्री गये और सभी व्यवस्था कर दी, उनके जो मामले थे वे सब तय करवा दिये थे जो कि चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाये। चीफ मिनिस्टर में भी थोड़ा दिमाग है।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—यह तो ठीक है, पर करते नहीं हैं दुख यही है न।

श्री **जयनारायण व्यास**—नौकर इसलिए रखना पड़ता है कि डिटेल में उनको जाना पड़ेगा और एक-एक डिटेल में अगर आप मिनिस्टर को जाने को कहेंगे, जैसा कि आपने भी कभी नहीं किया होगा अपनी मिनिस्टरी के काल में, तो यह व्यावहारिक बात नहीं होगी।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे भी खुशी होती और होगी कि अगर अधिकारी लोग स्वयं कुछ वेतन अपना कम कर दें। लेकिन जिस तरह का संविधान हमारा है उसमें राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार भी उनके जो प्रिवीलेजेज़ हैं, तनख्वाह के तथा और तरह के; उनमें कमी नहीं कर सकते हैं जब तक कि विधान में इसके सम्बन्ध की धारा ही नहीं बदल दी जावे। इसलिए चूँकि विधान अभी नहीं बदला है और जब तक यह विधान है, तब तक यह आशा करना और अगर उसमें कमी नहीं हो तो उलाहने देना, मैं समझता हूँ, यह मिनिस्टरों के प्रति न्याय करना नहीं होगा।

अब मैं थोड़ा हमारे पुरुषार्थी भाइयों के बारे में, जो इधर-उधर की कुछ बातें कहीं गई हैं, दो शब्द कहना चाहूँगा। कुँवर साहब ने तो यह कहा कि मकान बहुत बुरे हैं इसलिए कोई रहना नहीं चाहता......

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—बीकानेर में तो।

श्री **जयनारायण व्यास**—बीकानेर में मकान बहुत बुरे हैं इसलिए कोई रहना नहीं चाहते हैं और वे बिल्कुल खाली पड़े हैं और यादव जी ने यह कहा कि छोटा सा बापू बाजार बन गया इससे यह समस्या हल नहीं हो जाती है; न ही मेव बसाये गये हैं और न शरणार्थी। कोई पाकिस्तान में रेडियो बुला रहा है। यह बड़े दुख की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पुरुषार्थी भाई हैं उनको सम्पूर्ण रीति से संतोष मिले, इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। जो हजारों मकान बने हैं, जो हजारों दूकानें बनी हैं; हो सकता है कि उनमें से वैसे मकान नहीं हों जैसे कि मकान हमारे पास हैं, वैसे मकान नहीं हों जैसे कि वे वहाँ छोड़कर आये हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है और सीमित साधनों से करनी पड़ती है तो छोटे-छोटे मकान बनाने पड़ते हैं। फिर भी व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उन मकानों में जो कि बस्तियों से अलग बनाये जाते हैं, आना पसन्द नहीं करते हैं; फिर भी मकान जो बने हैं उन्होंने इस समस्या को कुछ हल किया है।

उनको बसाये जाने के अलावा जो वे जायदादें छोड़कर आ गये हैं उनको उनकी जायदादों के बदले में यहाँ मुआवजा भी देने लग गये हैं और एक इन्स्टालमेंट ३ लाख रुपये का उन्हें

[श्री जयनारायण व्यास]

मिल चुका है, और भी मिलता रहेगा। यह समस्या अब उतनी गंभीर नहीं रही है। मुआवजा उनको मकानों और दूकानों के रूप में भी दिया गया है। लेकिन अब वह इतनी गंभीर समस्या नहीं रही है और यह कह देना कि कुछ नहीं हुआ है और सिर्फ एक बापू बाजार हुआ है, यह गलत बात होगी। कई जगह बाजार हुए हैं, कई जगह दूकानें खुली हैं, कई जगह मकान बने हैं, कई जगह मुआवजा दिया गया है, कई जगह नारी-शालायें और केम्प्स भी हैं, कई जगह नौकरियाँ भी दी गई हैं, लेकिन पूरा संतोष किसी को नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मेवों और नहीं बसाया गया है। मेव करीब हैं बसा दिये गये हैं। अब यह कहना कि मेवों और शरणार्थियों में कई जगह झगड़े देखने में आते हैं, तो मेवों की बात आप करते हैं तो शरणार्थियों की बातें वे कह सकते हैं। यह बात इन्सान जब तक रहेगा तब तक रहेंगी। आपस में एक दूसरे के झगड़े की बात में एक दूसरे को ऊँच-नीच कहना, इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं।

मैं एक चीज़ समझ नहीं सका कि कुँवर साहब ने परम्परा के सिलसिले में कहा था कि एस्टीमेट्स कमेटीज़ और पी. ए. सी. कमेटियों में क्या हाल होता है, क्या नहीं होता है। तो एस्टीमेट्स कमेटियों के बारे में, जो कमेटियों में बैठे हुए हैं उन्हीं पर मैं छोड़ूँगा। यह उनके हाथ की बात है। हाँ इतना जरूर मैंने अखबारों में पढ़ा है; कि एस्टीमेट कमेटी में ऐसा हो रहा है, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के अन्दर यह हो रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो हुआ है उसके लिए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज के तौर पर उन चीजों को उपस्थित करूँगा और उस वक्त जो एस्टीमेट्स कमेटियों और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटियों के बारे में डिटेल्स में बातें होंगी वह आजायंगी।

अभी श्री त्यागीजी ने श्री कुम्भारामजी के बारे में बात कही है। उसमें हलालसिंहजी के बारे में भी कहा है। उसके बारे में मैंने बहुत कोशिश की कि वह फैसला किसी तरह से मुझे मिल जाय क्योंकि केवल कोरे-कोरे शब्द आ गये तो उन पर...

श्री वेदपाल त्यागी—वह मैं स्वयं उपस्थित कर सकता था, अगर आप मुझसे चाहते तो।

श्री जयनारायण व्यास—मैं यह प्रार्थना करूँगा कि वह बहुत अच्छी परम्परा डालेंगे, अगर २ दिन पहले ऐसे शब्द देंगे; ताकि मैं दूसरे पक्ष से भी पूछ लूँ। माननीय कुम्भारामजी बीमार हैं इसलिए वे खुद ही अपनी स्थिति को साफ नहीं कर सकते हैं। मेरे पास वे शब्द नहीं हैं जो श्री त्यागीजी ने कहे हैं। इसलिए इसके बारे में जब तक मेरे पास पूरा सबूत नहीं निकलता है तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।

अब फाइनेन्स के बारे में बातें हैं। यादवजी ने कर्ज ही कर्ज लेने की बात कही है। हम कर्ज ही तो ले रहे हैं, भीख तो नहीं माँग रहे हैं। हमें कुछ चीजें लेनी हैं तो कुछ चीजें जो हमने ली

[श्री जयनारायण व्यास]

हैं वे एफ. आई. एफ. एग्रीमेंट के मुताबिक हैं और कुछ गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। हमारे कई विषय केन्द्र में चले गये हैं ! रेलवे, नमक और दूसरी चीजें चली गई हैं, और उसके बदले में कुछ रियायतें और आर्थिक साधन लेने के हैं, इसलिए माँगे हैं और भारत सरकार ने बड़ी उदारता से दिये हैं। हम जो उधार ले रहे हैं वह रचनात्मक कामों के लिए ले रहे हैं; जो रचनात्मक काम आपके राजस्थान की तरक्की करेंगे। इनका निर्माण होगा तो साथ ही साथ वह इतना पैसे देंगे कि इस पैसे से न केवल हम कर्ज चुकायेंगे बल्कि अपने किसानों और मजदूरों का कर्ज भी चुका सकेंगे। भाखरा, चम्बल वगैरह तैयार होंगे तो यह कर्ज ले लेना कोई बुराई की बात नहीं है। उससे बिजली होगी, कारखाने होंगे, अनाज होगा, खेती होगी और बेकारी दूर होगी। तो यह कहना कि यह कर्ज मत लो, यह ठीक नहीं है।........

श्री गोपीलाल यादव—On a point of explanation, Sir. माननीय मित्र से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने यह बात नहीं कही है। मैं अपनी रिपोर्ट पढ़ रहा था। जो शब्द आपने इस्तेमाल किये हैं वे ठीक नहीं हैं। रिपोर्ट इतनी गलत है कि कहीं कुछ का कुछ लिखा है।

श्री चन्दनमल बैद—आपने कहा होगा, आपका ध्यान नहीं रहा होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मन्त्रीजी हाजिर नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री जयनारायण व्यास—श्री हरिकृष्णजी ने भी कहा था कि केन्द्र से ज्यादा रुपये लेना ही सरकार का काम बाकी रह गया है। यादवजी के कुछ शब्द थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप हाजिर होते तो आपको भ्रम नहीं होता।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने दूसरों की आँखों से देखा है। यह ज्वाइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है, यह उनके ध्यान में आना चाहिए। यह जो फाइनेन्स के बारे में लोगों में अविश्वास का वातावरण बन गया था उस अविश्वास के वातावरण को मिटाया गया है और आगे जाकर निर्माण की स्थिति में यह राजस्थान आया है। इसके लिए अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो उसके लिये यह कहना, मैं समझता हूँ, निर्दयता है। मुझे इतने ही शब्द कहने हैं। अन्त में आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ कि इस बार काफी बोलने का मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विरोधी पक्ष में जो बैठे हुए हैं उन्हें सन्तोष होगा और वह धन्यवाद के प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार करेंगे। (हर्ष ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—I put the motion to vote.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that the motion be passed.

(स्वीकृत)

The motion is passed with majority votes. (हर्ष-ध्वनि)

The house is adjourned to meet tomorrow at 8-30 A. M.

(सदन की कार्यवाही १२-३६ मध्यान्होत्तर ११ मार्च, १९५४, के प्रातः ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१० मार्च, १९५४।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्नोत्तर ८२ देखिये)

बनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं की सूची

नाम छात्रा	वर्ग	कक्षा
१ चम्पा बाई	यादव	३
२ शान्ति	यादव	३
३ कंचन	यादव	४
४ मोहन	यादव	४
५ खेमवती	यादव	४
६ केसरबाई	यादव	४
७ यमुना	यादव	४
८ सरस्वती	यादव	४
९ गीता	यादव	४
१० यमुना	यादव	४
११ गोपी	यादव	४
१२ शान्ति	यादव	४
१३ पुष्पा	यादव	४
१४ किरन	यादव	४
१५ लक्ष्मी	यादव	४
१६ पार्वती	यादव	५
१७ लक्ष्मी	यादव	५
१८ रामेश्वरी	यादव	५
१९ शान्ती	मेहतर	५
२० लक्ष्मी	यादव	५
२१ अरुणा	यादव	५
२२ मनोहर बाई	चमार	५
२३ सोहन	रैगर	६
२४ कस्तूरी बाई	रैगर	७
२५ कमला	भील	८

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्न तथा उत्तर जो प्रश्न समय में न लिये जा सकने के
कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

११० (६३/एफ. एम.) श्री चाँदमल मेहता एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ८७—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ में वाटर वर्क्स अभी तक नहीं बनने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि यहाँ के वाटर वर्क्स के लिए एक बोर्ड बन चुका था और इस काम के लिए ५ लाख रुपये भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने भी मन्जूर कर दिये थे ?

उत्तर

(क) साधारणतया ऐसे कार्य स्थानीय म्युनिसिपेलिटी द्वारा किए जाते हैं। अर्थाभाव के कारण सरकार की तरफ से इस प्रकार के कार्य को लेना कठिन है।

(ख) भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने ५ लाख रुपये किशनगढ़ पानी-व्यवस्था के लिये रखे थे, मगर यह रकम वृहत् राजस्थान बनने पर जनरल रेवेन्यू के शामिल हो गई।

प्रश्न

१११. (६४/एफ. एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम. एल.ए., डिविजन नम्बर ६४—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) कस्बा चित्तौड़ में नल लगाने का कार्य कब तक सम्पूर्ण हो जावेगा ?

(ख) क्या यह सच है कि यह कार्य गत चुनावों के बाद से बन्द पड़ा हुआ है जिसके कारण पहले का लगा हुआ सामान भी खराब हो गया है ?

उत्तर

(क) यदि आवश्यक द्रव्य मिल गया तो जून १९५५ तक कार्य समाप्त होने की आशा है।

(ख) पानी मिलने का पूर्व निश्चित स्रोत सफल न होने के कारण अन्य स्रोत की गवेषणा में कुछ समय अवश्य लगा है, किन्तु कार्य पूर्ण रूप से बन्द नहीं है। पहिले का सामान खराब नहीं हुआ है।

प्रश्न

११२ (२८/एम. एच. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४६—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) साल १६५३ में राजस्थान में मलेरिया क्षेत्र के लिए कितनी कुनैन दी गई और कितने स्पेशल डाक्टर लगाये गये ?

(ख) उनमें से बीकानेर डिवीज़न में कितने लगाये गये और बीकानेर डिवीज़न के नहरी इलाके में कितने ?

(ग) तहसील पदमपुर में कितनी कुनैन दी गई और कहाँ कहाँ, और नहीं दी गई, तो क्यों ?

उत्तर

(क) साल १६५३ राजस्थान में मलेरिया क्षेत्रों में निम्नलिखित औषधियाँ दी गई :—

कुनैन गोलियाँ	२८, ८५०
पॅल्यूड्रीन गोलियाँ	४५६, ४०२
मैपाक्रीन गोलियाँ	२४, ६८, १२०
कैमाक्वीन गोलियाँ	११, ०००
रेजोचीन गोलियाँ	२, ०५०
कुनैन सल्फ पाउडर	४२५ पौंड १२ आंस
कुनैन इन्जेक्शनस	४७५०

कन्ट्रोल ड्रग्स

एटाब्रीन गोलियाँ	८,५००
निवाक्वीन गोलियाँ	६,५००
सिनकोना पाउडर	११ पौंड

इन आंकड़ों में उदयपुर डिविजन में दी गई कुनैन आदि के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं। क्योंकि वे समयाभाव के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।

इस कार्य के लिये ११ स्पेशल डाक्टर लगाये गये।

(ख) बीकानेर डिविजन एवं उसके नहरी इलाके में कोई स्पेसल डाक्टर नहीं लगाये गये। किन्तु स्थायी डिस्पेन्सरियों के डाक्टरों को ही यह कार्य सौंप दिया गया था।

(ग) डी. एम. एण्ड एच. ओ गंगानगर ने पदमपुर डिस्पेन्सरी के लिए जो दवा भेजी उसके अतिरिक्त ए. डी. एम. एण्ड एच. एस., बीकानेर में पदमपुर डिस्पेन्सरी के लिए २ पौंड कुनैन एवं ५०० पैल्यूड्रीन की गोलियाँ और दे दी थीं।

प्रश्न

११३ (६५/एफ. एम.) श्री शम्भूसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला भीलवाड़ा की तहसील सहाड़ा, रायपुर में पंचवर्षीय योजना और लघुसिंचन कार्य के भीतर किस किस गाँव के तालाबों के कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकार होकर व्यय हुई ?

(ख) इन तहसीलों में तालाब कहाँ-कहाँ पर बने हुए हैं और कहाँ बिल्कुल नये बनने की योजना है ? कहाँ कार्य अब शुरू किया जायगा ? और कितना धन व्यय किया जावेगा ?

उत्तर

तहसील सहाड़ा—

(क) १. ग्राम गीडीया के पास गीडीया तालाब बनाने की योजना सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर, सिंचाई विभाग, उदयपुर, के पास स्वीकृती भेजी है। इस पर ६५,००० के लगभग व्यय होगा और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया लोन फार मिडियम वर्कस के अन्तर्गत व्यय होगा। कार्य मन्जूरी आने पर शुरू किया जावेगा।

२. नागड़ीया खेड़ा ग्राम के पास चन्द्रभागा नदी पर बांध बांधने की योजना विचाराधीन है।

(ख) इस तहसील में लगभग हरेक ग्राम में एक-एक तालाब मौजूद हैं। पोटला १, सरग्राम १ (तालाब की दुरस्ती व ऊँचाई बढ़ाना), मरक १ की ऊँचाई बढ़ाना व मरम्मत, गूढ़ा १, सहाड़ा २, लाखोला १, बगैरा १, आमली १, गीलोदिया १। फुलेरा, आम्बा वाला, गंगापुर, ऊन्डीया। कागनी २, कुशालसागर, मानसागर सालेरा १, ऊलेलाह १, खाती खेडा १, रुघनाथपुरा १, डेलाना १, निचला और पन्डरीया खरीया २, खेडा, काला, खेडा रुपारेल १, इत्यादि कुल तहसील में २६ तालाब हैं। इन सब पर किसी कार्य पर जैसे नारो की दुरस्ती व तालाब की दुरस्ती का काम जारी हैं या होने की योजना विचाराधीन है।

तहसील रायपुर—

तालाब कुरजीया का कार्य गवर्नमेन्ट भारत सरकार से लघु सिन्चन कार्य के लिये पहले कर्ज के अन्तर्गत जारी हैं। करीब १००००) रुपया व्यय हो चुका है और कार्य भी एक माह में सम्पूर्ण हो जावेगा।

नीचे दर्ज शुदा तालाबों के कार्य भारत सरकार से लघु सिन्चन कार्य के लिये दूसरे कर्ज के अन्तर्गत मंजूर हो चुके व टेन्डर वगैरह मांगे जा रहे हैं व कार्य भी अतिशीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

१. अर्जुनगढ़ तालाब	८,२००
२. थली तालाब	३३,०००
३. पीतलपुरा	४०,७००
४. केमुनिया	१२,००० । टेन्डर हो चुके हैं।

पंचवर्षीय योजना में देवरीया तालाब की स्कीम ३,८०,२२५) रु० की बनाई गई है।

इस तहसील में निम्नलिखित तालाब मौजूद हैं :—

दोबड़ा १, मरेड़ा १, केमुनिया १, जगपुरा १, सगरेव २, बडोल १, अर्जुनगढ़ १, सबलपुरा १, घूवाला १, गोरखिया १, रायपुर २, कुल १३ तालाब हैं।

प्रश्न

११४. (६६/एफ. एम.) श्री शम्भूसिंह एम. एल. ए. डिविजन नंबर १३६—क्या सिचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या भीलवाड़ा जिले की तहसील रायपुर के ग्राम देवरिया और तहसील सहाड़ा के ग्राम पोटलां में नये तालाब बनाने की कोई योजना विचाराधीन है अथवा स्वीकृति हुई है?

(ख) इन तालाबों पर अलग-अलग कितना खर्च होने का अनुमान है?

(ग) इन तालाबों पर किस मद से खर्चा होगा?

(घ) यह कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

भीलवाड़ा जिले की रामपुर तहसील के ग्राम देवरिया में नया तालाब बनाने की योजना विचाराधीन है। इसकी अनुमानित लागत ३,२४,०००) रु० है।

तहसील सहाड़ा के पोटला ग्राम के पास खारीया नाले पर रामोला तालाब बनाने की योजना विचाराधीन है।

ग्राम देवरिया का तालाब २,५०,००,०००) रु० की जो नई मद भारत सरकार ने मन्जूर की है उसी मद में बनाने की तजवीज है इसका कार्य लगभग दो माह में शुरू कर दिया जायगा। एवं पोटला के खारीया नाले को लघुसिंचित कार्य के मद के अन्तर्गत बनाने की योजना है।

प्रश्न

११५. (२६/एम. एच. एम.) श्री शम्भूसिंह एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३६—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या गंगापुर (जिला भीलवाड़ा) के अस्पताल के साथ रोगियों के लिए कोई वार्ड है? यदि नहीं तो रोगी कहां रखे जाते हैं?

(ख) क्या सरकार नये बजट में वार्ड बनाने के लिए उचित रकम रखेगी?

उत्तर

(क) गंगापुर डिस्पेन्सरी में अलग वार्ड तो नहीं है परन्तु वहाँ प्राथमिक मरीज़ों के लिये दो पलंगों की व्यवस्था है।

(ख) इस प्रश्न पर अन्य अस्पतालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा।

प्रश्न

११६. (६८/एफ. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ४६—क्या सिचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर जिला के नहरी क्षेत्र में सिंचाई की दरों में वृद्धि करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा गया था?

(ख) इससे पूर्व सिंचाई की दरों में वृद्धि कब हुई थी?

उत्तर

(क) गंगानगर ज़िले के नहरी क्षेत्र में सिचाई की दरों में वृद्धि करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया था:—

(१) उपज की क़ीमत और (२) आज कल सिंचाई के कामों की मरम्मत और चलाने का व्यय।

(ख) इससे पूर्व सिंचाई की दरों में वृद्धि नहीं हुई थी।

प्रश्न

११७. (३०/एम. एच. एम.) श्री शम्भूसिंह एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १३६—क्या चिकित्सा वह स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में खाद्य-पदार्थों में मिलावट रोकने का कोई प्रभावशाली कानून है या नहीं?

Page No.99

(ख) यदि नहीं तो सरकार ने ऐसा आवश्यक कानून अब तक क्यों नहीं बनाया और अब वह कब तक बन जायगा ?

उत्तर

(क) सम्पूर्ण राजस्थान के लिये साम्य नियम तो नहीं है फिर भी विभिन्न स्थानों में सम्मिलित भूतपूर्व राज्यों के क़ानून अब भी लागू हैं।

(ख) सम्पूर्ण राजस्थान के लिये एक क़ानून बनाने के लिये एक कद्र समिति ने यह कार्य हाथ में लिया था। इस दिशा में प्रगति इसलिये नहीं हो सकी कि भारत सरकार समस्त भारत के लिये खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का एक साम्य नियम बना रही है।

प्रश्न

११८. (६८/एफ. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६६—क्या सार्वजनिक मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितने स्कूल और कॉलिज हैं जिनकी इमारतें राजस्थान सरकार ने पिछले ४ साल में बनवाई हैं ?

(ख) जिन स्कूलों और कालिजों की इमारतें सरकार ने बनवाई हैं वे शहरों में कितने और गाँवों में कितने हैं ? उनमें से गंगानगर ज़िले के शहरों में कितने हैं और देहातों में कितने हैं ?

(ग) यदि शहरों के स्कूल व कॉलिजों की इमारतों पर अधिक व्यय हुआ है, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(क) राजस्थान निर्माण के बाद मुख्यतः ३७ स्कूल और कॉलेज बिल्डिंग बनवाई गई हैं या इनके परिवर्द्धन और परिवर्तन (A/A) पर खर्चा किया गया है।

(ख) सन् १९५१ में हुई जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में केवल ६ शहर माने गये हैं और इस विचार से १६ स्कूल या कोलेज बिल्डिंग शहरों में आते हैं और शेष कस्बों या गांवों में। गंगानगर जिले में कोई शहर नहीं आता इसलिए सब कार्य गांवों में ही हुए माने जाने चाहिए जिनकी रकम ८१००० रु० होती है।

(ग) इस प्रश्न का उत्तर शिक्षा विभाग से दिया जा सकता है क्योंकि यह कार्यालय शिक्षा विभाग की मांग के अनुसार काम करता है।

प्रश्न

११९. (३२/एम. एच. एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६४—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.100

(क) क्या उदयपुर डिविजन में ऐसे भी तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ डाक्टर की जगह कम्पाउन्डर ही काम कर रहे हैं ?

(ख) यदि नहीं तो क्या डूंगला, ज़िला चित्तौड़ गढ़, में डाक्टर का काम कम्पाउन्डर से लिया जा रहा है ?

(ग) क्या उदयपुर डिविजन में ऐसे भी स्थान हैं जो तहसील हैडक्वाटर नहीं होने पर भी वहाँ डाक्टर मौजूद हैं ?

(घ) क्या सरकार उक्त स्थान पर अब भी जल्दी से जल्दी डाक्टर भेजकर जनता के कष्ट को निवारण करेगी ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।
(ग) जी हाँ।
(घ) अवश्य।
(ङ) आशा है कि अप्रेल के अन्त तक नियुक्ति कर दी जायगी।